साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष : 13 अंक : 16 | प्रति सोमवार, इंदौर 26 नवंबर से 3 दिसंबर 2018 | पृष्ठ : 12 | मूल्य: 2 रुपए

अमेरिका और इंग्लैंड को औकात में रहना सीखो

दुनिया पर दादागिरी करने और थोपने का कोई हक नहीं

अमेरिका और इंग्लैंड दुनिया आप के बाप की जागीर नहीं

यदि चीन में ऊईगर अल्पसंख्यक मुसलमानों ने देश के बहुसंख्यक बौद्धिस्ट व अन्य जाति के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। वहां पर वह तांडव करते हैं दूसरे अन्य लोगों को परेशानियां खड़ी करते हैं आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं। तो चीन को हक है कि वह अपने देश में शांति की व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आवश्यक और जरूरी कदम उठाएं। बेशक उन्हें शांति से समझाया जाना चाहिए। परंतु यदि वह नहीं मान रहे हैं, बरसों से तो आवश्यक है, की कड़े कदम उठाए जाएं और अन्य बहुसंख्यक लोगों की शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी पूर्ण कार्य किए जाएं। इस पर अमेरिका और इंग्लैंड को अपने मानव अधिकारों का तांडव करके दूसरे देशों में उंगली करने का कोई हक नहीं है। क्या अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने देशों में इसी प्रकार के मानव अधिकारों का दुरूपयोग करके

दमनकारी नीतियां नहीं चलाई।

दूसरी तरफ अमेरिका में मेक्सिकन को बाहर करने के लिए उन्होंने दीवाल खड़ी कर दी और इंग्लैंड ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड को अपने देश का हिस्सा घोषित करने के लिए पिछले कई शताब्दियों से वहां के रहवासियों को परेशान नही कर रहा है।

पहले यह सूअर हरामखोर देश दुनिया पर दादागिरी दिखाने से पहले अपनी कॉलर साफ कर लें।

फिर अमेरिका और इंग्लेंड दुनिया पर मानव अधिकारों की आड़ में अपना डंडा घुमाने और दादागिरी करने से पहले बताएं क्या उनके देश में जो अपने आप को दुनिया का महान समझते हैं आज तक नस्लभेदी रंगभेदी नीतियों के अंतर्गत कितने लोगों की हर साल हत्या हो जाती है और वह कितना रोक पाते हैं। जब आपकी अपनी औकात नहीं कि अपने देश में रंगभेद और नस्लभेद की आड़ में कितनी एशियाई व अफ्रीकन काले लोगों की हत्या कर दी जाती है और गोरे लोगों का प्रशासन और कानून भी 90% काले लोगों का साथ नहीं देता। तब आप की औकात नहीं होती कि अपने गोरों के ऊपर पूरा शिकंजा कस कालों को न्याय दिलाया जा सके।

तो दूसरे देशों की अपनी व्यवस्थाओं में शांति स्थापित करने के लिए यदि वह देश कदम उठाते हैं तो आपको कोई हक नहीं कि उनको बदनाम करें, उंगली उठाये।

लाखों करोड़ का कर्ज लिया और खूब घी पिया, निवेश के नाम खूब विदेश यात्राएं की

भाजपा ने 13 साल में खूब लूटा और मचा दी तबाही

महाबेशर्म, घोर भ्रष्ट, जालसाज, आपराधिक, सत्ता के भुखेरे जन पार्टी के गिरोह ने स्वयं सिद्ध करते हुए बताया की जनता की भूल कमल का फूल वाले, खादी धारी डकैत शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 13 साल के शासन में हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन की कमाई केवल बिजली से ही की है। फिर परिवहन, आबकारी, भू अभिलेख पंजीयन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, संचार तकनीकी, खनन, गृह विभाग, नर्मदा घाटी, लोक निर्माण, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, गृह निर्माण मंडल आदि अधिकांश विभागों में पिछले 13 सालों में चारों तरफ भारी लूट का तांडव किया। सबसे ज्यादा पैसा लाखो करोड़ मीडिया पर अपने कुकर्मो को छुपाने के लिए खर्च किया गया। इन सब के उपरांत भी चुनाव के समय जनता से आशीर्वाद मांगने की यात्रा जन धन की खर्च बंद पर निकाली गई।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उमाशंकर गुप्ता- राजस्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्चना चिटनिस महिला एवं बाल विकास, यशोधरा राजे सिंधिया- खेल युवा कल्याण धार्मिक न्यास और धर्मस्व, पारस चंद जैन ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा, राजेंद्र शुक्ला- खनिज, वाणिज्य, उद्योग, रोजगार वा प्रवासी भारतीय, अंतर सिंह आर्य- पशुपालन मछुआ कल्याण व मत्स्य कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पर्यावरण, रामपाल सिंह- लोक निर्माण, माया सिंह- नगरीय विकास एवं आवास, भूपेंद्र सिंह ठाकुर गृह एवं परिवहन सिंह पवैया उच्च शिक्षा लोक सेवा प्रबंधन, राज्य मंत्रियों में दीपक जोशी तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास नर्मदा घाटी विकास सामान्य प्रशासन शरद जैन चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुरेंद्र पटवा संस्कृति पर्यटन व कृषि, हर्ष सिंह आयुष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, संजय सत्येंद्र पाठक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उच्च शिक्षा सामाजिक न्याय श्रीमती ललिता पाठक पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण, सारंग विश्वास सारंग सहकारिता पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सूर्य प्रकाश मीणा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण आदि सभी मंत्रियों ने हर विभाग में हजारों करोड़ आवंटन में 5 से लेकर 25% तक लेकर भ्रष्टाचार से लूटपाट का तांडव करने के साथ, सत्ता के विधायकों से लेकर सभी 16 निगमों,98 पालिका 264 परिषदों, के पार्षदों महापौरो से लेकर प्रदेश की लगभग 22624 पंचायतों के सभी सरपंच सचिवों, ने पिछले 15 सालों में कम से कम तीन से चार लाख करोड़ की लूट सरकारी धन से लेकर जनता से वसूले गए।

शेष पेज 6 पर

मोदी ने पूंजीपति आकाओं के लिए पिछले 4 सालों में चारों तरफ मचा दी घोर तबाही

नोटबंदी और जीएसटी के बाद चारों तरफ भारी बेरोजगारी, 50 लाख से ज्यादा लघु उद्योग, छोटी दुकानें, व अन्य कारोबार बंद हुए पूरे देश में, जिससे २० करोड़ से ज्यादा लोग चारों तरफ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ के सौदे केवल अपने ठेकेदार मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए। जिसमें स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों कालोनिया और पुराने बाजारों में पूरे देश में चारों तरफ भारी तोड़फोड़ की गई। बुलेट ट्रेन, चौगुनी कीमतों पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास के नाम पर सबसे ज्यादा फायदा भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उसकी कंपनियों ने उठाया। अपने पूंजीपति मित्रों का 20लाख करोड़ ऋण माफ करने नोट बंदी की गई, डिजिटल इंडिया के बहाने गरीब भारतीयों के 50करोड़ खाते खुलवा कर 4.50लाख करोड़ जनता का न्यूनतम बैलेंस के नाम पर हजमकर लिया गया। पांचवें बैंकों में लेनदेन के बाद हर लेनदेन पर रु175/- प्रति लेन-देन की जबरदस्त वसूली की जा कर जनता को प्रतिदिन रुपए दस हजार करोड़ से ज्यादा लूटा जा रहा है। शेष पेज 8 पर

देश की बैंकों, व्यापारियों, बीमा कंपनियों, उद्योगों को बर्बाद करने के बाद

अब मोदी कंगाल करेगा रिजर्व बैंक

ऊर्जित पटेल को लाने वाला कौन था। यही मोदी। जबकि वह भारतीय नागरिक नहीं है। अब अगर उसकी बात नहीं सुन रहा है। तो उसके विरुद्ध माहौल बनाया जा रहा है । नोट बंदी से जहां देश की 132 करोड़ जनता परेशान हुई वहीं सबसे ज्यादा बैंकरों और आरबीआई को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा यह है । फिर वह नई नौटंकी करने वाला है। वह मोदी के सामने सर झुका दे। और वह आरबीआई को भी लूट व लुटवा दे।

मोदी रिजर्व बैंक से जो रुपए 3 लाख 70 हज़ार करोड़ मांग रहा है। ये भारतीय रजिर्व बैंक का वो पैसा है जिससे वो देश की को अर्थ व्यवस्था स्थिर रखती है। और इस पर कुछ ब्याज भी कमाती है।अब भारतीय रजिर्व बैंक कानून के सेक्शन 7 का इस्तेमाल कर के मोदी जी इस धन को हथियाना चाहते है। सरकार का कहना है कि देश आर्थिक आपातकाल में है और सरकार को इस धन की जरूरत है जिससे वोअर्थ व्यवस्था को संभालेगी।अब सवाल ये है कि अगर देश का विकास हुआ है तो ये आपातकाल कहाँ से आई। और अगर वाकई में आपातकाल है तो देश को बताया क्यों नहीं जा रहा इस बारे में?

शेष पेज 8 पर

आपातकालीन शासकीय नियंत्रण, व्यक्तिगत संदेश माध्यमों और सारे सार्वजनिक प्रसार माध्यमों पर न्यायालीन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाना

सार्वजनिक प्रसार माध्यमों पर अघोषित आपातकाल

भारत का प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालते ही अपने विश्व भ्रमण, शासकीय धन के दुरुपयोग, पेट्रोल डीजल और ईंधन चौगुनी वसूली उच्च महंगाई दर, कुकर्मों प्रशासनिक नाकामियों, पूंजीपतियों के हित में लिए गए नोटबंदी जीएसटी ठोकने के निर्णय से, भारी बढ़ती बेरोजगारी, लघु उद्योग धंधों का का नष्ट होना, उत्पादन गिरना, गरीबों- अमीरों के बीच बढ़ती खाई, श्रम कानून को खत्म कर 20करोड मजदूरों का घोर शोषण, पूंजीपतियों को भारी लाभ पहुंचाना, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए मीडिया पर भारी मोटा हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन जन धन का खर्च कर मीडिया को खरीद कर सच्चाइयों को छुपाकर केवल अपनी प्रशंसा छपवाना, इसके विपरीत जब सच व्यक्तिगत संदेश माध्यमो से जिसमें WhatsApp, Facebook, ट्विटर इंस्टाग्राम के चारों तरफ करोड़ों लोगों के बीच फैलने लगा, और इन सभी माध्यमों पर इन कंपनियों के संचालकों को हजारों करोड़ खर्च देकर सारी जानकारियां सरकार लेती रही और अपनी धज्जियां उड़ते देख संकुचित बुद्धि का छिछोरा प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार की चारों तरफ थू -थू होती देखकर बौखला गया। शेष पेज 5 पर

भारत में पेट्रोल और डॉलर की कीमतें बढ़ने के पीछे मात्र मोदी का अंबानी प्रेम

आखिर 2019 के चुनावी खर्च अंबानी ही देगा इसलिए जनता से लूट जरूरी

पेट्रोल और डॉलर की कीमत बढ़ने के पीछे अंबानी द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 15-20% मोटे कमीशन के साथ क्रूड की खरीद की जाती है। बाद में सरकार की तेल कंपनियों को दिया जाता है। जिसे बाद में वह रिफाइन कर अपने लाभ के साथ केंद्र सरकार की 32% ड्यूटी जोडकर राज्यों को देती है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में $70 का क्रूड होने पर भी हमारे यहां रु90 -95 का जो पैट्रोल बिक रहा है उसके ऊपर जानबूझकर भेड़िया झुंड पार्टी के मोदी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज व अन्य सभी गिरोह के मंत्री एकदम मुंह बंद करके इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सबको मोटा कमीशन लाखों करोड़ में चुनाव के लिए अंबानी की व्यवस्था की थी । और भविष्य में भी करेगा। इसलिए जनता को लूटवाकर राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से लेकर पैट्रोलियम, वित्त मंत्री आदि तक सब कुछ जाने के बावजूद भी उल्टी सीधी दलीलें देकर चुप हो जाते हैं। जबकि इन्हीं भेड़ियों का झुंड सन 2004 से लेकर 2013 तक रु2 बढ़ने पर भी झान्ज मजीरे लेकर पूरे देश में हंगामा खड़ा किया करते थे। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रो क्रूड की कीमत $120 -30 तक पहुंच चुकी थी। तब कांग्रेस की सरकार रु82/- पेट्रोल बेंच रही थी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रो क्रूड की कीमत $70-75 चल रही है। जिसे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस पैट्रोलियम 85 से $90 में खरीद दिखाकर सरकार की तेल कंपनियों को दिया जाता है। यही कारण है कि सूचना का अधिकार में अधिकांश जानकारी दैने मे हर केंद्रीय मंत्रालय को भारी पसीना आता है और महीनों तक जानकारी देने की बात तो दूर प्रधानमंत्री कार्यालय तक धारा 4 के अंतर्गत जानकारी लोड करने की अपेक्षा पत्र को यहां से वहां भेजा करता है। यहां तक की भारतीय रेलवे और विमानन कंपनियों को डीजल पेट्रोल की आपूर्ति का ठेका सरकारी

शेष पेज 6 पर

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

संपादकीय

लोकतांत्रिक नहीं लूटतांत्रिक व्यवस्था राजनैतिक दल नहीं, गुंडों का गिरोह

पूरी दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक राष्ट्रों में चुने हुए नेता यथार्थ में पूर्व के पुराने घाघ, घोर, जालसाज और भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं। जिन्होंने छल,बल से अपने जैसे अनेकों घाघों को जोड़कर दल खड़े किए होते हैं।यथार्थ मे ये सफेदपोश गुंडों का गिरोह होता है।

भारत के संदर्भ में यह तथ्य बहुत सटीक और सच है। भारत में वर्तमान में जितने भी राजनीतिक दल हैं जिसमें मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के बाद आप, सपा, बसपा, जदयू, व अन्य दल जो संख्या में सात राष्ट्रीय दल, 22 राज्यों के दल, व 2024 दल चुनाव आयोग में पंजीकृत है। पर वे ही दल सफलतापूर्वक भारत में सत्ता को हाक पा रहे हैं। जो की अत्यधिक घाघ, झूठे, मक्कार, भ्रष्ट, अय्याश और आपराधिक प्रवृति के होते हैं। जिनके ऊपर अनेकों गंभीर जालसाजी हत्या मारपीट धोखाधड़ी बलात्कार आदि के प्रकरण दर्ज होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर नीचे के सत्र एवं जिला न्यायालयों में अनेकों प्रकरण विचाराधीन होते हैं। इन सब पर अनेकों बार अनेकों मुकदमों की सुनवाई के अंत में सत्र से सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों तीखे निर्णय और टिप्पणियां की हैं हर बार समाज और सत्ता में ऐसे ही अपराधियों को बाहर करने उन्हें चुनाव ना लड़ने आदि के लिए कहा गया परंतु जब सभी राजनीतिक गिरोहों के एकत्रित होने का आधार ही आपराधिकता, फिर जहां चुनावों में धन बल और दल का उपयोग कर जनता को धन बल से खरीद कर चुनाव लड़ा जाता वह जीता जाता हो, तो उन्हें राजनैतिक दल नहीं, गिरोह की परिभाषा में रखा जाना चाहिए। उसके राजनीतिज्ञ अर्थात छल, बल, दल में निपुण सफेदपोश आपराधिक नेता जो सफेद खादीधारी धरती के मानव गिध्द, जनहितों का शोषण, अपनों का पोषण करने वाले गुंडों के दल-दल का गिरोह कहिये। सत्ताधीश ऐसे राजनीतिक गुंडे न्यायालयों, सरकार सबको अपनी गुंडागर्दी से हांकते और चलाते हैं।

दूसरी ओर जो उचित जो उच्च शिक्षित व्यक्ति नेतागिरी में उतरे उन्होंने उन्होंने अपने पीछे का अपने पैशे व ज्ञान का सदुपयोग राष्ट्र व जनहित की अपेक्षा अपनी मोटी कमाई और अपनी जमीन मजबूत करने के लिए किया बे अपनी मोटी कमाई के लिए भी अपना जमीर गिरवी कर अपना पैशा त्याग कर पूंजीपतियों के हित में काम करने लगे। गहन अध्ययन के बाद, यह निष्कर्ष निकला कि देश में 1965 के बाद कोई भी कानून, जनहित के लिए नहीं केवल पूंजी पतियों के हित में जनता को लूटने, देश की संपतियों का उनके हित में उपयोग करने के लिए बनाए गए।जिसने कानून की परिभाषा जो कि समाज को संयमित व सुरक्षित तरीके से चलाने, उनकी समृद्धि उनके विकास के लिए बनाए जाते हैं। इन घोर धूर्तो और मक्कारो के गरिोह ने बदल कर इसकी अपेक्षा अब "कानून धूर्तो के बनाये शब्दों के मायाजाल बन गए, जो अपनों के पोषण और निरीहों के शोषण के काम आने लगे। उस श्रेणी में कीटनाशक अधिनियम 1966, बीज अधिनियम 1968, एमआरटीपी 1970, आयोडीन नमक कानून 1971, से लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 आदि को इन्हीं धूर्तो और गुंडों जो कि सफेद खादी धारी सत्ताधीश नेता थे जिन्हें जनता ने हीं उनकी मीठी आकर्षक लोक लुभावनी भाषा सुनकर अपने मताधिकार से चुनकर सत्ता चलाने और अपने कल्याण सुरक्षा व विकास के लिए सत्ता में भेजा था। इसके विपरीत लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में यही अपराधी गिरोह जनहित के नाम पर जन हितों की आड़ में अपने, अपने सहयोगियों, दानदाताओं ई कल्याण के लिए कार्य करने में जुट जाते हैं यथार्थ में लोकतंत्र अब लूटतंत्र बन चुका है। सत्ता में आते ही जनता उनके लिए कीड़े मकोड़े, सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनके लिए गाय, बैल, भैंस, बकरी, उद्योगपति और पूंजीपति दुधारू पाढ़े और सांड होते हैं। उनके लिये।जनि का भरपूर उपयोग वे सत्ता में रहते हुए कर लेना चाहते हैं और करते भी हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में पुरानी कांग्रेस को कोसते हुए अनेकों बार कहा कि उन्होंने 65 साल देश को लूटा है। स्पष्ट था कि अब हमें मौका दो। हम अगले 5 साल में उससे दुगना लूट कर दिखा देंगे। और मोदी ने यह करके दिखलाया भी उसने पिछले 4 सालों में 90 से ज्यादा विदेश यात्राएं अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जिससे उसने चुनाव के लिए हजारों करोड़ रुपए चंदा लिया था व उनके लिए हर विदेश यात्रा में सरकारी खर्च पर उनका व्यवसायिक प्रतिनिधि बनकर दया और देश के प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों से उनके लाभ के लिए बड़े बड़े व्यवसायिक लाभ के सौदे करके आया। यहां तक की उन्हें वह अपनी शासकीय यात्रा में जनधन से ही उन्हें अपने साथ विदेशों तक मैं साथ लेकर भी गया। जब ज्यादा बदनामी होने लगी तो इस महा मक्कार, ऐतिहासिक आपराधिक प्रवृत्ति के भ्रष्ट इस घोर जालसाज झूठे नेता ने सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से लेकर जनता के हाथ में अपने कुकर्मों को जनता के मस्तिष्क से और प्रसार माध्यमों साफ करने प्रसार माध्यमों के माध्यम से अपनी प्रशंसा और राष्ट्र हति के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा सिद्ध करने की कोशिश की। पर यह नौटंकी भी ज्यादा दिन नहीं चली। जनता को यह भी समझ में आने लगा किस की आड़ में अपने पूंजीपति मित्रों टाटा, अंबानी, अदानी, हिंदूजा आदि से जनता से चौगुनी कीमत बेचे गए पेट्रोल डीजल से वसूले गए जन धन के लाखों करोड़ के कचरा ढोने के वाहन, रसायन, व सफाई के ठेके उन्हीं को दिए गए। और बदले में मोटा कमीशन सरपंचों सचिवो से लेकर पार्षदों, महापौर, अधिकारियों, कर्मचारियों, आयुक्तों सचिवों प्रधान सचिवों मंत्रियों मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री गृहमंत्री तक सबको बांट कर मोटी कमाई करवाई गई अर्थात सफाई के नाम पर भी जनता की जेब की सफाई कर पूरे गिरोह का लूट से फायदा करवाया गया।

बेशक यह सच्चाई भारत के दृश्य श्रव्य व मुद्रित माध्यमों ने जनता को कभी भी इसीलिए नहीं बताई क्योंकि इस लूट में उनको भी अपना मुंह बंद रखने और सच्चाई ना दिखाने, छापने के लिए हर दिन दृश्य श्रव्य समाचार श्रृखलाओ को 30 मिनट से लेकर 120 मिनट के, व दैनिक मुद्रित समाचार पत्रों को को4 से 6 पेज के विज्ञापन जन धन के हजारों करोड़ खर्च कर बांटे गए गहन अध्ययन और मनन् करने के उपरांत वर्तमान में लोकतंत्र की इससे श्रेष्ठ परिभाषा उपलब्ध नहीं होगी धरती पर कम से कम भारत के संदर्भ में।

विद्युत कंपनियों की डकैती चारों तरफ हजारों करोड़ की

प्रदेश में 30 हजार मेवा उत्पादन फिर भी प्रदेश में अंधेरा

प्रदेश में हजारों करोड़ की महंगी विद्युत खरीदकर, दूसरे राज्यों को आधी कीमत में आपूर्ति की जाती है। जबकि सस्ती बिजली प्रदेश के घरेलू, कृषि, व्यवसायिक और औद्योगिक क्षेत्र में 5 से 10 गुना महंगी बेची जाती है। पहले 12 साल खूब गरीबों की झोपड़ियों को लाख लाख रुपए महीने का बिल देकर लूटा गया। चुनावी साल में 3 महीने पहले गरीबी रेखा से नीचे व मजदूरों को 200 महीने के बिल देकर पुराने बिल माफ कर दिए गए। ताकि गरीब लोगों के आसानी से भ्रमित करके वोट लिया जा सके।

मध्यप्रदेश में शिवराज के आने के बाद पुरानी जल व ताप बिजली की परियोजनाएं पूरी हो जाने से उत्पादन लगभग 18हजार मेगावाट हो गया। जबकि प्रदेश में कुल मांग अधिकतम साढे11हजार मेगावॉट की थी। साथ ही फिर निजी कंपनियों से भी जिसमें सौर, वायु, के साथ ताप परियोजनाओं से भी, रिलायंस, टाटा अन्य कंपनियों से 5.50 से 6.50 प्रति यूनिट बिजली खरीदने के अनेकों समझौते किए गए। स्वाभाविक था, कि 50 पैसे से 1 लागत की प्रति यूनिट बिजली को खरीदने में 50 से 70 परसेंट तक कमिशन था। और यह लगभग 18हजार मेगावाट से ज्यादा थी यह महंगी बिजली मोटे कमीशन पर दूसरे राज्यों में बेची जाने लगी। इसमें भी रु हजारों करोड़ हर दिन का कमीशन था। जिसकी मोटी कमाई बिजली कंपनियों के प्रबंध संचालकों जो की मुख्यमंत्री के खास भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी हैं, के साथ, लगातार प्रतिदिन की जा रही है। चुनाव की इस नौटंकी से पूर्व पिछले 12 सालों में इन विद्युत कंपनियों ने प्रदेश की जनता के साथ चारों तरफ दोगुनी से 10 गुनी तक के बिल देकर ना केवल जनता को भारी लूटा वरन हजारों को हर साल आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। हजारों गरीबों को तो 12 सालों में बलि देखकर ही हृदयाघात हो गया और कईयों की उस में मृत्यु हो गई। परंतु इन बिजली कंपनी के अधिकारियों का इस लूट के बाद में भी दिल नहीं पसीजा न हीं उस समय इस जगत मामा को जनता की याद आई। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीटर के नाम पर दस से 20 गुना तक के ऐसे तेज मीटर भी लगाई जो बिजली बंद होने के बाद में भी चलते रहते हैं दूसरी तरफ प्रदेश की बची हुई बिजली दिल्ली में ढाई रुपए की मिलती है। परंतु प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 4.5 से 9/- तक व्यवसायिक उपयोग के लिए वहीं बिजली 9.50 रुपए से 18 यूनिट तक मिल रही है। यह लूट का तांडव से 12 साल से लगातार जारी है। इसकी कोई सुनवाई कहीं पर नहीं होती। और इमानदार उपभोक्ता हर तरह से इन बिजली कंपनी द्वारा लूटा जा रहा है। अभी भी जब गरीबों और मजदूरों के नाम से रु200/- प्रति माह की जुलाई में घोषणा की गई। तब भी इसका फायदा केवल राजनीति से जुड़े उन गरीबों को ही मिल सका। जो कि नेताओं के खास है। जबकि वास्तविकता में बाहर से आने वाले मजदूरों गरीबों जो दूसरी जगह किराए के मकानों में रहकर मेहनत मजदूरी कर जिंदगी गुजार रहे हैं उसको इसका फायदा नहीं मिल सका। दूसरी तरफ इस घोषणा के तत्काल बाद आम ईमानदार उपभोक्ता को दोगुने से 4 गुना तक की बलि देना शुरू कर दिया । जब उसकी शिकायत की गई। तब कोई बात सुनने वाला नहीं था। कंपनियों के वितरण केंद्रों पर बैठे, बरसों से कुंडली मारे बैठे घोर हरामखोर जालसाज मीटर रीडर जो अपने आप में कंपनी का एमडी होता है। यदि उसको आप हर महीने 300-400/- देते रहते हैं। तू भाई आपको सारी कारगुजारी करके आपका मीटर सेट कर देता है और उस पर सील भी ठोक देता है। परंतु ऐसा ना करने पर और भारी भरकम बिल आने पर यदि आप उस वितरण केंद्र के हरामखोर उपयंत्री से लेकर सहायक यंत्री को बिल कम करने की शिकायत देते हैं। तू किसी भी हाल में उस कम नहीं करता ज्यादा करने पर उस बिल के ऊपर किस्त बना देता है ।

परंतु बिल बन जाने के बाद मैं वसूली अवश्य करते हैं। चाहे आपने बिजली का उपयोग किया हो या ना किया हो। बिजली कंपनियों की इन इन बदतमीज और लूट खसोट के बारे में पूरे प्रदेश और देश के अखबारों में पिछले 12 सालों से लगातार समाचार छपने के उपरांत भी इन हरामखोर भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों अपनी मोटी वसूली के लिए इस लूट को बंद नहीं किया।

दूसरी तरफ कंपनी के प्रबंध संचालकों ने जो कि कोई इंजीनियर तो नहीं थे उनका एकमात्र उद्देश्य लूटना था। विद्युत मंडल के द्वारा बनाई गई सारी व्यवस्थाओं को चौपट करते हुए अपनी लूट के लिए सभी कामों को स्तर हीन ठेके पर करवाना शुरू कर दिया यहां तक की ठेकेदारों द्वारा स्तर हीनता की हद ए लोंग ते हुए मजदूरों से चलती बिजी लाइनों पर काम करवा कर सैकड़ों मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उन ग्रामीण अनपढ़ मजदूरों को बिजली से संबंधित कोई भी काम के रखरखाव का प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था। इसके विपरीत इन बजिली कंपनी से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों ने अपने बेटे बेटियों के नाम से ही ही रखरखाव के ठेके लेना शुरू कर दिए जिस में न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी पर मजदूरों को भर्ती कर लिया गया। जिन्हें प्लायर पकड़ने व उपयोग की विधि तक मालूम ना होने के साथ उन्हें ग्लोब्ज, मास्क, गम बूट आदि के सुरक्षा उपकरण तक नहीं दिए गए और उसके नाम पर ठेकेदारों ने अपनी मोटी कमाई करते हुए गरीब मजदूरों को महीने में रखकर बिजली कंपनियों से प्रति मजदूर 12.5 हजार तक प्रशिक्षित व कुशल श्रमिक के नाम पर वसूली की जाती है। इसके साथ ही हजारों करोड़ रुपए के ठेके पूरे पश्चिमी पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के पुरानी मजबूत खंभों को बदलने के लिए बड़ी कंपनी को मोटे कमीशन पर दे दिए गए और उन कंपनियों ने स्तर हीन कम वजन के काम चलाउ कमजोर खंबे पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में खड़े कर दिए गए जो कि लगाते लगाते ही मुडने लगे थे। इसके साथ ही जो पुराने खंभों व तारों का लाखों टन लोहा व व एलुमिनियम बेचकर हजम कर लिया गया। जिसका कोई कहीं कोई हिसाब नहीं है। यही हाल पुरानी ट्रांसफार्मर उनके रखरखाव और नये ट्रांसफार्मरों की खरीद में भी हुआ। जिससे पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के साथ पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था चरमरा चुकी है यही कारण है। हर दिन बड़े शहरों से लेकर 25000गांवों में भी बिजली आती-जाती रहती है आप जब भी शिकायत की जाती है । तब वहां बैठे ठेके के व नियमित्त हरामखोरों की फौज एक ही बहाना बनाती है की मेंटिनेस चल रहा है जबकि मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत मंडल मार्च, अप्रैल, मई, 3 माह में हीं पूरे अगले 9 महीने का इस तरीके से करता था की बरसात में भी कभी बिजली नहीं जाया करती थी। परंतु जब से मंडल को भंग करके इन कंपनियों में भारतीय प्रताड़ना सेवा के सूकरों की फौज ने प्रभार संभाला है सबसे इनको एक ही चीज दिखती है और वह है येन केन प्रकरेण हर महीने हजारों करोड़ की कमाई। इतनी सारी हजारों करोड़ लूट होने के उपरांत भी, हर साल हर बिजली कंपनी अपनी बैलेंस शीट में घाटा दिखाकर अरबो की हानि की बात करती है और विद्युत नियामक आयोग मैं बैठे घर भूखे रे मकानों की फौज को मोटा धन देकर अपनी बात मनवा कर कीमत बढ़वा ली जाती है।

इसके साथ ही कृषि के लिए बिजली के संबंध में भी बिजली कंपनी दोहरी नीति खेलती हैं एक तरफ मामा बोलता है कि हम किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। जबकि वही बिजली रात में मात्र दो-तीन घंटे के लिए उच्च दांव पर कृषि पंपों चलाने के लिए दी जाती है। वह भी हर दिन नहीं। अर्थात चारों तरफ बिजली कंपनियों की भरपूर लूट के बाद भी प्रदेश के उपभोक्ता, किसान सभी अंधेरे और लूट से हैं, हैरान-परेशान।

कर्ज़ लो, घी पियो, मंत्री से उपयंत्री तक डकैतों का अड्डा है, जल संसाधन

प्रदेश में सिंचाई कार्यदक्षता सुधारने हेतु 375 मिलियन डॉलर कर्ज

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच हुये हस्ताक्षर

संजय सरोवर सिंचाई परियोजना को एक बेहतर डिजायन वाली परियोजना में विकसित करने के लिये लिये एक व्यापक आधुनिकीकरण संभावना अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगी।

नई दिल्ली। गोंडवाना समय। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच मध्य प्रदेश में सिंचाई की कार्यदक्षता सुधारने के लिये 375 मिलियन डॉलर के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं ताकि सिंचाई के नेटवर्क का विस्तार कर और कार्यकुशलता बढ़ाकर कृषि आय को दोगुना किया जा सके। मध्य प्रदेश सिंचाई कार्यदक्षता सुधार परियोजना 125,000 हेक्टेयर भूमि के लिये नये, बेहद कार्यकुशल और जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित रहने वाले सिंचाई नेटवर्क का विस्तार कर और 400 गावों में जल के प्रयोग के तरीके को सुधार कर मध्य प्रदेश के 8 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचायेगी।

श्री सुनील कुमार खरे, संयुक्त सचिव (बैंक कोष एवं एडीबी), आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार की तरफ से और श्री सब्यसाची मित्रा, राष्ट्रीय उपनिदेशक, इंडिया रेजीडेंट मिशन, एडीबी ने एशियाई विकास बैंक की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर किये। मध्य प्रदेश की तरफ से परियोजना निदेशक श्री ए. के. उपमन्यु ने एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर किये। श्री खरे ने कहा, यह परियोजना सिंचाई की कार्यदक्षता और जल की उत्पादकता को अधिकतम संभव सीमा तक बेहतर बनाकर मध्य प्रदेश सरकार के सिंचाई के विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रम की मदद करेगी। श्री मित्रा ने कहा, एडीबी से मिलने वाली राशि का प्रयोग सिंचाई की कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिये एक विशालकाय दाब पर आधारित और स्वाचलित सिंचाई प्रणाली के विकास के लिये किया जायेगा। यह परियोजना डिजायन-बिल्ड-आपरेट आधार पर संस्थागत नवाचार को प्रोत्साहित करेगी। यह परियोजना दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। इनमें से पहले-कुंडलिया सिंचाई परियोजना में यह 125,000 हेक्टेयर भूमि के लिये नयी एवं अत्यधिक कार्यकुशल और जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित रहने वाली सिंचाई प्रणाली का विकास करेगी। इसमें दो बड़े पंपिंग स्टेशनों का निर्माण शामिल है जो कि जलापूर्ति कक्षों में पानी की आपूर्ति करेंगे जहां से भूमिगत पाइपों के नेटवर्क के जरिये जल की आपूर्ति खेतों में की जायेगी। यह परियोजना किसानों को नकदी फसलों की सिंचाई के लिये सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने में भी मदद करेगी।

दूसरी बड़ी सिंचाई प्रणाली - मौजूदा संजय सरोवर सिंचाई परियोजना को एक बेहतर डिजायन वाली परियोजना में विकसित करने के लिये लिये एक व्यापक आधुनिकीकरण संभावना अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगी। एशियाई विकास बैंक एक समृद्ध, समावेशी, टिकाऊ और स्थायी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के विकास के साथ-साथ घोर निर्धनता के उन्मूलन के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिये प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित इस संस्था का स्वामित्व 67 सदस्यों के पास है जिसमें से 48 इस क्षेत्र से ही हैं। 2017 में एशियाई विकास बैंक का सकल कामकाज 32.2 अरब डॉलर रहा था जिसमें से साझेदारी के जरिये उपलब्ध करायी गयी 11.9 अरब डॉलर की धनराशि भी शामिल है।

इसके पूर्व 1600 करोड़ का लोंन सन 2008 में वर्ल्ड बैंक पुरानी नहरो, बांधों को पुनर्जीवन देने के लिए लिया गया था। जिसका 10% काम ढंग से नहीं हुआ और वह सारा पैसा हजम कर लिया गया आप सरकार को जन धन से वसूले टैक्स से उसका चुकारा करना पड़ा।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

मध्य प्रदेश प्रदूषण फैलाओ मंडल, जब से मिश्रा सचिव तब से पूरे प्रदेश में लूट का तांडव

प्रदूषण नियमों के अंतर्गत चल रहा केवल वसूली का खेल

सूचना के अधिकार में ना जानकारियां दी जाती है और ना ही 13 वर्ष बाद भी प्रदूषण मंडल की साइट पर प्रदर्शित की जा रही है। तो मात्र मोटी कमाई करने के लिए

भोपाल के प्रदूषण फैलाओ मंडल के मुख्यालय में जब से सदस्य सचिव के रूप में मोटा पैसा खर्च कर अच्युतानंद मिश्रॉ ने पद संभाला। तबसे अधिकांश प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों ने मोटी वसूली देकर कानूनो को अंगूठा दिखाते हुए अपनी फैक्टरी के नाम पते और किन प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों और तत्वों का उपयोग किया जा रहा है। क्या संभावित खतरे हो सकते हैं? किसी भी आपात स्थिति में कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार होगा, साथ ही उपयोग किए जाने वाले तत्वो से भड़की आग वायु प्रदूषण आदि में किस तरह से उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। जो जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आवश्यक रूप से लगाए जाने वाली सूचना पटल तक हटा दिए गए। ताकि अंदर क्या और कैसा काम किया जा रहा है? उस के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? उत्पन्न होने वाला जल एवं वायु प्रदूषण के बारे में आमजन को आप कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है? यूनियन कार्बाइड की तरह हर जगह जहां बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है। दुर्घटनाओं को नहीं रोका जा सकेगा। इंदौर नगर के बीच में ही पोलो ग्राउंड, लक्ष्मी नगर, देवास रोड, धार रोड, मंगलिया, महू रोड, नेमावर रोड, उद्योग नगर और सांवेर रोड पर चलने वाली २० से ज्यादा बड़ी दवा, 2 शराब, 300 दाल, 70 रसायन, 20 बेट्री , फैक्ट्रियां जिसमें एम पी बियर, इप्का, साइनो, प्लेथिको, आदि सैकड़ों फैक्ट्री है। 400 से ज्यादा नर्सिंग होम, 200 से ज्यादा बड़े गैरेज, बहुमंजिला इमारतें जो नियमित रूप से भारी जल एवं वायु प्रदूषण फैला रही हैं। जो सभी प्रदूषण मंडल के अंतर्गत आ रहे यही हाल पीथमपुर में लूपिन, एसार, जैसी हजारों फैक्ट्री के है।

देवास के उद्योग क्षेत्र में, 400 से ज्यादा, शाजापुर के मक्सी में, खरगोन के निमरानी में, ग्वालियर के उद्योग क्षेत्र, बिरलाग्राम, गोले का मंदिर, झांसी रोड भिंड के मालनपुर, भोपाल के मंडीदीप, गोविंदपुरा, उज्जैन के देवास रोड, शाजापुर रोड, जबलपुर के आधार ताल, औद्योगिक क्षेत्र, सभी सैन्य फैक्ट्रीयों, इटारसी की सैन्य फैक्ट्रियों कों, इस प्रकार मध्य प्रदेश के 51 जिलों के जो कि 150 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में 40000 से ज्यादा उद्योगों में लगे हुए बोर्ड हटा दिये गए और उनसे मोटी वसूली पंजीयन के बाद अनापत्ति लाइसेंस के पुनर्नवीनीकरण में अरबों रुपए प्रति वर्ष की वसूली की जाती है। वर्तमान में हर कॉलोनाइजर, खदान माफिया, नर्सिंग होम व चिकित्सालय, ईंट भट्टा, को भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना और लाइसेंस लेना जरूरी है उसके साथ ही उसका हर दो-तीन वर्ष में पुनर्नवीनीकरण करवाना भी आवश्यक होता है। इसकी भी भारी मोटी रकम वसूल की जाती है। इसके बाद सारी फैक्ट्रियां खुलकर जल एवं वायु प्रदूषण फैलाते हुए आराम से काम कर रही हैं। बेशक दिखावे के लिए हर क्षेत्रीय कार्यालय बड़ी कंपनियों पर जिसमें बीना, गुना की रिफाइनरी, सिंगरौली के रलिांयस के पावर नरसिंहपुर की शक्कर फैक्ट्रियों, सतना की की खदानों, तहसील स्तर के नगरपालिकाओं आदि पर जिन से मनचाही वसूली ना मिलने के कारण प्रकरण स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायालय में मैं चल रहे हैं। बेशक पर्यावरण सुधार के नाम पर वर्तमान में प्रदूषण फैलाव मंडल मैं 5 आंचलिक कार्यालय और 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसमें इंदौर अंचल पांच क्षेत्रीय कार्यालय जिंन में इंदौर जिले के साथ खंडवा खरगोन बुरहानपुर वही पीथमपुर में दो एक पीथमपुर और दूसरा विशेष आर्थिक क्षेत्र पीथमपुर है।

धार क्षेत्र में धार झाबुआ बड़वानी अलीराजपुर यहां पर मेघनगर का उद्योग क्षेत्र कुछ विशेष खनिज की खदानें हैं। वैसे भोपाल स्तर पर जो तकनीकी शाखा है उसने मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के अंतर्गत दो मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री तीन कार्यपालन यंत्री कार्यरत है। विभाग में संचालित प्रयोगशालाओं के लिए रसायन, उपकरण, वायु एवं जल प्रदूषण के सतत निरीक्षण के लिए बड़े डिस्प्ले बोर्ड आद की खरीदी में, हर महानगर और नगरों में अनेकों स्थानों पर सतत वायु के विश्लेषण के लिए पूरे प्रदेश में जनधन से अरबों रुपए की मशीनें 25 से 40 के कमीशन पर खरीदकर लगा कर भूल ही गया। अध्यक्ष के बाद सीधा नियंत्रण सदस्य सचिव मिश्रा के पास ही है और यह पुराना भ्रष्ट इंदौर में भी अरबों रुपए की वसूली कर लगभग 15 से ज्यादा वर्षों तक जमा रहा। और करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री शिवराज, मुख्य सचिव के साथ मंत्री व प्रधान सचिव आवास एवं पर्यावरण पर खर्च कर सदस्य सचिव बन गया और अब खुले में वसूली का खेल चारों तरफ से चल रहा है। इसके आते ही ईमानदार अधिकारियों ने जिसमें विवेक द्विवेदी आदि थे देश छोड कर विदेश में नौकरी कर रहे हैं। इस की भ्रष्टाचार और अय्याशी के किस्से इंदौर में आम होने के साथ भोपाल में भी सदस्य सचिव बनने के बाद दबी छुपी तरह चलते रहते हैं।

फिर खदानों के संबंध में जिनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदूषण मंडल द्वारा किए जाते हैं। हजारों में से खुदाई किए जाने के बाद हर खदान को पुनः मिट्टी से भरना उस पर पौधारोपण करना कानूनन आवश्यक होता है। परंतु अधिकांश खदान भू माफियाओं खनिज माफियाओं जो कि सत्ताधीश अधिकारियों नेताओं की स्वयं की होने के साथ उनके भाई भतीजो और रिश्तेदारों के नाम की होती है। जिसमें जिला उप व जिलाधीश, खनिज अधिकारी, वहां बैठे निरीक्षको को जिन को हर महीने लाखों से करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर और सत्ता के दम पर चमका धमका कर अवैध उत्खनन सैकड़ों करोड़ रुपए का कर रही है। जिसमें नदियों के किनारे और नदियों में से रेती निकालना जिस के सबसे बड़े रेत माफिया प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी रिश्तेदारों की खुली डकैती चल रही है। होशंगाबाद से लेकर बुधनी के किनारों तक, ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर की चंबल में, प्रदेश के 51 जिलों में अधिकांश जिलों के पहाड़ों और पहाड़ियों को साफ कर दिया गया।

अधिकांश नेताओं की स्वयं की पत्थर गिट्टी आदि से लेकर अभ्रक, मैग्नीज लौह अयस्क बालाघाट में ताम्र अयस्क, कटनी सतना मैं चुने की खदानें अधिकांश खदान जो कि उनके रिश्तेदारों के नाम से, वाह बड़े अवैध कारपोरेट कंपनियां अवैध उत्खनन कर रही हैं। स्वाभाविक है अरबों रुपए प्रतिमाह का यह कमिशन न केवल खनिज विभाग के निरीक्षकों अधिकारियों के साथ जिलाधीश उप जिलाधीश तहसीलदार पटवारी से लेकर प्रदूषण मंडल के अधिकारियों तक पहुंच रहा है। इसलिए स्वाभाविक है कि खनिज निकाले जाने के बाद खदानों को खुला छोड़ दिया जाता है वह बिल्कुल भराई नहीं की जाती और ना ही पेड़ लगाए जाते हैं जैसा कि अंग्रेजों ने अपने कानूनों में खनन के पूर्व और खनन की खदानों के पट्टे देने में शर्तो में लिखा जाता है। जो कि खुले में प्रदूषण कानूनों का उल्लंघन किए जाने के साथ हर वर्ष सैकड़ों लोगों की मौत का कारण भी बनता है जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर मुख्यालय तक सभी जिम्मेदार होते हैं।

यही कारण है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 13 साल गुजर गए परंतु अभी तक धारा 4 के अंतर्गत सारी जानकारियां, विभाग में पंजीकृत सभी औद्योगिक इकाइयों प्रदेश के 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकृत अनुज्ञप्ति धारक हैं वह कौन सा काम करती हैं उनकी फैक्ट्रियों में किन घातक रसायनों व पदार्थों का उपयोग किया जाता है यदि आपातकाल और दुर्घटना की दशा में किन सुरक्षा साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए की जानकारी तक अभी तक अपलोड नहीं की गई। न ही कौन सा अधिकारी, कर्मचारी नाम, पद, कहां क्या काम देख रहा है कार्यक्षेत्र और पात्रता क्या है। उसकी हर वर्ष के अंत में संपत्ति क्या है वर्ष की कमाई क्या थी? किस श्रेणी में किस योग्यता व जाति के आधार पर इस विभाग में कार्यरत है अभी तक धारा 4 के अंतर्गत साइट पर प्रदर्शित नहीं किया गया जो इनकी भ्रष्टाचार के प्रदूषण फ़ैलाओ मंडल की कार्यशैली का स्पष्ट प्रमाण है।

उपायुक्त लक्ष्मी प्रसाद पाठक के भ्रष्टाचार के कारनामे, लोकायुक्त के बेटे के साथ साझेदारी फर्म

श्रमोदय विद्यालयों के निर्माण व सामग्री आपूर्ति में भारी भ्रष्टाचार से करोडों हजम

म प्र के श्रम विभाग को वैसे तो सबसे गरीब विभाग समझा जाता है। इसके विपरीत यहॉ के कुछ अधिकारियों पर लोकायुक्त के छापे पढ़ना और उसमें जांच के नाम पर लंबे समय तक खींच कर उसे ठंडा कर भ्रष्ट अधिकारी को क्लीन चिट दे देना। स्वयं ही लोकायुक्त की भ्रष्ट कार्यप्रणाली को परिभाषित कर देता है। फिर जब पूर्व लोकायुक्त संजय नावलेकर के बेटे संदीप नावलेकर ने उस भ्रष्ट अधिकारी के साथ साझेदारी मे अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली हो। तो फिर सारे श्रम विभाग के भ्रष्टाचारियों के लिए रास्ता पूरा ही साफ हो गया। फिर तो उस उपायुक्त लक्ष्मी प्रसाद पाठक को क्लीन चिट मलिना हीं थी। फिर साथ ही दूसरे भ्रष्ट अधिकारियों जिसमे सहायक आयुक्त जैसमनि अली सितारा जिस ने मिलकर श्रमिकों के बच्चों के लिए फर्जी फर्म से खरीदी गई रुपए 60लाख की कॉपियों का प्रकरण हो जिसमें गरीबों के बच्चों को कॉपियां तो नहीं मिली, परंतु उस क्रय समिति के सभी सदस्यों के वारे न्यारे हो गए हो और जब सूचना का अधिकार में पत्रकार ने जानकारी मांगी तो उस पर बलात्कार का आरोप लगाकर उसे अंदर करवा दिया गया हो। तो समझा जा सकता है की इस गरीब विभाग में कैसे करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले होते हैं। बेशक श्रम विभाग गरीब है परंतु उसके अंतर्गत चलने वाले, म प्र श्रम कल्याण मंडल, दूसरा म प्र भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और तीसरा म प्रअसंगठित शहरी/ ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल मैं आने वाले करोड़ों रुपए प्रति माह के धन से बड़े-बड़े भारी भ्रष्टाचार किए जाते हैं। **शेष पेज 3 पर**

म प्र में कुछ समय पूर्व प्रदेश के चार महानगरों ग्वालियर भोपाल जबलपुर और इंदौर में गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा देने के उद्देश्य चार श्रमोदय विद्यालयों जिनमें 200 छात्र व 200 छात्राओ को छात्रावास की सुविधा के साथ निर्माण कराने की व्यवस्था की गई जो लगभग 80 से 100 करोड के हैं इंदौर में यह विद्यालय इंदौर और बेटमा के पास ऊपर पहाड़ी पर इस विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि पुर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरसी लाहोटी के भतीजे को दिया गया है जबलपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी के भाई को, ग्वालियर में भाजपा के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कें और भोपाल में माननीय महा घोर भ्रष्ट शिवराज चौहान के रिश्तेदार को इन विद्यालयों व छात्रावासों के निर्माण का ठेका दिया गया है। स्वाभाविक सी बात है की जिन्हें मकान बनाने का अनुभव नहीं था वह 400 बच्चों के छात्रावासों और विद्यालयो का निर्माण कैसा और क्या कर रहे होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। हालात यह हैं कि छात्रावास और विद्यालय अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है उनके सीमेंट का प्लास्टर टपकने लगे हैं। दरवाजे खिड़कियां टूटने हिलने और टपकने लगे हैं। और शायद छात्रावास विद्यालय में पढ़ाई शुरू होने पर छतें भी टपकने लग जाएंगी। परंतु लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई के परियोजना संचालक वर्मा से लेकर, इंदौर के अतिरिक्त संचालक डी एस तिवारी, वर्तमान संभागीय यंत्री सेनानी की औकात नहीं कि वह इन सब घटिया निर्माण की सच्चाई को बता कर काम रुकवा उनके बिलों के भुगतान रोक दें। यही हाल भोपाल जबलपुर ग्वालियर में भी विद्यालय और छात्रावास निर्माण का है।

लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुलेमान सब जानकर भी चुप है क्योंकि मामला पार्टी के बड़े नेताओं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जुड़ा हुआ है इसलयि सब अपना-अपना कमीशन खाकर जो हो रहा है। होने दो बाद में निर्माण की लागत बढ़ने, साथ ही अधिक कार्य के नाम ज्यादा आवंटन करवा कर कामचलाऊ धक्का लगाउ मरम्मत करवा के गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा के नाम मौत के मुंह में छोड़ दिया जाएगा। बेशक यह आवंटन लक्ष्मी प्रसाद पाठक के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की पी आइ यु कर रही है। इसमें सबका मोटा कमीशन है। जो कि करोड़ों में होता है।

अब कहानी पाठक की शुरू होती है। इसमें पाठक ने हीं फर्नीचर आपूर्ति, कंप्यूटर, भोजन व्यवस्था ड्रेस, कर्मचारियों व श्रमिकों की आपूर्ति आदि के लिए निविदाएं जारी की। जिसमें हर कदम कदम पर पाठक ने मोटे कमीशन के लिए अपने खास लोगों को निविदाआ देने के लिए भारी जालसाजियों को अंजाम दिया।

बड़ी कंपनियों को मोटे कमीशन के चलते टेंडर करने के लिए जिसमें फर्नीचर कंप्यूटर भोजन आपूर्ति आदि के टेंडर अपने खास लोगों को देने के लिए पाठक ने हीं बार बार टेंडर की शर्तों को बदला। फर्नीचर में जो फर्नीचर गोदरेज बनाता भी नहीं था उस फर्नीचर को गोदरेज कंपनी के नाम से दोगुनी से 3 गुनी कीमत तक में खरीदा गया। जिसमें अलमारियां कंप्यूटर टेबल कुर्सियां और अन्य सामान था और इंदौर कि मेथोडेक्स कंपनी को जोकि वर्तमान आपूर्ति के के सामान से एक तिहाई कीमत मैं फर्नीचर सप्लाई करने को तैयार थी उसको बाहर कर दिया गया क्योंकि वह पाठक की इच्छा अनुसार करोड़ों का कमीशन देने में सक्षम नहीं था।

यही हाल कंप्यूटर की की करोड़ों की खरीदी में भी हुआ जो कंपनियां कंप्यूटर कंप्यूटर कंपोनेंट्स नहीं बनाती है। इसके विपरीत अपने खास आदमी से वही कंप्यूटर जो कि सीधे उत्पादक के बिट वितरक से लेने की अपेक्षा, 20:30 पर्सेंट की कीमत का वही माल कंपनी के लोकल वितरक की कीमतों में खरीदा गया उसमें भी 40 से 50 पर सेंट का कमीशन पाठक ने डकारा।

प्रदेश की राजधानी भोपाल के श्रम विभाग में 20 वर्षों से पदस्थ टी जैसमिन अली सितारा जसिकी शादी भोपाल में हुई भोपाल में ही मूल निवास है वह पिछले 20 सालों से अकेले श्रम विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ है। जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश संनिर्माण कर्मकार मंडल की अध्यक्ष थी भारी करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। इसका पति अहमद अली विश्वास सारंग मंत्री के साथ सक्रिय भाजपा का कार्यकर्ता है । पति पुलिस में था जिसकी नौकरी छुड़वा कर उसको वह पार्टी में ले आई। ताकि सहायक श्रमायुक्त के रूप में कमाया गया काला धन पत्नी से पति की कमाई दिखा कर निवेश किया जा सके। इसका आखिर स्थानांतरण क्यों नहीं किया जा रहा। जोो की पिछले 20 सालों से एक ही स्थान पर अपने गृह जिले में नौकरी कर रही है। जो कि कानूनी तौर पर पूर्णता गलत है जैसमिन अली सतारा के सीधे संबंध शिवराज सिंह चौहान विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा विधायक से हैं जो इससे पिछले 20 सालों से एक ही शहर में पदस्थ किए हुए हैं।

मध्यप्रदेश श्रम विभाग की इस महिला अधिकारी के सभी बड़े अधिकारियों और नेताओं से घरेलू संबंध इसे यहां बचाए हुए हैं और उसको बड़े बड़े पदों पर पदस्थ किया जाता रहा। जब सितारा संनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष थी तभी खरीदी में बहुत सारे घोटाले किए गए थे परंतु सभी से मधुर संबंध होने के कारण उसे बचाया जाता रहा सूचना का अधिकार में जानकारी देने की अपेक्षा पत्रकारों को मारपीट और बलात्कार के आरोप में उलझाया गया। इसके विपरीत अधिकारी वहां बरसों से कुंडली मारे बैठे सभी प्रकार के भ्रष्टाचारियों को अंजाम देने के साथ भोपाल संभाग के आने वाली बीस से ज्यादा उद्योग क्षेत्रों की 500 से ज्यादा इकाइयों में श्रमिकों का वास्तविक कानूनी कल्याण व अधकिार का कार्य त्याग कर सभी उद्योगपतियों उनके श्रम अधिकारियों से मोटा धन लेकर अपने स्व कल्याण मैं लगी हुई है। यह है शिवराज सरकार की गरीब श्रमिकों की कल्याण की योजना का हिस्सा और 0% भ्रष्टाचार की नीति।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

लोनि विभाग ऊपर से नीचे तक भ्रष्टों का तांडव, अधिकांश पदों पर प्रभारी रॉयल्टी के लिए

ई टेंडरिंग में जालसाजी, काम-भुगतान पहले, टेंडर बाद में, चुनावी चंदे की वसूली

प्रधान सचिव सुलेमान, प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल से लेकर, नीचे तक भवन एवं पथ, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सेतु, सड़क डकैती निगम के मुख्य अधीक्षण व सभी संभागों में, कार्यपालन यंत्री से उपयंत्री तक कर रहे हैं। घोर जालसाजयिा व वसूली। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर कोई भी कार्यपालन यंत्री जानकारी नहीं देता जब सारे कार्य कंप्यूटर से होने लगे तो धारा 4 के अंतर्गत सब कुछ आवंटन कार्य प्रगति नापपुस्तिका भुगतान आदि सब ऑनलाइन क्यों नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा फायदा इसका विभाग को मिलने के साथ जनता को भी पारदर्शिता के साथ मिल सकेगा उसे मालूम पड़ सकेगा। कितना काम हुआ का कितना भुगतान हुआ। इंदौर के पूर्व के 10 साल तक जमे रहने वाले आरके व्यास वर्तमान में भोपाल में मुख्य अभियंता है और भारी भ्रष्टाचार में दोनों हाथ से बटोर रहे हैं। इंदौर में संभाग 1 में पदस्थ आरके जोशी भी अपनी सहिंस्थ वाली कार्यशैली से इंदौर में कार्य कर रहे हैं। चुनावी माहौल में पूरे प्रदेश के भवन एवं पथ के सभी कार्यपालन यंत्रीयों की दसों घी में, सिर भ्रष्टाचार से जिलों के जिलाधीशों के साथ चुनाव के नाम पर उल्टे सीधे आधे अधूरे कार्य करवाकर मोटा धन अंटी करने के चक्कर में उलझा हुआ है।

चुनाव सर पर हैं और अभी तक सरकार ने अनेकों घोर भ्रष्ट जिसमें लोक निर्माण विभाग के संभाग क्रमांक एक में बैठा एसडीओ अभय राज दुबे 10 वर्षों से और पंकज तिवारी 7 वर्षों से, अधिकारी जो वर्षों से जमे हुए हैं। उनका स्थानांतरण नहीं किया। ये तो भ्रष्टाचारी थे इनके साथ में इनका आका का यं आरके जोशी जिसने उज्जैन में 2016 सिंहस्थ में काफी सैकड़ों करोड़ के कामों में मोटे भ्रष्टाचार किये है। और सब को धन बाटा इसलिए इनके आकाओं ने जिस में अखिलेश अग्रवाल प्रमुख अभियंता और प्रधान सचिव सुलेमान ने खुश होकर इंदौर में बैठा दिया। सूचना के अधिकार में इस हरामखोर ने उज्जैन में भी कोई जानकारी कभी नहीं दी क्योंकि यह घोर भ्रष्ट मोटा धन खर्च करके सिंहस्थ के लिए ही आया था।

अब आलम यह है की बिना टेंडर के करोड़ों के काम करवा लिए जाते हैं। हाल ही में चुनावों के लिए इंदोर स्टेडियम में और सभी शासकीय भवनों कार्यालयों जहां पर मतदान केंद्र रखा गया है। वहां पर रेंप बनाने, पानी, बिजली व अन्य व्यवस्था करने के लिए करोड़ों रुपए चुनाव आयोग से लोक निर्माण विभाग नगर निगम आदि को मिलते हैं। यह कहानी पूरे प्रदेश के हर कार्यपालन यंत्री की है। उसके बाद में टेंडर जारी होते हैं फिर दूसरे ठेकेदारों को हडका कर अपने खास ठेकेदार को काम दे दिया जाता है। उसमें पंकज तिवारी जो उपयंत्री भी है और सहायक यंत्री भी हैं। दोनों का हिस्सा डकार कर फर्जी बिलों से का यंत्री जोशी तिवारी और ठेकेदार के बीच में कई सालों से मोटा लेन-देन चल रहा है। रंगाई पुताई और सरकारी भवनों में छोटी मोटी रिपेयरिंग थे पिछले 7 साल में तिवारी ने करोड़ों का काम करवाया अब आप अंदाज लगा सकते हैं । जबकि सत्तर परसेंट काम कागजों पर ही संपन्न हो गया सूचना के अधिकार में यह हरामखोर की जानकारी नहीं देते।

इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर अपने समाचार पत्र में इंदौर और भोपाल के साथ जहां जहां आप हैं वहां भी प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

टीवी चैनल्स वाले पत्रकार ऐसे 10-50 मतदान केंद्रों की शूटिंग करके सभी जिलों के कार्यपालन यंत्री यों के साक्षात्कार, लेखन के गठन के कर्ज के बारे में पूछने वैसे तो 99% रेंप पुराने ही बने हुए हैं उन पर लिपाई पुताई करके ही बिल बनाकर करोड़ों रुपए जिले का कलेक्टर, कार्यपालन यंत्री, ठेकेदार, उपयंत्री, सहायक यंत्री, हजम कर लिया जाता है।

चुनाव का चंदा या अधिकारियों का धंधा?

मध्यप्रदेस लोक निर्माण विभाग के न्यू डवलपमेंट बैंक के माध्यम लोन लेकर प्रदेश की सड़क पुल बनाये जा रहे हैं, लेकिन 50 करोड़ तक के पैकेजो के टेंडर बुलाये गये थे जिन ठेकेदारो ने को वर्क आदेश/अनुबंध किये जा रहे हैं उनसे 50-50 लाख का चुनावी चन्दा मांगा जा रहा हैं। कुछ ठेकेदार दे रहे हैं और कुछ चुनाव परिणाम का इंतज़ार कर ऊठ किस करवट बैठेगा तक देखो और आगे बढो की भूमिकाओं में हैं। हरदा जिले में मरम्मत कार्यो के नाम पर भुगतान हुए है। कुछ सहायक यंत्री ठेकेदार में तकरार के चलते एक ठेकेदार के विरुद सहायक यंत्री ने पुलिस प्राथमिकी। दर्ज करवाई हैं। मामला लेंन देंन को लेकर हैं। सहायक यंत्री ठेकेदारो पर दबाब बनाकर बताते हैं कि मेरी पत्नी राजधानी का प्रतिष्ठित अख़बार में पत्रकार हैं। यह भी सत्य हैं। सहायक यंत्री जोड़तोड़ में माहिर हैं कार्यपालन यंत्री का सरक्षण हैं हँसकर किसी बात को टालना इनकी कला हैं। आर के व्यास मुख्य अभियंता का सरक्षण था आजकल मुख्यअभियंता RK वैद्य का सरक्षण जारी हैं ? गरमा गरम ख़बर यह हैं कि आर के व्यास की ख्याती चाचा भतीजा की तरह हैं आर के व्यास का चयनकर्ताओं ने आर्बिटेशन मैं सिलेक्शन कर लिया है और सूत्रों से ख़बर हैं कि आर के व्यास का आवेदन नोटिस शासन को भेज दिया हैं दबाब यह बनाया गया हैं कि मुख्य न्यायाधीश तत्काल उपस्थिकति कराना चाहते हैं। कितना सच हैं? यदि कोई काग़ज हो बात बनती हैं लेक़िन भतीजा झूठ मक्कारियों से भरा महान भ्रष्टाचारी हैं, इस पर बहुत से प्रकरण धूल खा रहे हैं ऐच्छिक सेवा निवृत्तिभ लेने से वे सब दब जाएंगे, हमारी शासन से अपील हैं कि बुधनी में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री केलकर के विरुद्ध 85 लाख की रिकवरी को आर के वैध, आर के व्यास के ऊपर बराबरी से निकलनि चाहियें, मुख्यआभियन्ता आर के व्यास ओर अधिक्षण यंत्री आर के वैद्य के सरक्षण में भ्रष्टाचार हुया था।

सभी सरकारी योजनाएं, सड़कें, सरकारी भवन, स्मार्ट सिटी सब डकैत भूमाफिया नेता अधिकारियों के इशारे पर लाभ के

भू माफियाओं के लाभ के लिए कोर्ट बनेगा पिपलिया हाना तालाब में

वर्तमान में जिस मोती बंगले में जिला एवं सत्र न्यायालय चल रहा है पिछले 40 सालों से, वहां पर भी पिछले 20 वर्षों से 100 से ज्यादा कमरों का निर्माण किया गया है और वहां पर भी न्यायिक कार्य संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही पीछे मलि की जमीन खाली पड़ी हुई है। पर वहां न्यायालय नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बड़े भू माफियाओं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं कब्जे में है उस जमीन की भारी कीमत बड़े प्रोजेक्ट्स में बसूल कर लेंगे। पिपलियाहाना तालाब जो पहले मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग का था।

जो १५० एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। पहले भूमाफिया ने महादेव तोतला, व्रजेश्वरी नगर, और करीब 10से ज्यादा कॉलोनियों के साथ ही वहां पर इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम नंबर140 मैं बड़ी शॉपिंग मॉल एक करीब 150 करोड़ की बिल्डिंग जो अभी बिक नहीं रही है जिसके तीन बार कीमतें कम कर दी गई परंतु जैसे ही पिपलियाहाना में तालाब को खत्म कर न्यायालय की बिल्डिंग बनाई जाएगी वैसे ही बायपास के पास बड़े-बड़े भारतीय प्रताड़ना सेवा के प्रधान, सचिव, जिलाधीशों, सहायक एवं उप जिला अधिकारियों, बड़े भूमाफिया नेताओं, और देश विदेश के सौ से ज्यादा बड़े जालसाज भूमाफिया कॉलोनाइजरो की जो 400 से ज्यादा कॉलोनिया अवैध रूप से कृषि, वन,नजुल भूमि पर खड़ी हुई है। उन सब की कीमतें भी आसानी से 50 से 100 गुना बढ़ जाएंगी, जिनमें सभी उच्च, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, केंद्रीय, राज्यो के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, अधिकारियों का कालाधन इन सभी कॉलोनियों में लगा होने, , जहां पर सभी भेड़िया झुंड पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं भू माफियाओं भारतीय प्रताड़ना, भारतीय अपराध संरक्षण पुलिस सेवा, एवं भारतीय वन नोचो सेवा आदि के अधिकारियों की जो जमीन है उन्होंने अपने काले धन से खरीदी हैं उनकी कीमतें 50 से 100 गुना बढ़ जाएंगी। इसलिए पिपलियाहाना तालाब में न्यायालय भवन का निर्माण करना आवश्यक है अन्यथा बेचारे सारे घोर भ्रष्ट, मक्कार जालसाजों को भविष्य मे काले धन कौ 50 से 100गुने मैं ना बदलने का नुकसान हो जाएगा। जब तक इंदौर शहर देवगुराडिया से कंपेल तक पहुंच जाएगा लगाया ।

यही कारण है नौलखा का बस स्टैंड उठाकर तीन इमली चौराहे पर फेंक दिया गया नहीं है नौलखा बस स्टैंड की जमीन जमीन पर नेताओं और अधिकारियों के के नाम उनके रिश्तेदारों के बारे न्यारे हो गये। आखिर इंदौर के भूमाफियाओं नेताओं, अधिकारियों जालसाज कॉलोनाइजर के सामने और उनके फायदे के लिए उच्च न्यायालय व भेड़िया झुंड पार्टी की सांसद सुमित्रा सब हिस्सेदार और सब न्यायालय का तीसरी बार उद्घाटन कयिा।

आखिर हर मानव प्राणी चाहे वह उच्च व सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश को या सांसद सुमित्रा महाजन हो सब की मृत्यु निश्चित है। परंतु सब हैं घोर लालची, अपनी जमीन मजबूत करने के लिए अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करते हैं। जमीनों का तांडव छोटे गांव और जंगलों से लेकर राजधानी दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों तक भू माफिया, गुंडे, नेताओं, अधिकारियों, न्यायाधीशों, पुलिस, प्रशासन, का लाखों करोड़ का मोटा गठजोड़ है

सबकी निगाहे जमीन से उठकर, मृत्यु तक जमीन पर, मजबूत करने, खरीदने और अपने नाम करवाने के भ्रम में लगी रहती हैं। और मृत्यु होने पर वो आकांक्षाएं भी मिट्टी में मिल जाती है उसी प्रयासों का परिणाम है पूर्वी इंदौर के एक मात्र पिपलियाहाना तालाब में हरित प्राधिकरण द्वारा आपत्ती लेने व जनता द्वारा बार-बार मना करने व प्रदर्शन करने के बाद में भी उस तालाब की भूमि को खत्म कर न्यायालय बनाकर उस क्षेत्र में बड़े भूमाफियाओं की जमीनों को जिनका अभी कोई भाव नहीं है सब की जमीनों के भाव 100 से 200 गुना ज्यादा हो जाएंगे और इंदौर शहर बढ़ते-बढ़ते 15 कि मी आगे कंपेल तक पहुंच जाएगा और वहां तक की जमीनों के भाव बढ़ जाएंगे ।

सबकी मृत्यु निश्चित है। अगले पल का ठिकाना नहीं। व्यवस्था सात पुश्तों की कर रहे हैं। हरामखोर सब कंक्रीट जंगल बना दो आने वाली पीढ़ियों को ना हरियाली मिले ना खेती के लिए जमीन बस इन सब को ही बड़ी पोश कालोनियों में 2-5 बंगले, अरबों की जमीन, बैंक बैलेस चाहिए, खाने को , 4 रोटी ढंग से पचती नहीं और अपनी बैंक के देश के विदेश की भरने को हर षडयंत्र रचना इनके नेता अधिकारी होने की निशानी है।

फिर मानव जैसा शैतान प्राणी घोर लालची, मक्कार वह भी भारत का, धरती शर्मसार है।

फिर जो जितने बड़े पद पर उतना बड़ा शैतान ।

इनकी बला से कल का मरता आज मरे देश, प्रदेश, नगर का सारा इंसान।

नर्मदा ताप्ती कछार मुख्य अभियंता शर्मा विभाग बाप की जागीर नहीं, कर्मचारी हो

मुअ शर्मा मत बनो तानाशाह, जानकारी देने से क्यों लगता डर

इंदौर का मप्र जल संसाधन विभाग का मुख्य अभियंता वाय सी शर्मा घोर बदतमीज होने के साथ कानून को भी अपने बाप की जागीर समझता है और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यह हरामखोर सूचना के अधिकार में जानकारी देने की अपेक्षा सूचना के अधिकार के अंतर्गत धारा 19 में नियत किए गए प्रशासकीय कार्यालय के प्रमुख को जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारी बनाया गया था और उसके वरिष्ठ अधिकारी को उसका अपीलीय अधिकारी बनाया गया है परंतु यह हरामखोर महाधूर्त अपने आप को बचाने और अपने कार्यपालन यंत्री को बचाने के लिए इन्होंने कार्यपालन मंत्रियों को ही उनका अपीलीय अधिकारी बना दिया। यह सब करने की इसको पात्रता ही नहीं थी। पर इस श्वान ने अपनी महानता दिखाते हुए एक आदेश स्वयं ही निकाल दिया। जिसकी प्रतियां ऊपर लगी हुई है। जिसमें कार्यपालन यंत्री को ही अपीलीय अधिकारी बना दिया गया है। वैसे वाई सी शर्मा की बदतमीजी पूर्ण हरकतें, तानाशाही और भ्रष्टाचार से इंदौर के नर्मदा ताप्ती कछार के 16 कार्यपालन यंत्रीयों चार अधीक्षण यंत्रीयों के साथ उनका स्टाफ भी भारी हैरान परेशान है।

वैसे भी वाई सी शर्मा ने अधिकांश समय मुख्यालयों में अटैच लेकर गुजारा है। उनका ज्यादा बड़े स्टाफ से कभी पाला नहीं पड़ा और पूर्व का इतिहास भी इनका शुरू से ही बहुत गंदा रहा है पूरे नर्मदा ताप्ती बेसन का स्टाफ प्रार्थना कर रहा है कि कब यह यहां से स्थानांतरित होकर अपना कृष्ण मुख करेंगे।

वैसे भी क्षेत्र में जाकर अपने अधीनस्थ ओं के कार्य की समीक्षा की कर लेते तो मालूम पड़ जाता कहां क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा कांड खरगोन मंडल में हुए जहां पर एक ही अधीक्षण यंत्री भगोरा पिछले 20 सालों से बैठकर क्या काला पीला कर रहा है मालूम पड़ जाता पर शायद कमीशन दे रहा है। जो वहां 1992 से सहायक यंत्री बन कर पदस्थ हुआ वहीं पर कार्यपालन यंत्री 2002 मे, 2010 मे अधीक्षण यंत्री बना हुआ बैठा है। अनेकों टेंडरों मैं आधा अधूरा काम करवा कर भुगतान करके फरि उसी कार्यय के 10 से 12 टेंडर निकाल कर करोड़ों रुपए हजम कर गया। उससे व ऐसे ही व अन्य सभी से ही मोटा कमीशन मिलने के कारण ना तो उन्हें सूचना के अधिकार के धारा 6(3) में पत्र अन्तरति किए जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए हरामखोर हरामखोर ने अपने स्तर पर ही पत्र निकाल कर कार्यपालन यंत्री को कार्यपालन यंत्री का अधीक्षण यंत्री को अधीक्षण यंत्री का अपीलीय अधिकारी बनाकर धारा 19 (1) खुला मजाक उड़ाया। जब इसकी शिकायत ऊपर की गई तो मालूम पड़ा ऐसा कोई भी पत्र इसके आधार पर यह पत्र दिया था मुख्यालय से नहीं निकाला गया जिसके आधार पर मन से ही यह पत्र जारी कर दिया। जबकि पड़ोस के जिले देवास में जाकर दतुनी बांध की नहरों के किनारे जाकर उसकी कंक्रीटिंग लाइनिंग और बनावट देख लेते डिजाइन से कितनी अलग बनाई गई है।

मालूम कीजिए कन्नौद सतवास रोड के समानांतर बनी हुई एक तरफ बोला जा रहा है नहर में पानी चल रहा है दूसरी तरफ 70% से ज्यादा सुखी पड़ी हुई है नहरों की बनावट स्पष्ट करती है। शर्मा की की यही निष्ठा काम और नहरो के प्रति दिखाई देती तो शायद जनता के लूटे धन से मिलने वाला वेतन सार्थक होता परंतु अपने आप को छुपाने बचाने मैं जो ऊर्जा खर्च की जा रही है और जसि तरीके से स्टाफ को कानून के प्रति बदतमीज और लापरवाह बनाया जा रहा है। भविष्य में उच्च भ्रष्टाचार को को पोषित करने का कार्य कर रहा है।

जबकि पूरे विभाग में धारा 4 के अंतर्गत मुख्यालय से लेकर हर कार्यपालन यंत्री के कार्यालय की सारी जानकारी कितना धन प्राप्त हुआ। कहां व कैसे उपयोग हुआ। कौन-कौन लोग कब से, कहां काम, व क्या काम कर रहे हैं? किस की संपत्ति कितनी है? किस जाति के अंतर्गत जाति का लाभ लेकर कौन-कौन से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और आरक्षण का लाभ लेकर वह उस पर विराजित हुआ है। आदि सब सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 17 बिंदुओं की जानकारी विभागीय साइट पर अपलोड होनी चाहिए थी। जो कि इन हरामखोरों ने 13 साल के बाद में भी आज तक नहीं डाली जब सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी जाती है तब यह हरामखोर मक्कार भ्रष्टों की फौज जानकारी देना देने के लिए बहाने बनाती है और पांच पांच पेज के खर्रे बना बनाकर भेजती है।

इस पर पत्रकार पर अपनी समाचार पत्रों में टिप्पणियां लिखें और सरकार से पूछो कि आखिर 13 वर्ष के बाद में भी मध्यप्रदेश की सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 की जानकारियां अभी तक नहीं डाली गई और सरकार अपने आप को बहुत इमानदार बताती है। के अधिकारी सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देते जनधन को अपने बाप की जागीर समझते हैं और सूचना देने के नाम पर बहाने बनाते हैं ऐसे अधिकारियों के ऊपर सरकार ने अभी तक कार्यवाही नहीं की ना ही धारा-4 की जानकारियां सबकी साइट पर लोड की गई। चारों तरफ घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। और सरकार का मुखिया शिवराज अरबों रुपए हर महीने अपने चुनावी कैंपेन में जन धन का खर्च कर रहा है घोर भ्रष्टाचार के धन से। इस के विपरीत अपने आप को ईमानदार बता रहा है।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

मध्य प्रदेश ग्रामीण यांत्रिकीय के कार्यपालन व सहायक यंत्री की सेवाएं दिखावा बना दी गई

ग्रामीण विकास के नाम पर बर्बाद किया जा रहा भ्रष्टाचार के लिए पैसा सीधा पंचायतों को देकर

कोई भी निर्माण कार्य बिना कार्यपालन एवं सहायक यंत्री की मंजूरी व बिना देखरेख के किया जाना घातक व बर्बादी। सरपंच जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी बंदर बांट के लिए अपनी मर्जी से जो स्तरहीन निर्माण कार्य करवा रहे हैं वह जनता के लिए घातक व जनधन की बर्बादी।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास के नाम पर भारी चारों तरफ भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही दिया जा रहा है ताकि सरपंच,सचवि, जनपद अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण विकास का जनधन का पैसा आसानी से भ्रष्टाचार में हजम करके खुश रहें व भाजपा के पक्ष में आने वाले समय में मतदान करवाते रहे और भाजपा की सरकार बनती रहे। जब से मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रधान सचिव राधेश्याम जुलानिया को ग्रामीण विकास का प्रभार दिया था। तब से ग्रामीण विकास के निर्माण कार्यों के लिए कार्यरत संस्था ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा के कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री को केवल ग्रामीण विकास में चल रही सभी निर्माण गतिविधियों का केवल देखने का कार्य सौंप दिया गया जबकि उसकी विस्तृत परियोजना विवरण पुस्तिका मैं किसी भी निर्माण कार्य की सारे कार्य की योजना, सामग्री व लागत तैयार की जाती है। जिसे उपयंत्री सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री की देखरेख में सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है वहां की मिट्टी और जलवायु कैसी है। जिस पर निर्माण कार्य होना है के आधार पर तैयार होती थी। परंतु जब से जुलानिया जी ने कार्यभार संभाला था उन्होंने यह सारा काम पंचायतों के सरपंचों, सचिव और उपयंत्री के हवाले कर दिया था। जिससे उपयंत्री जो कर्मी था तो ग्रामीण यांत्रिकी का परंतु वह भी सरपंच और सचिव के इशारे पर डीपीआर तैयार करता था और उसी के हिसाब से सारा निर्माण कार्य जिसमें भवन निर्माण, नालियां, सड़कें, तालाब, छोटी-मोटी नहरें जो कि मनरेगा के धन से भी बनाई जाती हैं। यह तीनों मिलकर किसी अपने ही भाई भतीजे छुटभैया ठेकेदार से स्तरहीन काम करवाते है और कुल लागत का 25 से 50 प्रतिशत पैसा हजम कर जाते हैं। इस प्रकार के सभी निर्माण कार्यों में उपयंत्री अपने सहायक और कार्यपालन यंत्री की मंजूरी भी नहीं लेता और किसी भी प्रकार की जानकारी भी नहीं देता। सहायक, कार्यपालन व अधीक्षण यंत्री केवल कार्यों की देखरेख कर सकते थे। परंतु वह किसी भी प्रकार की रोका टोकी व स्तर हीनता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते थे। क्योंकि उपयंत्री ही नाप पुस्तिका भरता, बिल चढ़ाता और बनाता और पंचायत के खाते से उसका भुगतान करवा दिया जाता है। स्वाभाविक है कि पिछले 3 सालों में ग्रामीण विकास का पंचायत को मिलने वाला भवन, सड़क, नालियां, तालाब, स्टॉप डैम, नहरें आदि बिना पूर्वनियोजित नियोजन से ही मनमर्जी के तरीके से बनाई जा कर प्रदेश के 51 जिलों में लगभग रुपए 20000 करोड की बर्बादी की गई जिसमें केंद्र सरकार की मनरेगा, ग्रामीण विकास का व प्रदेश का पंचायतों का और् ग्रामीण विकास का जनधन बर्बाद किया गया। अधिकांश कार्य कागज पर ही संपन्न होकर धन हजम हुआ, पर जो भवन, गांवो में बनाई गई कांक्रीट की सड़कें, तालाब, नालियां, ब स्टॉप डेम कई जगह तो इतने कमजोर बनाए गए की एक बरसात भी ढंग से नहीं देख सके। इस प्रकार के 90 परसेंट कामों की ना तो कोई जांच की गई ना शिकायतें हुई क्योंकि धन सीधा उपयंत्री सरपंच सचिव से लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष व सचिव जिला पंचायत अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालन अधिकारी से होता हुआ जिलाधीश प्रभारी मंत्री ग्रामीण विकास सचिव प्रधान सचिव व मंत्री को बंट गया। निसंदेह मुख्यमंत्री शिवराज ने ग्रामीण विकास में जुलानिया को इसी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बैठाया था। प्रधान सचिव जुलानिया ने जब इस भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की तो सरपंच सचिवों जनपद अध्यक्ष वह सचिवों ने जुलानिया की शक्ति से त्राहि-त्राहि कर उ ठे तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को की तो उल्टे ही अपना जनाधार बिगड़ते हुए देख जुलानिया से ग्रामीण विकास ले कर विदा कर दिया।

धार में बैठ जब ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग में जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत काम करता है और वहां पर यह व्यवस्था थी कि किसी भी निर्माण कार्य की पहले मंजूरी ली जाकर, उसकी हर तथ्य को ध्यान में रखकर उपयंत्री से डीपीआर बनवाई जाती थी। जिसे बाद में सहायक यंत्री जांच कर अनुमोदित करता था । उसके बाद कार्यपालन यंत्री के द्वारा वह स्वीकृत कर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दी जाती थी। प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति के बाद उसकी निविदा प्रकाशित कर निर्माण एजेंसी नियुक्त की जाती थी जिस पर वह कार्य उपयंत्री द्वारा ठेकेदार से डी पी आर के अनुसार करवाया जाता था। जितना कार्य होता था उस कार्य का आकलन कर नाप पुस्तिका में चढ़ाने का काम उपयंत्री करता है। जैसा कि हर निर्माण विभाग यथा लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जल संसाधन आदि में विभागीय

पध्दति के अनुसार होता है। अर्थात पुनः पूर्व की तरह अन्य निर्माण विभागों की तरह सहायक व कार्यपालन यंत्री का डीपीआर बनाने से लेकर बिल बनाने का भुगतान करने की पद्धति को पुनः लागू किया जाए। और संबंधित पंचायत में निर्माण कार्य के संपन्न होने पर उसका भुगतान कार्यपालन यंत्री की हाथ में ही हो ताकि कार्य निर्धारित मापदंड और स्तर के अनुसार मजबूती के साथ संपन्न किया जाए और गड़बड़ी पाए जाने पर आसानी से सहायक व कार्यपालन यंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा सके अन्यथा ग्रामीण विकास को दी जाने वाली जन धन की राशि का 30 से 70% तक का पैसा अशिक्षित और गैर तकनीकी सरपंच सचिव जनपद पंचायत अध्यक्ष व सचिव मिलकर ही डकारते रहेंगे। और इन स्तरहीन निर्माणो से होने वाली जनहानि का जिम्मेदारी गाहे-बगाहे मंत्री और मुख्यमंत्री पर आएगी।

जनसंपर्क नामाः मुख्यमंत्री के खास रिश्तेदार के कलम तले जनसंपर्क में फिल्मों की बंदरबांट

लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा सत्ता जाएगी छूट

चुनाव आते ही जनसंपर्क में अधिकारीयों के हरियाली के दिन आ जाते हैं। जनसंपर्क के भारी भरकम प्रचार बजट से अपने अपनों को उपकृत करने का सिलसिला जारी है।. वर्तमान में जनसंपर्क का जिम्मा एक आईएएस और आईपीस अधिकारी पर है। जो मुख्यमंत्री की चुनावी नैया को पार लगाने की ताकत लगा दी हैं। आईएएस अधिकारी इन्दोरियों को उपकृत कर अब बजट को ठिकाने लगाने के कार्यों में व्यस्त हो चुके हैं और आईपीएस के तो कहने क्या? सैंया भये कोतवाल तो अब डर काहे का...

जनसंपर्क के विज्ञापन कार्यों के अलावा इन दिनों जनसंपर्क में प्रचार प्रसार की फिल्मों और चुनावी रथ को लेकर काफी गहमा गहमी है।अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली है कि एक उच्च अधिकारी के इशारे पर लगभग ६ करोड़ रुपये का विडियो रथ का कार्य इलेक्शन कमीशन के एक पूर्व अधिकारी एवं जनसंपर्क निदेशक के कहने पर एक एनजीओ आधार कला प्रशिक्षण केंद्र जिसका सञ्चालन श्री पुरूषोत्तम बुधवानी करते हैं , उनको रातों रात दे दिया गया।

गौरतलब है श्री पुरूषोत्तम बुधवानी पेन्ट के व्यवसाय को त्याग कर एक फिल्म वितरण अधिकारी को पार्टनर बना मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले विभाग में चांदी काट रहे हैं।६करोड के इस कार्यादेश में जनसंपर्क के वरिष्ठ अधिकारी की इसमें सहमती न होने के बाद भी यह खेल खेला गया .और ऑर्डर दे दिया गया...खबर है कि उक्त डील में ४०-५० प्रतिशत की डील एडवांस में खेली गयी। यह रथ पूरे प्रदेश में चुनाव हेतु लोगों को प्रेरित किया।

फिल्मों से अधिकारियों का बदलता चेहरा

शिवराज का चेहरा चमकाने के लिए बनने वाली फिल्मों में बंदरबांट का खुला खेल खेला है जिसमें संचालक और कमिश्नर जनसंपर्क की मूक सहमती प्रतीत थी।

खबर है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार नए संचालक ने आते ही सर्वप्रथम मलाईदार विभागों की जानकारी ली और फिर फिल्म निर्माण कंपनियों के संचालकों से वन टू वन मीटिंग की सरकार की योजनाओं पर फिल्मों के निर्माण के संबंध में चर्चा की गई। ८० फिल्म निर्माताओं को झटका तब लगा जब रातों रात फिल्म निर्माण के लगभग २.२५ करोड़ के आर्डर (८५ फिल्मों) रात बारह बजे तक कुछ खास लगभग ९ कंपनियों को जारी किये गए...उक्त फिल्म निर्माताओं में एस ऍफ़ प्रोडक्शन ,मुंबई ५ फिल्म , श्रद्धा फिल्म्स -मुकुंद शर्मा ५ फिल्म्स, खोजी पिक्चर ,जबलपुर ओनर - शिवकुमार शर्मा ,बॉलीवुड फिल्म- शिवशर्मा ५ फिल्म्स , अलुमिनी फिल्म्स -शिवकुमार शर्मा ५ फिल्म , स्वाति प्रोडक्शन ,न्यू दिल्ली ५ फिल्म्स , इंडस फिल्म्स - अरविन्द त्रिपाठी ५ फिल्म्स , राजेश गुप्ता नर्मदा फिल्म्स संस्था , जी आर films- संदीप कुशवाह प्रमुख ५ फिल्म कुल ८५ फिल्म है। ...यूं तो बन्दर बाँट का ये खेल पिछले १५ वर्षों से जारी है और आर्थिक अनियमितताएं लोकायुक्त और cow की जांच में है । किन्तु १५,दिन पूर्व उसमें एक और दाग लग गया।

...आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्था के फिल्म निर्माण से जुड़े बाबू श्री कैलाश घोडकी कई अधिकारीयों के भारी खर्च उठा कर १० वर्षों से इस पद पर बने हुए हैं पद मलाईदार जो ठहरा मामला .... ये फिल्मों की हर बात गोपनीय रखते है और आर्थिक अनियमितताओं के राजदार है और पैसे मांगने का खेल खुले में खेलते हैं।

एक उपसंचालक श्री राजेश बेन जो फिल्म निर्माण के साथ साथ इलेक्ट्रोनिक मीडिया भी देखते हैं भी कई फिल्म कम्पनियों में पार्टनरशिप दखल रखते हैं ..बड़ा माल पीट चुके हैं .अभी हाल ही में उन्हें शिकायतों के आधार पर उन्हें जनसंपर्क मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा के आदेश पर हटाया गया था किन्तु अपने अर्थ मैनेजमेंट के चलते वे अंगद के पैर की तरह पुनः जम गए .....और मंत्री जी की एक ना चली।

जनसंपर्क के कई वरिष्ठ अधिकारी इस बंदर बाँट के मूक साक्षी हैं और दबे स्वर में खुसुर पुसुर भी करते हैं किन्तु आईपीएस-आईएएस के खौफ और दबदबे के चलते सब मौन ...और आईपीएस भी मुख्यमंत्री का खास रिश्तेदार ....ना बाबा ना ..भैया जो चलता हैं चलने दो ....

रिश्तेदारी का चुनावी फायदा मुख्यमंत्री को

फिल्मों के निर्माण के जरिए कुछ खास फायदा सिमेरू वीडियो को पहुंचाना है जो फिल्म अंगद का पैर और कई अन्य एनिमेटेड फिल्म कांग्रेस पर , कमल नाथ पर अटैक करती फिल्म निर्माण कर चुकी है । इस संस्था को ५० लाख रुपए की पहली खेप का भुगतान इन निर्माताओं के माध्यम से रिश्वत हेतु करवाया गया जिससे वो कांग्रेस पर खुला अटैक कर सके। और रिश्वत का एक नया जरिया भी वन सके। यह खेल संचालक के पी ए श्री राजेन्द्र बरखाने जो स्वयं भी फिल्म निर्माता हैं के मार्फत खेला गया। गौरतलब है कि श्री budhwanee को सामाजिक न्याय के विषय का फिल्म हेतु भी २.४० करोड़ का ऑर्डर दिया गया । कांग्रेस को लगातार अटैक करने और अपनी आर्थिक उन्नति हेतु विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा यह मिलीभगत का खेल खेला जा रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस इस मसले को चुनाव आयोग के समक्ष उठाकर शिवराज को इसके राजनैतिक फायदे और रिश्वतखोरी के खेल को उजागर कर सकती है।

सोचने वाली बात है कि ८० निर्माताओं के रजिस्टर्ड होते हुए भी आईं ए एस और आईं पी एस ने ये खेल क्यों खेला। दाल में काला ही काला है।

पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला को चिकित्सा अवकाश के बहाने दबाव में छुट्टी पर भेजा जाना षडयंत्र का प्रारंभ है

डीजीपी शुक्ला को दबाव में भेजा गया छुट्टी पर

क्या इसके पूर्व कोई भी अधिकारी कर्मचारी सेवा में रहते बीमार नहीं हुआ और बीमारी किसी को भी हो सकती है।10- 15 दिन की छुट्टी लेकर भी बायपास बीमारी का इलाज करवा कर आसानी से कर्तव्य पर उपस्थित हो जाता है। तो फिर पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला को जबरन बीमारी दिखाकर 2 महीने की छुट्टी पर भैजा जाना। भाजपा की चुनाव जीतने की रणनीति का षड्यंत्रकारी हिस्सा है यह बहुत साधारण घटना नहीं है। भविष्य में भाजपा जिस रणनीति से चुनाव जीतने की कोशिश में है।

फिर चुनाव सिर पर होने के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे प्रदेश में दशहरे पर पथ संचालन से क्या शक्ति प्रदर्शन कर चुनाव जीतने की प्रारंभिक रणनीति है। आखिर संघ भाजपा ही का पितृ संगठन है । क्यों इस संगठन पर चुनाव आयोग की आचार संहिता का कोई असर नहीं हुआ। दूसरी ओर क्या आचार संहिता केबल विपक्षी वह अन्य राज्य राजनीतिक संगठनों के लिए ही लागू होती है। उन्हीं को प्रचार-प्रसार से रोकने के लिए आचार संहिता के दायरे में बांधकर रोका जाता है। जबकि स्वयं भाजपा कि शिवराज सिंह चौहान अपनी आशीर्वाद यात्रा को अविलंब अविराम जारी रखे हुए हैं उसके पोस्टर बैनर झंडे सड़कों पर मंच चारों तरफ लगाए जा रहे हैं गलियां झंडे बैनर पोस्टरों से पटी पड़ी है। इसके विपरीत उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। बीच सड़क पर मंच लगाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में उनकी यात्रा निर्वाध, निर्विघ्न संपन्न हो रही है। इन सब नौटंकियों के विपरीत सरकार भारी दहशत में है कानून व्यवस्था पुरी प्रशासन के हाथ में है आप संभावित है भविष्य में चुनाव जीतने के लिए भारी जन आंदोलन की आड़ में अपने कुकर्मो पर पर्दा डालने के लिए गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी भाजपा भविष्य में सामाजिक दंगे करवा दे इसीलिए नियमित पुलिस महानिदेशक को हटाकर काम चलाऊ महानिदेशक को सत्ता सौंप दी गई ताकि भविष्य में कोई भी विवादों की स्थिति में कानूनी अड़चनों में आसानी से काम चलाऊ महानिदेशक को तत्काल हटा कर अपने आप को पाक साफ सिद्ध कर दिया जाए। यह उसकी शुरुआत है देखिए आगे होता है क्या? डरपोक सवर्ण हिंदुओं को दहशत देकर वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास का हिस्सा है यह।

भारत सार्वजनिक प्रसार माध्यमों पर अघोषित आपातकाल

पेज एक से जारी

तो उसने सीधे पहले इन सभी माध्यमों पर सीधा प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया पर जब यह प्रयास समय माया की साइटों द्वारा मीडिया में उछाला गया और मीडिया ने जब उस पर केंद्रित होकर इसकी सच्चाई को प्रकाशित करना शुरू किया तो सरकार बौखला गई और उसने सीधा प्रतिबंध लगाने की अपनी भाषा पर लगाम लगाते हुए, इसके लिए न्यायालयों को माध्यम चुना व भीडाक्रमण के नाम पर जो कि सहस्त्रों वर्ष पूर्व मानव सभ्यता के साथ चलन में आ चुका था। इस भीडाक्रमण को, अफवाहों से फैली हिंसा में हुई मौतों को, इन व्यक्तिगत संदेश प्रसार साधनों को आधार बनाते हुए सरकार ने सभी सामाजिक व्यक्तिगत संदेश साधनों जिसमें WhatsApp के संदेशों को एक बार 5 संदेश से ज्यादा संपर्कों पर संदेश भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जबकि सच इसके विपरीत था अपनी सच्चाइयों को फैलने से रोकने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया मोदी सरकार द्वारा।

दूसरी तरफ वर्तमान भेड़िया जानवर पार्टी की सरकार ने अपने विरुद्ध चल रही सच्चाई पूर्ण खबरों को रोकने के लिए उन सबको अफवाह बनाकर उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए मोदी नए-नए षड्यंत्र रच कर प्रतिबंध लगाने के लिए आमदा है। यथार्थ में अघोषित आपातकाल जो सच समाचारों और संदेशों को रोकने को प्रतिबंधित करने के लिए जोकि न्यायालयों के माध्यम से लाया जा रहा है।

आने वाले चुनाव में अपनी बदनामी को रोकने के लिए लागू कर दिया गया है, क्योंकि मोटा भाई ने 2014 में जिस प्रकार से जनता को झूठे वादे किए जिसमें 15लाख रुपए हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आएंगे, एक करोड़ रोजगार दिए जाएंगे महंगाई कम कर दी जाएगी मनरेगा और एक दो रु कलिो का गेहुं चावल बेचना बंद कर दिया जाएगा। आतंक खत्म कर दिया जाएगा। 12वी तक शिक्षा मुफ़त दी जाएगी। विदेश में पड़ा सारा काला धन भारत ले आया जाएगा। परंतु इन वादों को पूरा करने के विपरीत, नोटबंदी और जीएसटी लगाकर चारों तरफ घोर हर तरफ तबाही मचा दी। 2 महीने तक 40 करोड़ लोग बैंकों की लाइन में खड़े होकर नोट बदलवाने के लिए परेशान होकर बेरोजगारी झेलते रहे। जिसमे 255बैक कर्मीयो की मौत हुई। नगदी के अभाव में देशभर में लगभग 2000 बड़े उद्योगों के बंद होने से लगभग 2करोड, 40लाख लघु उद्योग बंद होने से 5करोड से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए।

आखिर मोदी को यही प्रसार माध्यम इसे सोशल मीडिया का नाम दिया गया है Facebook WhatsApp ट्विटर इंस्टाग्राम पर झूठे मक्कारी पूर्ण वादे कर 2014 मैं चुनाव जिता कर लाई थी। अब क्यों इससे मोदी को डर लग रहा है जो उसे षड्यंत्र पूर्वक तरीके से बंद करने के लिए आमदा है।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

आधार कार्ड से आधार हीन बना दिया 100 करोड़ लोगों को, सरकार ने

गूगल की गुलाम है भारत सरकार, बकवास है गोपनीयता की दलीलें

सुंदर पिचई को मु.का.अ बना भारत के 132 करोड़ लोगों का, सभी मंत्रालयों का डाटा बेंच लाखों करोड़ की कमाई कर सकें

सरकारी अधिकारी चुंकि मोटा धन खा रहे हैं। इसलिए आधार कार्ड की प्रशंसा करते हैं। भारत शासन का अपना खुद का सरवर नहीं, सारी सरकारी सूचनाएं, जनता का डाटा, बैंकों का 300 करोड़ से ज्यादा खाते व ऋण के खातों का डाटा भी अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पास है। करोड़ों लोग ठगाए जा चुके हैं। ऊपर से सरकारी तंत्र चैलेंज करता है। कि हमारा सारा डाटा सुरक्षित है। जबकि कदम कदम पर आधार कार्ड को मोबाइल फोन से, बैंक अकाउंट से, गाड़ी के नंबर से, मकान नंबर से, एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़े होने पर आसानी से कोई भी हैकर और जालसाज मोबाइल नंबर के माध्यम से आधार कार्ड बैंक अकाउंट एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड आदि का नंबर जानकर रोज 3000 से ज्यादा लोगों में ठगी की जा रही है। हर बैंक का, सरकारी एप, सब गूगलप्ले के माध्यम से डाउनलोड होते हैं। कहानी वहीं से शुरू हो जाती है ठगी और लूट की जो मोबाइल में डले फोटो से लेकर सभी संपर्कों फोन नंबर डायरी, व्हाटसएप संदेश का डाटा लेकर उसका व्यवसायिक उपयोग करता है और सरकार के शुकरों की फौज हजारों करोड़ का कमीशन खाकर गुलाम बन देखती रहती है।

सरकार के सभी मंत्रालयों, बैंको, बीमा कंपनियों, विभागों से लेकर देश की 6 लाख से ज्यादा पंचायतों तक का, 100करोड आधार कार्ड तक का सारा डाटा गूगल के पास संग्रहित होता है। भारत सरकार का न अपना सर्वर डाटा केंद्र न अपनी व्यवस्थाएं सब तकनीकी आधार पर गुलाम है पूरा, अमेरिका सरकार तक परेशान है उसकी बदतमीजीयों से।

सभी केंद्र व राज्य शासित मंत्रालयों की सारी जानकारियां, यहां तक की भारत की सरकारी व गैर सरकारी सारी मोबाइल एप, जिसमें भीम भुगतान, सभी बैंकों के, सभी नगर निगमों, से लेकर निजी कंपनियों तक के गूगलप्ले से डाउनलोड होने से सारे उपयोगकर्ताओं का सारा डाटा, बातचीत, सारी निजी, वित्तीय, बैंको, प्राप्तियां व भुगतान, एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारियां, कैमरे व मोबाइल में लोड सारे चित्र, यहां तक की हर व्यक्ति

के आने-जाने, घूमने फिरने बात करने की सारी जानकारी मोबाइल से इकट्ठी कर हजारों करोड़ों रुपए प्रति माह में दुनिया की सारी कंपनियों को उपलब्ध करवाता है। यह गूगल के हरामखोर जालसाजों का अड्डा। सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की वो सारी जानकारियां जिन्हें सूचना के अधिकार में मांगने पर जिसे सरकार कानून में गोपनीय बताती है। उसके अधिकारी 90% जानकारी देने से मना कर देते हैं कि वह सूचना के अधिकार में नहीं दी जा सकती। परंतु वह सारी जानकारियां भुगतान खरीदी गोपनीय रिपोर्ट, जो भी कुछ कंप्यूटर पर, तैयार किया जाता है इमेल भेजे व प्राप्त करने आदि की सारी जानकारियां भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिकी सर्वर पर इकट्ठी होती रहती हैं। जिसे वहां के हरामखोर शूकरों की फौज भारत के घोर शत्रु राष्ट्र चीन, पाकिस्तान से लेकर भारत का व्यावसायिक उपयोग करने वाले पाखंडी मित्र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन व दुनिया के अन्य देशों व उनकी कंपनियों, हैकरों, आई एस आई एस जैसे मुस्लिम आतंकवादियों के गिरोह तक उपलब्ध करवाने से उन्हें कोई परहेज नहीं होता। अर्थात देश के लोगों को सूचना के अधिकार में जानकारी देने में भारत के केंद्र व सभी राज्यों के भ्रष्ट मंत्रालय, उनके सभी विभाग सभी सरकारी कंपनियां, निकाय, निगमो मैं बैठे घोर भ्रष्ट जालसाज मक्कार सभी अधिकारी जनता को जानकारी देने से साफ मना कर देते हैं बहनों का अंबार लगा देते हैं अपीलो की सुनवाई नहीं होती पर वही दूसरी तरफ सब कुछ, सारा रिकॉर्ड सारे दस्तावेज गूगल के माध्यम से पैसे खर्च कर प्राप्त की जा सकती है न केवल देश में, वरन दुनिया के हर कोने में आसानी से उपलब्ध हो जाती है पर सरकार को समझ में नहीं आता।

यहां तक की जब भी कोई सरकारी या गैर सरकारी Android मोबाइल पर उसकी एप गूगलप्ले से लोड करने की कोशिश की जाती है तभी Google उपयोगकर्ता से ना केवल विज्ञापन देखने वरन आपके मोबाइल में सभी संपर्कों की जानकारी से लेकर आपके मोबाइल में खींचे गए फोटो, बातचीत, WhatsApp Facebook Twitter आदि पर आई फोटो, आनेजाने घूमने फिरने, व अन्य कार्यों की जानकारी तक को संग्रहित करने जानने और उसका उपयोग करने की चेतावनी देता है और उपयोग करने की अनुमति मांगता है ना देने पर वह मोबाइल ऐप आपके मोबाइल पर डाउनलोड ही नहीं होता। यह अप्रत्यक्ष नोच खसोट का गिद्धों का अड्डा आप से अनजाने में आपकी हर गतविधि का भारी व्यवसायिक दुरुपयोग कर बच्चों से लेकर बूढ़ी महिला पुलिस पुरुषों को सरेआम नग्न करके रखता है।

यही नहीं सभी सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड के विवरण का भरपूर लाभ, मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों, बैंकों में बैठे जालसाजों से लेकर, पेट्रोल, डीजल, गैस विक्रेता, जहां-जहां लेन-देन कार्ड के माध्यम से किया जाता है। वह डाटा हर विक्रेता होटल एयरलाइंस टेलीफोन बिजली के बिल सभी के पास लिस्ट में सुरक्षित हो जाता है जो बाद में ठगी करने में आसानी से उपयोग किया जाता है सरकार नहीं रोक पाती है। नीचे एक जालसाजी कांड आधार कार्ड का अभी उत्तर प्रदेश में सामने आया। यही कांड पंचायतों के माध्यम से बैंक कर रही हैं ग्रामीण विकास का पैसा मजदूरों का पैसा सरकारी व के लोग इसी तरह मध्य प्रदेश में भी हजम कर रहे हैं।

अब एंड्राएड मोबाइल उपयोगकर्ता समझे कि अपने मोबाइल में कौन-कौन सी एप्लीकेशन लोड करके अपनी कौन-कौन सी जानकारी सार्वजनिक कर अपने आपको लुटवाना है। जैसा कि चारों तरफ दुनिया के हर कोने में हैकरो द्वारा जालसाजी और ठगी की जा रही है और सरकार उसकी सुरक्षा एजेंसियां, साइबर पुलिस, सभी बैंक पिल्लो की तरह कुकू करके चुप हो जाती है। केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय भी स्वयं जानती है, कि देश का सारा डाटा Google के पास संचित होता है और वह उसका भारी दुरुपयोग कर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच रहा है। इससे भारत का कोई भी केंद्र व राज्यों के सभी मंत्रालय, उनके सभी विभाग, सभी कंपनियों से लेकर भारत की 6 लाख के करीब पंचायतों, भारत के 132 करोड़ में से 120 करोड़ लोगों का आधार कार्ड का डाटा भी जिसमें उसके मोबाइल नंबर बैंक खाते गाड़ी का नंबर मकान नंबर घर का पता आदि सब कुछ Google के पास संचित है उसका वह ना केवल सदुपयोग कर दुनिया भर की कंपनियों, सरकारों से लेकर आतंकवादी गिरोह तक को बेच रहा है। इस प्रकार आम आदमी से लेकर सभी व्यवसाइयों कंपनियों तक सभी को सरे उनकी गोपनीयता को भंग कर आम चौराहे पर नीलाम करने पर तुला हुआ है। इसके विपरीत सरकार में बैठे भुखेरा जन पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी और उसके गिरोह कें अन्य मंत्री व सरकार में बैठे भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी हजारों करोड़ का कमीशन खाकर हर सेवा का उपयोग उस के माध्यम से ही करके सबकी गोपीनीयता को भंग करने पर तुले हुए हैं।

भारत कें सुंदर पिचाई को इसीलिए गूगल ने अपना मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया ताकि वह आसानी से मोटी रिश्वत मंत्रियों संतरियों को बांटकर आसानी से पूरे डाटा को अपने कब्जे में ले सके और उसके डाटा से लाखों करोड़ का फायदा कमा सके और कमा रहा है।

अमेरिकी व इंग्लैंड की सरकार ने Google, Facebook ट्विटर पर इस गोपनीयता भंग करने का हजारो करोड़ का अर्थदंड भी ठोका। साथ ही अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए दूसरी छोटी कंपनियों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर करना, ऊनके डाटा की व्यवसायकि जानकारी एकत्रित कर उन्हें हानि पहुंचाकर नष्ट करना आदि का दोषी पाकर 5 सितंबर को Twitter के जैक डोर्सी, Facebook की सी ओओ शेरलि सेंडवर्ग को खुलेआम अमेरिकी सीनेट में जवाब देने बुलवाया गया था। परंतु भारत भारत सरकार के सूचना मंत्रालय, गृह मंत्रालय की तो औकात ही नहीं कि वह उनकी जालसाजियों के विरुद्ध कोई निर्णय ले कोई ठोस कार्रवाई कर केंद्र व राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों विभागों, बैंको और जनता के डेटा की सुरक्षा कर सकें। यहां तो स्वंय केंद्र वह राज्यो की सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग Google की गुलामी करने पर तुले हुए हैं। उसे मोटा हजारों करोड़ का धन देकर, सैकड़ों ऐप और जानकारियां प्रबंधन का जिम्मा भी सौंप रखा है। धन्य हो ऐसे देश

आखिर 2019 के चुनावी खर्च अंबानी ही देगा इसलिए जनता से लूट जरूरी

पेज एक से जारी

तेल कंपनियों के पास था, वह ठेका सरकारी कंपनियों से लेकर रिलायंस को सौंप दिया गया। स्वाभाविक था रेलवे की और एयर इंडिया को ऊंची कीमतों पर पेट्रोल-डीजल मिलने से उनकी परिचालन लागत बढ़ गई उसकी भरपाई इस मोदी ने रेलवे के के यात्री किराए में 2 गुना से 10 गुना तक वृद्धि कर दी। रोना रोया गया की रेलवे प्रति किलोमीटर यात्री किराए में रु 2 की हानि भुगत रहा है। जबकि यह तो सामने दिखा गया। सरकारी जबकि उसने अनेक विभागों में बड़े मोटे मोटे सौदों में हर जगह अंबानी, अडानी, टाटा बिरला जैसों को मोटे कमीशन के लिए सरकार को घाटा पहुंचाते हुए सौंप दिए गए हैं।

यह खरीदी का सारा अधिकार मोदी की सरकार आते ही अंबानी को सौंप दिया गया था।

एकमात्र कारण छिछोरे बुद्धिहीन पूंजी पतियों की रखैल मोदी अंबानी अडानी टाटा प्रेम अब आप कहेंगे कैसे बहुत छोटी सी बात है देश में आने वाला सारा पेट्रोल खरीदी अंतरराष्ट्रीय मार्केट से क्रय करने का जो काम पहले सरकारी कंपनियां करती थी। जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वही सारा काम अब अंबानी न्यूनतम कीमतों पर करके अपनी रिलांयस की रिफाइनरी को देता है। और वह पेट्रोल डीजल गैस, आदि सभी पेट्रोलियम पदार्थों को २०% तक मोटे कमीशन पर सरकारी कंपनियों को आपूर्ति की जाती है। फिर उस पर केन्द्र व राज्यों की ड्यूटी व 28% वेट टैक्स के बाद भी म प्र में रु5 पेट्रोल और 4 डीजल व गैस प्रति लीटर वसूली।

अक्खां भारत जानता है कि सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम खरीद में खर्च होती है। भारत की। जिसमें मोटी कमाई अंबानी बंधु खरीद की उच्च कीमत दिखा कर बीच का मार्जिन$15 तक प्रति बैरल वो घोर धूर्तों की औलाद मुकेश विदेशों में अपने नये व्यवसाय में लगा देता है। पर इस तथ्य पर कोई मिडिया का सूकर मुंह नहीं खोलता । जबकि नुकसान विदेशी मुद्रा का सीधे सरकार का वित्त व पेट्रोलियम मंत्रालय से जनता को भुगतना पड़ रहा है।

दूसरे भूखे भेड़ियों मोदी ने मोटे कमीशन के चक्कर में और विदेश यात्रा में मौज मस्ती और शौक पूरा करने के लिए मोदी ने हीं विदेश में जाकर रूस, अमेरिका, जर्मनी, इजरायल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, व अन्य देशों से समय बाधित और पुराने हथियारों का कबाड़ा जिसमें लडाकू विमानों, मिसाइलों, तोपों, टैंकों राडार आदि खरीदा जिसमें देशी बिचौलिया अंबानी, टाटा जैसे अनेकों ने मोटा कमीशन हजम किया इसमें भी भारत की विदेशी मुद्रा ही गई।

फिर अंबानी अडानी व अन्य सैकड़ों देशी विदेशी पूंजीपतियों के फायदे के लिए की गई नोटबंदी और जी एस टी से एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी 14 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार होने के साथ 40 लाख से ज्यादा छोटे लघु उद्योग मोदी की नोटबंदी और जीएसटी के टैक्स के चक्कर में बंद हो गई इससे उत्पादन में भारी गिरावट आई और इसे विदेशों में निर्यात किए जाने वाले सामान में भी भारी गिरावट आई। निर्यात घटना और आयात बढने से रु की कीमत गिरी।

फिर $40-50 करोड का राफेल विमान जिसमें 60 % तक कंपनी के लाभ का हिस्सा भी था। जो कांग्रेस 540 करोड़ में खरीद रही थी। वह मोदी अंबानी की तत्काल बनी कंपनी के माध्यम से $ 1650करोड़ में खरीद रहा है। तो यह $ 44000 करोड़ भी तो विदेशी मुद्रा ही है। अभी वक्त है मात्र चीन से आयात व उसकी कंपनियों के भारत में ठेकों में 50% कम कर देने से विदेशी मुद्रा बचने से $ की कीमत रु55-60 के बीच आ जाएगी।

जनता आगामी त्योहारों पर मात्र दिसम्बर तक सारे चीनी माल का बहिष्कार कर देने मात्र से दिसम्बर तक $ रु 65 तक आ जायेगा।

आखिर सरकारी नौकरी में ही क्यों होती है, लिखित-मौखिक शारीरिक चपरासी, बाबु की परीक्षा

नेताओं का चुनाव पूर्व होना चाहिए, शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परीक्षण

विधान सभा लोक सभा देश की सत्ता के मानव चिड़िया घर नहीं, जहां अंगूठा टेक, अपराधी, बीमार अपाहिज पहुंचकर देश के 132 करोड़ों की सत्ता को हांक कर मनमर्जी से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशो तक की नियुक्ति अपने तरीके से करे। वहां चुनाव नामांकन से पूर्व ली जानी चाहिए प्रवेश परीक्षा ली जानी चाहिए, हर नेता की ।

किसी सरकारी विभाग में चपरासी बाबू या पुलिस में मिलिट्री में सिपाही बनने के लिए आपको न्यूनतम शिक्षा के आधार पर परीक्षा देनी होगी यदि आपने परीक्षा पास कर ली तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आपका मेडिकल होगा। आपको उस समय पूर्णतः स्वास्थ्य होना चाहिए। आप की लंबाई चौड़ाई नापी जाएगी। यदि आप सब में मापदंडों पर खरे उतरे व सफल रहे। तब आपको चपरासी बाबू या पुलिस या सेना में सिपाही या अन्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

इसके विपरीत आपने सैकडों अपराध किये हों, पूर्णतः चरित्रहीन हो। तुतलाते हों, सैकड़ों बीमारियों हों। अंगूठा टेक हों। अंधे हो। लूले लंगड़े हो। सजायाफ्ता हो। इन सब दोषों के साथ भी आप सरपंच, पार्षद, विधायक, महापौर, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं। जीतने पर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के लिए यह सारे दोष, कमियां, अयोग्यताएं, यह आप के दुर्गुण नहीं। यह आपके सद्गुण कहलाएंगे। जनता कि आप ज्यादा सहानुभूति बटोर कर चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और आप चुनाव आसानी से लड़ सकते हैं। ये जीतकर जहां आपको चपरासी, बाबु, सिपाही बनने से रोका गया था। उस विभाग के मंत्री बन सकते हैं। मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद यह सार्वजनिक संपत्तियों सड़क बिजली पानी नदिया पहाड़ जमीनी जनता की सारी जमीनें संपत्तियां और जनता की बैंको मे सारी जमायें, सरकारी खजाने सरकारी सहकारी बैंकों मैं जमा संपत्तियों के आप मालिक बन जाते हैं। सब अपने बाप की जागीर समझ कर जैसे चाहे वैसे उपयोग करें विदेश यात्रा करें। विदेशों में जाकर अय्याशी मोज मस्ती करें। देश की सार्वजनिक व प्राकृतिक संपत्तियां गिरवी करें, बेंचें।

देश की संपत्तियों को लूट कर पैसे को विदेशी बैंकों में जमा करें वह अपनी होटलें खोलें। अपने बच्चों के बाजार अपने मित्रों के व्यापार के लिए देश को बर्बाद करें और अपने इंन दुष्कर्मों को छुपाने के लिए जन धन से बस हर दिन हजारों करोड़ के विज्ञापन समाचार पत्रों में आपकी तारीफों के छपवाते रहें।

देश का बिकाऊ भड़ुवों और भांडो की फौज मीडिया जनता को सच्चाई से दूर भ्रमित कर झूठे रंगीन सब्ज बाग घुमाता रहेगा। भेड़ों का झुंड रूपी जनता को जैसा वो सत्ताधीश हांकेगे वह चलेंगे और फिर उन्हीं को चुनेंगे।

इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यक है कि सरपंच से लेकर सांसद तक सब की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं निश्चित की जाये वरन किसी भी चुनाव लड़ने से पूर्व उसकी भी नियमानुसार लिखित परीक्षा हो, उसकी भी शारीरिक मानसिक योग्यता व चिकित्सीय परीक्षण चुनाव आयोग की निश्चित संस्था द्वारा किया जाना चाहिए। उनका भी पुलिस से चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए यदि के ऊपर भी कोई अपराध हो। तो किसी भी कीमत पर मत चुनाव न लडे। ताकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंगूठा टेक, गुंडे मवाली, अपराधी बीमार अंधे लंगड़े लूले और शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति सत्ता में पहुंचकर 132 करोड लोगों के देश की सत्ता को भेडियों का झुंड नोच खसोट कर खाने रु 25-25 लाख का सूट पहनकर खाने सत्ता में आते ही अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह हजारों करोड़ की लागत के हवाई जहाज लेकर विदेश यात्राओं में जनता के धन को बाप की जागीर समझ कर लुटाने ना निकल सकें।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

मोदी और शाह का ईवीएम की जालसाजी से चुनाव जीतने का अहंकार, सिद्ध करता है

पुनः ईवीएम की जालसाजी से जीत लेंगे 18-19 के चुनाव

बेशक जिस तरह से अगडे पिछड़े हिंदुओं में कानून के माध्यम से पूरे देश में गृह युद्ध करवाने की तैयारी की गई है। उसका मूल उद्देश्य यही है। कम से कम एससी एसटी के 32 परसेंट वोट पूरी तरीके से प्राप्त हों। बाकी सारा खेल वो ईवीएम की जालसाजी के साथ बिना मशीनों से प्राप्त मतों की गणना को ऑफिस एक्सल शीट में डाले बिना और बिना पूरी मशीन खुले ही यहां बैठे जालसाज घोर मक्कार सहायक, उप जिलाधीश, जिलाधीश को उनकी इच्छा के अनुसार पोस्टिंग व लूट का मौका देकर पिछली बार की तरह पुनः प्रदेशों व देश की सत्ता पर कब्जा किया जाए। इसके लिए अभी हर जिलाधीश कार्यालय में सारे घोर भ्रष्ट, जाल साज और धूर्त अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी गई है। या वे पिछले 5-8 सालों से एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। इंदौर में जो कलेक्टर था। आकाश त्रिपाठी इंदौर में ही पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी का प्रबंध संचालक बन कर बैठा हुआ है। 5वर्ष पूर्व का जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष सिंह इंदौर नगर निगम में आयुक्त बनकर बैठा हुआ है। 8 वर्ष संदीप सोनी एडीएम जो पुर्व में कलेक्टर ऑफिस में था। वह भी इंदौर नगर निगम में ही बैठा हुआ है।

मप्र का घोर भ्रष्ट, जालसाज पूर्व प्रधान सचिव ओ पी एस रावत, जो वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त है। आखिर सरकार की कृपा से ही चूंकि शिवराज को अपने कार्यकाल में काफी धन कमा कर दिया। इसी वफादारी को ध्यान में रखकर सेवानिवृत्ति के बाद उसे शिवराज ने केंद्र में भेजकर मुख्य चुनाव आयुक्त बनवा दिया गया ताकि सरकार की हर जालसाजी और भ्रष्टाचार में वो आंख मीच कर हां में हां करता रहें।

पूर्व के मुख्य चुनाव आयुक्त जब टी एस कृष्णमूर्ति ने हीं इस बात को दिल्ली में स्वीकार कथिा कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम की हैकिंग से राज्यों के चुनाव जीते हैं। सभी विपक्षी दलों को चाहिए कि वह ईवीएम मशीनें हटवाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए ताकि ईवीएम हैकिंग की जालसाजी से एक तरफा जीत को रोका जा सके उस पर वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त रावत ने नई दलील पेश करते हुए पुनः भाजपा सरकार को जिताने के लिए कह दिया की वेलेट पेपर से चुनाव करवाना संभव नही। उसमें उसमें बूथ कैप्चरिंग करते हैं और बहुत साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त रावत हर हाल में ईवीएम से ही चुनाव करवा कर आसानी से हैकिंग कर भाजपा को जितवाकर अपनी भ्रष्टाचार और जालसाजी पूर्ण कार्यशैली से अपनी वफादारी सिद्ध कर सेवानिवृत्त होने के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने और सभी प्रकार के सत्ता सुख और मोटी कमाई का अवसर देने का एहसान उतारना चाहते हैं।

17 नवंबर 18 को भिंड जिलाधीश कार्यालय में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग मैं जब ईवीएम मशीन को जांच रहे थे। तो उन्होंने दो बार बटन दबाया और उसमे से दोनों बार बीजेपी की पर्ची निकली जिससे क्षुब्ध होकर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत भोपाल और दिल्ली में की तत्काल वहां से जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक के साथ 19 अधिकारियों को वहां से तत्काल हटा दिया गया। ऐसी ही गड़बड़ियां, न केवल मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मिजोरम, आदि के विधानसभा चुनावों में की ही जाएंगे यह सारा खेल सभी प्रदेशों के जिलों के जिलाधीश द्वारा जानबूझकर करवाया जाता है जिसकी 99% जांच न होने के अभाव में वह अपने षडयंत्रों में सफल हो जाते हैं। इसके बदले में सत्ताधीश पार्टी द्वारा उन्हें मनचाही पोस्टिंग से लेकर, जलसाजीयां, वाह हर प्रकार के भ्रष्टाचार करने की

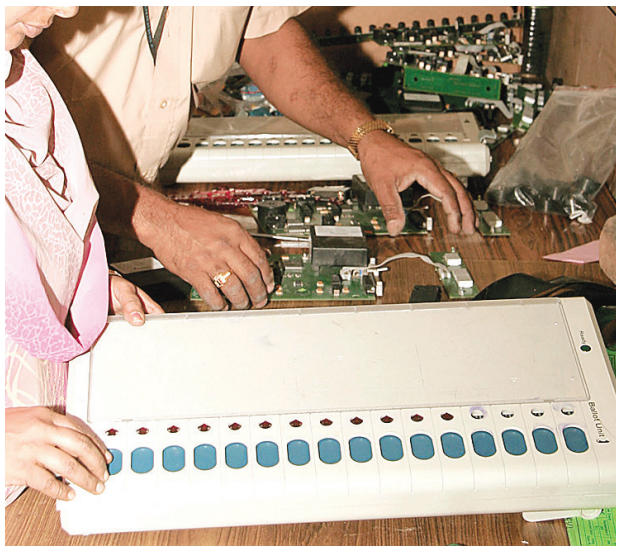

जमीनों की उठापटक करने से लूटने की पूरी छूट दी जाती है।

इसके बारे में अरविंद केजरीवाल, और दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने इसकी शिकायत की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा की आखिर चुनावी मशीन की गड़बड़ी में वोट किसी के भी हो केवल भाजपा को ही जाते हैं। यदि सचमुच में गड़बड़ी हुई है। तो किसी अन्य पार्टी को भी बोट क्यों नहीं मिलते । वैसे इस बात को समयमाया समाचार पत्र पिछले 12 सालों से लगातार उठा रहा है। जब से देश में चुनाव ईवीएम से किए जाते। क्योंकि वह जानते हैं कि इसमें आसानी से फर्जीवाड़ा किया जा सकता है तो फिर भारत में ही चुनाव ईवीएम से करवाने की सत्ताधीशों की जिद के पीछे पूरी जलसाजिया छुपी हुई है। वह जानते हैं कि हम ईमानदारी से किसी भी हाल में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यही बात दिग्विजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने दोहराई।

सभी विपक्षी दलों को चाहिए कि वह किसी भी हाल में ईवीएम से चुनाव ना होने दें क्योंकि उसे आसानी से ब्लूटूथ, जीपी आरएस, जीपीएस, वायरलेस लोकल लूप, रिमोट, वाईफाई आदि से न केवल ऑपरेट किया जा सकता है। वरन वीवीपीएट जैसे दिखाउ प्रणाली में भी पर्ची में कुछ भी प्रिंट करके दे देंगे परंतु अंदर आसानी से उसे परिवर्तित व मनचाहे परिणाम लिए जा सकते हैं। यह बात मशीन को बनाते समय उसमें पूरी तैयारी से बनाई गई है। मतदाता नोटा पर भी बटन दवा देगा। तो भी अंत में तो इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जो भाजपा की जीत को पक्का कर फिर सत्ता सौंप देंगे।

भविष्य में होने वाले चुनाव में इवीएम और बीवीपेट वैसे तो रेडियो से नियंत्रित संचालित होती है।

जिसे कोई रोक नहीं सकता ।बाद में जहां पर वह संग्रहित करके रखी जाती है। उसके चारों तरफ सभी राजनीतिक दलों को जामर लगवाने की व्यवस्था भी करवानी चाहिए।

साथ ही मशीनों के सीधे प्रिंटर से कनेक्ट होना चाहिए। हर मशीन खोलने के पहले जिस प्रकार से सत्यापित करवाकर दिखाई जाती है उसी समय उसे प्रिंटर से भी कनेक्ट करना चाहिए।

ताकि मशीनों को खोलकर दिखाते समय प्रिंटर पर भी सीधा प्रिंट होकर हर प्रिंटेड पेपर मशीन से सीधे हर प्रत्याशी को तत्काल दिया जाना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से यह कहा अवश्य जाता है। परंतु ऐसा कभी होता नहीं ताकि हर प्रत्याशी का रिजल्ट मशीन से निकलने के साथ हीं देखा भी जा सके।

जबकि मशीन खोलने के समय प्राप्त मतों की संख्या हर उम्मीदवार को और मशीन खोलने वाले अधिकारियों को हाथ से लिखनी पड़ती है। फिर हाथ से लिखी हुई हर मशीन की प्रत्येक उम्मीदवार हर टेबल से हर राउंड की ऑफिस एक्सल शीट में डालकर हर उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या दिखाई जानी चाहिए जो कभी नहीं होता और यहीं से थोड़ा जालसाजी का मतगणना में कांड होता है जहां मन चाहे उम्मीदवार को वहां के अधिकारी आसानी से जिता देते हैं ।

आखिर क्यों और कब तक ये जालसाजियां जिलों के जिलाधीशों द्वारा अपने अंतर्गत कार्यरत उप जिलाधीश, सहायक जिलाधीशों, के साथ 90 से ज्यादा शासकीय विभागों के जिला अधिकारियों सहायक जिला अधिकारियों के माध्यम से सत्ताधीशों के लिए करवाई जाती हैं। जीते हुए अन्य उम्मीदवारों को हारा हुआ दिखा कर बाहर कर दिया जाता है। उसके कहने या उसके समर्थकों द्वारा आपत्ति उठाने पर मारपीट की जाती है। और अंत में सत्ताधीश पार्टी के उम्मीदवार को जीता हुआ दिखा दिया जाता है।

इन्हीं धूर्त मक्कार अधिकारियों द्वारा यह कांड हर जिले में प्रदेश में और देश में होते रहे हैं।

बड़ी-बड़ी चैनल और समाचार पत्रों के पत्रकार भी यह सब सामने होते देखकर भी चुप रहते हैं। क्योंकि उन्हें मोटे 5-5 पेज के विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में व 1-2 घंटे की विज्ञापन व प्रशंसा के समाचार स्लाट सत्ताधीश सरकार के विरुद्ध ना लिखने और छापने के लिए ही मिलते हैं।

कब रुकेंगी ये जालसाजीयां।

चुनाव आयोग तो केवल चुनावी नौटंकी की औपचारिकता क्षेत्रीय व देश की जनता को दिखाने और दुनिया के सामने अपने आपको सच्चा ईमानदार दिखाने के लिए की जाती है।

जबकि चुनाव आयोग जिसका अंतिम बिंदु जिले का प्रभारी प्रतिनिधि कलक्टर होता है वही सारे खेल करता है।

आखिर क्या तकलीफ है कागज के मतपत्र से चुनाव करवाने के लिए यदि चुनाव में ज्यादा खर्च होता भी है तो देश का पैसा देश के ही अन्य लोगों के काम भी तो आता है ।

उसमें भी तो मोटी कमाई कलेक्ट्रेट के अधिकारियों से लेकर चुनाव आयोग को भी होती है।

निसंदेह रुपए दो 3000 की मशीन 5 से 10लाख रुपए में खरीदने पर मोटा कमीशन मिला। चुनाव आयोग से लेकर वित्त व विधि मंत्रालय के कर्मचारियों अधिकारियों को जो हजारों करोड़ में होगा।

यह तो देश की सरकारी खरीद का दस्तूर है।

फिर मशीन का मदर बोर्ड वह भी तो विदेशी कंपनी से आयात करना पड़ा ना।

फिर मशीनों का निर्माण सत्ताधीशों की इच्छा, निर्देश और आवश्यकता के अनुसार ही तो करेगी उत्पादक कंपनी।

बुद्धिजीवी पत्रकार इन तथ्यों पर भी ध्यान दें।

आखिर इन ईवीएम से चुनाव कनाडा फ्रांस जर्मनी जापान इंग्लैंड अमेरिका आदि में क्यों नहीं होते इन्होंने आखिर क्यों उसे लागू नहीं किया।

यह सब जानने समझने के लिए प्रस्तुतकर्ता ने 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और यह सब अनुभव वहां से चुनावों का कड़वा सच वहां से इकट्ठा किया है।

त्योहारों पर जनता को चाहिए सोच समझ कर खाद्य वस्तुओं की खरीदारी करें

पैकेज्ड फूड को त्यागे और खुला सामान छोटे दुकानदारों से खरीदें देखभाल कर

यूरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारत की 132 करोड़ आबादी से कमाई के लिए कैसे षड्यंत्र रचे हैं। इसका अंदाज आम आदमी तो दूर सरकार को भी नहीं है। एक तरफ रसायन व कीटनाशक युक्त खाद्य पदार्थ जिसमें चॉकलेट बिस्कुट से लेकर पेय पदार्थ तक शामिल है जनता को बेचकर बीमारियां भी साथ दे रहे हैं और उन बीमारियों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में दवाइयां बेच रही हैं इस प्रकार से हर तरह से जनता को लूटा जा रहा है। बदले में खाद्य निर्माता एवं पेकर व औषधि निर्माता बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सरकार में बैठे मंत्रियों से लेकर उच्चाधिकारियों तक मोटा कमीशन बांटा जा रहा है।

वर्तमान में भारत में शॉपिंग मॉल के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना पैकेज देसी खाद्य पदार्थों जिस में आटा, दाल चावल, तेल, घी, मसालों आदि से लेकर चटनी अचार तक बिस्कुट चॉकलेट नमकीन आदि तक सब कुछ मनमानी कीमतों पर घातक रसायनों व कीटनाशक युक्त खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं जो एक तरफ आमजन में भारी घातक बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सरकार उनके फायदे के लिए उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निर्मित औषधियों संसाधनों आदि का उपयोग करने के लिए आयुष्मान योजना लागू कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से जनता को ठग कर क्योंकि उस आयुष्मान योजना का बीमा प्रीमियम जनता के धन से अपने खास अंबानी की रिलायंस हेल्थ केयर इंश्योरेंस को लाखों करोड़ में देगा।

बेशक इसका अंदाजा केवल उन धूर्त भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों को ही भर है जिन्होंने इसमें मोटा कमीशन हजारों करोड़ का खाया है एक तरफ बहुराष्ट्रीय खाद्य निर्माता कंपनियां जिसमें चॉकलेट बिस्कुट पिज़्ज़ा, ठंडे पेय जिसमें कोका कोला पेप्सी व अनेकों प्रकार के फ्रूट जूस जो पैकेज्ड किए जाते हैं व अन्य वस्तुएं हैं। जिनमें एंटीफंगल एंटी जरमेटिक अत्यधिक धीमा कीटनाशक मिला कर जनता को खिलाया पिलाया जा रहा है।

जिसे हमारी नव धनाढ्य युवा आबादी बड़े चाव से सेवन करती है और दूसरी तरफ गहन गंभीर बीमारियों को आमंत्रित कर किडनी लीवर हृदयाघात से लेकर चर्म रोगों को आमंत्रित कर रही है।

जिससे विशेष प्रकार की बीमारियां हों और बीमारियों के इलाज के लिए वहीं यूरोपीय कंपनियों की लाखों करोड़ की दवाएं भारत में आसनी से बिक सकें।

इन सब की सुरक्षा के लिए अकेले वॉलमार्ट अमेरिकी कंपनी ने हीं $ 550 करोड़ डॉलर, इसके साथ हिंदुस्तान लीवर, इंडियन टोबैको कंपनी, रिलायंस, टाटा, बिरला आदि लाखों करोड भारत में सन 2005 में सत्ताधीश पार्टी कांग्रेस को दिए थे और बदले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 लागू करवाया था बेशक सारे उस समय के लोकसभा 543 और राज्य सभा सांसदों में हर को 600 से 700 करोड़ रुपए हाथ में आए थे। जिसकी कोर कमेटी के विपक्षी सदस्य के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज भी शामिल था।

उद्देश्य था देश के सारे छोटे खाद्य पदार्थ निर्माता विक्रेताओं को खत्म कर देश की सारी मंडियों छोटे बाजारों को समाप्त कर दिया जाए। किसानों की जमीन हड़प ली जाए। सारा व्यापार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में हो।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सारी कृषि की खाद्य फसलों पर पकड़ गांवों से लेकर देश के पूरे खाद्य बाजार पर हो।

पैकेज्ड फूड प्रणाली को बड़े शॉपिंग मॉल के माध्यमों से देश की जनता पर थोपकर लाखों करोड़ों रुपए हर महीने कमाया जाए। पर इस कानून के संबंध में सन् 2006 मे मुझे खाद्य व औषधि विभाग के जान पहचान के निरीक्षकों ने बुलाकर मुझे वह एक्ट को पढ़ने और समझने के लिए दिया। उसको पढ़ने के बाद मैं उसके खिलाफ लगातार 12 साल से लिख रहा हूं। मैंने अपने समयमाया समाचार पत्र और www.samaymaya.com की साइट से इस सच को सन 2006 से पूरी दुनिया में उछालना और प्रकाशित करना शुरू किया। जिसके शुभ परिणाम भी रहे कि सन 2011 तक सरकार उस कानून को लागू नहीं कर पाई ।

दूसरी तरफ आज तक छोटे बाजार सरकारी कृषि उपज मंडीयां भी जीवित है।

बेशक स्मार्ट सिटी की आड़ में देश के लाखों ठेलों पर व्यापार करने वालों के ठेले इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने, तोड़े गए।

उन्हें मारा पीटा गया छोटी दुकानें मंडियां साफ कर दी गई।

करोडो को बेरोजगार करने की कोशिश की गई नोटबंदी और जीएसटी से।

मोदी सरकार ने केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यापार को बढ़ाने और उनसे हजारों करोड़ का कमीशन खाने के लिए।

इस लेख का उद्देश्य है, कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्र को समझ पैकेज्ड फूड का जनता इन त्यौहारों पर भी त्याग करें। और बाजार से सामान छोटे दुकानदारों से खुला हुआ देख व जांच परख कर खरीद कर अपने घर में ही सारे पकवानों का पारंपरिक तरीके से निर्माण करें।

स्वयं व परिवार के साथ और अपने रिश्तेदारों मित्रों के बीच स्वास्थ्य को बनाये रख करआनंद लें।

हर हाल में पैकेज्ड फूड के समयबाधित विषाक्त दूषित खाद्य पदार्थों से परिवार बच्चों को बचाने के साथ अपने रिश्तेदारों और इष्ट मित्रों को भी बचाएं।

इन सबके साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को, गरीब छोटे विक्रेताओं को लाभार्जन करवाकर उनके परिवारों को चलाने बच्चों को पढ़ाने में अपना सहयोग दें। ताकि वे भी सुखी और समृद्ध जीवन जी सकें।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

म प्र वाणिज्य कर में, 60% अधिकारी 5 से ज्यादा बरसों से एक ही स्थान पर

सभी घाघ अधिकारी पांच साल से ज्यादा पुराने, करेंगे चुनावी कार्य

इंदौर में उपायुक्त संभाग 3 का भ्रष्ट अब्दुल मजीद 8 साल से ज्यादा समय से, ए के जोशी, धर्मपाल शर्मा, आरके शर्मा, 5 साल से, सहायक आयुक्त दीपक श्रीवास्तव, निनामा, बाधवा, रुबी रघुवंशी, विनीता जैस, पूर्णिमा चौरसिया, वाधवा, पारुल अग्रवाल व अन्य अनेकों अधिकारी जिसमें निरीक्षकों, सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों, से लेकर, वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक आयुक्त व उपायुक्तों तक हर वृत, संभाग आदि में कुंडली मारे बैठे हैं।

50 से ज्यादा वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक आयुक्त उपायुक्त पूरे मध्यप्रदेश में 5 साल से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर बैठे रहकर, भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में भोपाल में सहायक आयुक्त विशाल मेडा रु 50000- की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस द्वारा पकड़ा गया। बेशक जीएसटी के लग जाने से अधिकांश अधिकारियों के पास काम नहीं है। उनका काम करने में मन भी नहीं लग रहा है। जहां तक उपायुक्त संभाग 3 अब्दुल मजीद 8 साल से एक ही स्थान पर बैठे रहकर जो कि चेतक चेंबर में लग रहे दो एंटी इवेजन, दो उपायुक्त, और 14 वृत्त कार्यालयों का और पर 25 लाख से ज्यादा का महीने का किराया चुका रहा है।

उसमें सीधा 10% का कमिशन हजम किये जाने के कारण एक तरफ अफीम गोदाम की जमीन पर वाणिज्य कर का कार्यालय नहीं बनने दे रहा है। तो दूसरी तरफ घोर भ्रष्ट यह अधिकारी सूचना के अधिकार में जानकारी तो देता ही नहीं। साथ में अपील लगाने पर बिना सुनवाई के अपील की एकतरफा कार्रवाई कर हरामखोर रद्द कर देता है। यह भी सच है।

सूत्रों के अनुसार की उस कमीशन मै से हिस्सा आयुक्त को भी जाता है इसलिए चेतक चेंबर के 100 से ज्यादा कमरों में चलने वाले कार्यालयों में परेशान होने वाले 300 से ज्यादा कर्मचारी वा अधिकारी पिछले 15 सालों से ज्यादा समय से परेशान है पर ये भ्रष्ट हरामखोर अपना शेरू हिस्से डकार कर चुप हैं। फिर इन जालसाजों ने नया कार्यालय बनाने के लिए अपनी अफीम गोदाम की जमीन छोड़कर जमीन भी देखी तो शहर से 10 किलोमीटर दूर बाईपास के पास उसका नाम सुनकर कर्मचारी और अधिकारी बीच शहर से जंगल में जाने की अपेक्षा चुप रहना बेहतर समझा।

अभी भी पुराने वैट अधिनियम में धारा 14, 34, 54 अंतर्गत कर निर्धारण में कमाई में जुटे हुए हैं। निसंदेह नई जीएसटी में उनके पास काम ही नहीं बचा। अधिकांश काम ऑनलाइन हो जाने से बाबू से लेकर उपायुक्त अपरआयुक्त तक अधिकांश काम खत्म हो चुका है। जीएसटी मैं चोरी थोड़ी कम हुई है यह बात सही है पर इसके विपरीत क्योंकि अभी कानून नया है इसलिए व्यापारियों निरीक्षकों अधिकारियों को ज्यादा कुछ बारीकियां समझ में अवश्य नहीं आई है। परंतु आने वाले समय में इसकी बारीकियां और उसके कर चोरी करने के छेद फिर वही कुल व्यवसायिक खरीद बिक्री की कर राशि वही 40-50% से ज्यादा नहीं आएगी।

अब मोदी कंगाल करेगा रिजर्व बैंक

पेज एक से जारी

क्योंकि ये आपातकाल नोटबंदी, जीएसटी और मोदी जी के दोस्तों के 20 लाख करोड़ के गैर उत्पादित ऋणों या डूबंत की वजह से आई है।

शेष पेज 9 पर

2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत सरकार को इमरजेंसी का बहाना देकर रिजर्व बैंक के पैसे हथियाने की जरूरत नहीं पड़ी तो मोदी जी तो सिर्फ पैट्रोल-डीजल पर देश की जनता से 12 लाख करोड़ ज्यादा वसूल चुके है, दूसरी लूट के पैसे अलग, फिर भी मोदी जी को रिजर्व बैंक के 3.70 लाख करोड़ चाहिए?

ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है?

अब अगर RBI का पैसा गया तो उसे भी मोदी जी वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे देश की तिजोरी के सारे पैसों को किया। सारा पैसा धन्ना सेठों की जेबों में जायेगा। पर उससे भी खराब बात ये होगी कि रिजर्व बैंक जिस काम के लिए बनी है वो काम नहीं कर पायेगी। ये कितना खराब होगा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अम्बानी का आदमी उर्जित पटेल, जिसे खुद मोदी जी ने रिजर्व बैंक गवर्नर बनाया था वो इसे रोकने इस्तीफा देनेकी धमकी दे चुका है।

अगर ये हुआ तो मार्किट और रुपये की गिरावट छोड़ो,रिजर्व बैंक पर से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा। ये भरोसा बनाने में देश को 70 साल लगे है, ये सेकिंडो में खत्म हो जाएगा।

ये रफाल से बहुत बड़ा कांड है पर सवाल सिर्फ 1 है। मोदी सरकार पिछली सारी सरकारों से कई गुना अधिक रुपया जनता की जेबों से काट रही है, चाहे GST या कई सारे टैक्स-सेस के बहाने या पैट्रोल-डीजल पर हो रही लूट के जरिए, तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? योजनाओं की तो सिर्फ घोषणाएं होती है, किसी योजना में तो पैसा खर्च नहीं हो रहा। अगर खर्च हो रहा है तो सिर्फ पब्लिसिटी पर। फिर सारा पैसा जा कहाँ रहा है?

ये पैसा 3 गुना दाम पर खरीदे रफाल के जरिए अम्बानी की जेब में जा रहा है। ये पैसा बैंकों के जरिए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या की जेब में जा रहा है। ये पैसा IL&FS के जरिए संदेसरा और राकेश अस्थाना की जेब में जा रहा है। ये पैसा गैर उत्पादित ऋणों या डूबंत जरिए रुइया, अडानी, टोरेंट, जिंदल की जेबों में जा रहा है। ये सब ऑन पेपर है, सब को दिखता है जो देख-समझ सकता है। क्या हुआ ग्वालियर भोपाल फिल्म शोर के हो गई जोकर सूची सामग्री यदि गया है सुबह से 1000 जीआईएफ रोज को हजारीबाग

क्या यही है नया भारत? ये है विकास? ये सब ऐसे ही चलते रहना चाहिए? असली विकास की जगह सिर्फ विकास की जूठी पब्लिसिटी ही चाहिए देश को? इस पब्लिसिटी के लिए देश के गरीबों और मध्यम वर्ग से दुगना टैक्स लूटा जा रहा है?

आखिर जिस उदित पटेल को जोकि कीन्याई नागरिक है। अंबानी का जीजा को लाकर पहले रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया और जब उसने इन धूर्तों चीटली और मोदी के इशारे पर नाचने व उनको रुपए साडे तीन लाख करोड़ देने से मना कर दिया।

ताकि बैंकों की जमा पूंजी को जो उन्होंने मोदी के आकाओं अंबानी अडानी टाटा बिरला व अन्य सैकड़ों को दिए थे को डूबंत ऋण मानकर समाप्त करने और उसकी भरपाई करने रिजर्व बैंक से धन देने के लिए दबाव डाला गया जिससे पूरी रिजर्व बैंक भी कंगली हो जाएगी और देश की हालत दिवालिया इसलिए उर्जित पटेल ने धन देने से मना किया तो उसको हटाने और इस्तीफा देने के लिए दबाव बना रहा है। महा मक्कार और घोर धूर्त मोदी और अरुण चीटली।

मोदी आखिर यह माल रेलवे का नहीं जहां स्टेशन पर चाय बेचने के बहाने यात्रियों को भी लूटो और रेलवे की संपत्ति भी चुरा कर बेचकर गहने बनवा लो। फिर उनकी भी चोरी करके घर से भाग जाओ ताकि बाप रूपी जनता यहां पर भी कंगाली से दम तोड़ दे।

जितना 65 साल में जमा हुआ उसका आधा 4 साल में स्विस बैंक में जमा किया गया

पेज एक से जारी

पूरे देश में पेट्रोल की आपूर्ति के लिए विदेशों से क्रूड आयात करने के सारे ठेके अंबानी बंधुओं को हाथ में सौंप दिए गए। जो प्रतिदिन सारी खरीदी पर 10 से 20% कमीशन हजम कर विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं। यही कारण है। की अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड की कीमत $30 आ जाने पर भी देश में रु70 से कम पेट्रोल नहीं बेचा गया और वर्तमान में 85 से रु95/- तक वसूला जा रहा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत 75 से $80 पर चल रही है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 50 करोड लोगों के स्वास्थ्य बीमे की ढाई लाख करोड़ की बीमा प्रीमियम एक मुफ्त अंबानी बंधुओं के बीमा कंपनी को दे दी जाएगी। सरकारी बैंकों, बीमा कंपनियों, तेल कंपनियों, बिजली कंपनियों, सरकारी स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों, चिकित्सा, अभियांत्रिकीय, प्रबंधन, महाविद्यालयो आदि को बर्बाद करने उनमे बेरोजगारी बढ़ाने किस तरीके से कदम कदम पर छल कपट जालसाजी की जा रही है यह आम आदमियों को समझ में नहीं आ रहा। सत्ता संभालते ही मोदी ने हीं 100 से ज्यादा देशों की यात्रा में 10 लाख करोड़ से ज्यादा बर्बाद किया। जिस में जाने के पूर्व बड़े देशों में मीडिया पर साथ ही होर्डिंग बैनर आदि पर हजारों करोड़ अपनी प्रशंसा और वाहवाही छपवाने के लिए बांटा जाता रहा।दूसरी तरफ अमेरिका फ्रांस रूस आदि से देश की रक्षा के नाम पर पुराने हथियारों का 1-2 पर्सेंट की कीमत का कबाड़ा, वह हथियार, मिसाइल, जोकि उन देशों में पुरानी बेकार और समय बाधित हो चुकी थी खरीदा गया जिसमें राफेल फ्रांस का जो कि मात्र 25 से 50 करोड़ रुपए का था उसे कांग्रेस 5:30 सौ करोड़ में और भूखेरा जन पार्टी 1650 करोड में अंबानी के माध्यम से खरीद रही है। वही हाल $400 रशियन मिसाइल का भी है। जोकि 40 हजार करोड़ में 8 खरीदी जा रही है। उच्च शक्ति इंजन के अतिरिक्त क्या होता है विमानों में। मिसाइल में भी जोकि 5000 करोड़ रुपए में ली जा रही है। अखिल भारत की ब्रह्मोस पृथ्वी आदि मिसाइलों को विकसित क्यों नहीं किया जाता क्योंकि वहां से कमीशन नहीं मिलेगा।

भारत का मोदी सबसे पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो 10वीं पास भी नहीं। घोर झूठा, जाहिल, लालची मक्कार और भुखेरा, जो 12-13 साल की उम्र मैं घर से मां के जेवर चुराकर भागा, से लेकर तीस 32 साल तक की उम्र गुंडे मवालीओं के बीच गुजरी इसलिए पढ़ने लिखने का सवाल ही नहीं था। जिसने जो अपनी युवावस्था में सीखा व ग्रहण किया होगा वही वह इस उच्च पद पर आकर जनता को, जाहिलता और गवारु पन से पूंजी पतियों की शरण बैठकर उनके लाभ के लिए, जनता को बर्बादी भर दे सकता है।वह पिछले 4 साल में भरपूर दी देश की जनता को। वह कोई अर्थशास्त्री, कोई विषय विशेषज्ञ कुछ भी नहीं बस। छल कपट झूठ मक्कारी से परिपूर्ण भाषण देने की कला जो उसने 30-32 साल की उम्र से संघ के कार्यालय झाड़ू पोंछा और सफाई करने की आड़ में बड़े नेताओं की चड्डी बनियान और कपड़े धोकर जो सेवा के बहाने सबके राज इकट्ठे कर बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर पहले गुजरात में विधायक का टिकट हाथिया,और येन केन प्रकारेण जीत हासिल कर गुजरात का मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री बनते ही बड़ी पूंजी पतियों इसमें टाटा बिरला अंबानी अदानी आदि को उनके व्यवसाय में हर प्रकार की छूट देकर हजारो करोड़ की भारी वसूली कीऔर संबंध मजबूत किए। सभी समाचार पत्रों न्यूज चैनल, फेसबुक ट्विटर गूगल व्हाट्सएप आदि को हजारो करोड के भारी विज्ञापन बांट अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदारसिद्ध कर दिया। फिर इसी तरह केंद्र के नेताओं को ब्लैकमेल कर सांसद से सीधा प्रधानमंत्री बन गया।

फिर जैसा कि एक भूखे आदमी को सत्ता मिलते ही वह है जन धन पर टूट पड़ता है। वैसे ही उसने सत्ता संभालते ही दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में शाही अंदाज में जनता का लाखों-करोड़ केवल उन देशों में जाने से पहले वहां के समाचार पत्रों टीवी न्यूज चैनल सोशल मीडिया के साथ होर्डिंग बैनर पोस्टर आदि पर ही हजारों करोड़ खर्च कर दिए ताकि वहां का मीडिया मोदी की झूठी वाह वाही व प्रशंसा और छाप व प्रसारित कर, वहां की सत्ता व लोगों का ध्यानाकर्षण करें।

यथार्थ में मोदी हर देश की यात्रा पर अदानी अंबानी टाटा बिरला आदि का व्यवसायिक प्रतिनिधि बन कर, शासकीय यात्रा और धन पर गया वहां उसने अपने खास मित्रों के लिए बड़े बड़े व्यवसायिक सौदे देश की कीमत पर और देश कि बैंकों के धन से किए और देश की जनता को महंगा पेट्रोल, महँगे खाद्य पदार्थ व अन्य सुविधाएं पूंजी पतियों को लाखों करोड़ का लाभ पहुंचा कर उपलब्ध करवाई जाती रही। उन देशों के इसमें खासतौर से अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, इटली, आदि देश जो भारत को केवल एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में देखते हैं और बदले में देश से लाखों करोड़ का व्यवसाय कर पूंजी बटोर कर लाभ के रूप में ले जाते हैं। उन्होंने अपना कबाड़ा, पुरानी तकनीकी, सब इसके व्यवसायिक दौरे में भारत में खपाने का बढ़िया मौका प्राप्त किया। इसलिए दिखावे में जनता के सामने अपने व्यवसाय की खातिर इसकी भारी आवभगत करते हुए दिखाया। जबकि यथार्थ इसके विपरीत था इसके बारे में वहां की जासूसी एजेंसियों को सब कुछ बारीकी से अच्छी तरह ज्ञात है। जिसका उपयोग वहां के सत्ताधीशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भरपूर किया। यह सच भारत के किसी भी मीडिया हाउस ने नहीं दिखाया। वे सब मोटे धन के लालच में इसकी प्रशंसा ही दिखाते रहे।जबकि विदेशी मीडिया में इसकी हर बदतमीजी का बड़ा खुलकर प्रकाशन भी किया और इसकी सच्चाईयां भी प्रकाशित और प्रसारित की। जिसमें इसके पूंजी पतियों के इशारे पर नाच कर देश को बर्बाद करने के किस्से कहानियां लेख लगातार प्रकाशित हो रहे हैं यहां तक कि इसके भ्रष्टाचार के बारे में स्विट्जरलैंड की बैंकों ने जो सन 2007-8 में भारत से काले धन के बारे में कांग्रेस के समय जानकारी के आदान-प्रदान का समझौता किया था। उसे भी उसने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मोदी के आने के बाद भारत में भारी भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ जो धन पिछले 65 सालों में भारत से काले धन के रूप में जमा हुआ था। उसका आधा लगभग अनुमानित 25लाख करोड रुपए पिछले 4 सालों में जमा हुआ है। भारत के पूंजीपतियों, सत्ताधीशों, अधिकारियों, मंत्रियों, आदि का।

जब जब विपक्षियों और जनता ने इसके भ्रष्टाचार इसकी राक्षसी लूट, खसोट पर फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आदि पर इन मुद्दों को उठाया इसने उन मुद्दों को दबाने के लिए खुद व जनता के हाथ में सफाई के नाम पर झाड़ू पकड़ा कर झूठी सहानुभूति बटोरने की कोशिश की पर वहां पर भी उसने सफाई की आड़ में लाखों करोड़ का खेल कर दिया।देश के छह महानगरों में ही टाटा, अशोक लेलैंड हिंदूजा, महिंद्रा 100000 से ज्यादा छोटे मिनी ट्रक कचरा उठाने के लिए 5000 से ज्यादा ट्रक डंपर ट्राले आदि खरीदी में ही हजारों करोड का कमीशन खा लिया गया और यह खरीदी देश की 6लाख पंचायतों से लेकर 800 शहरों, 25 महानगरों में पहुंचेगी। जब जब विपक्षियों और जनता ने इसके भ्रष्टाचार इसकी राक्षसी लूट, खसोट पर फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आदि पर इन मुद्दों को उठाया, क्योंकि पिछले 4 सालों में इसने दैनिक समाचार पत्रों को प्रतिदिन चार से पांच पांच पेज के विज्ञापन देकर, जो लगभग प्रतिदिन 2से3 हजार करोड के होते हैं, टीवी वीडियो न्यूज चैनलों को 500 से 700 करोड़ के विज्ञापन डीएवीपी के अतिरिक्त विभिन्न विभिन्न मंत्रालयो आयकर, विक्रय कर, बैंकिंग, बीमा, जो सभी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, के साथ तेल कंपनियों, कृषि विकास, उद्यानकी, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे, डॉक तार एवं संचार, विधि मंत्रालय व अन्य विभागों से लगातार बांटे जाते रहे हैं। इसलिए भारत के बड़े मुद्रित समाचार पत्रों व टीवी न्यूज चैनलों ने इसके भ्रष्टाचारों, कुकर्मो के विरूद्ध इतने मोटे धन को पाकर लिखना ही बंद कर दिया। पर सोशल साइटों पर चलने वाले इसके विरुद्ध सचाईयां, भ्रष्टाचार की खबरों को बुद्धिजीवियों ने खासतौर पर युवा वर्ग में भारी उत्साह के साथ उठाया।

इसने उन मुद्दों को दबाने के लिए खुद व जनता के हाथ में सफाई के नाम पर झाड़ू पकड़ा कर झूठी सहानुभूति बटोरने की कोशिश की पर वहां पर भी उसने सफाई की आड़ में लाखों करोड़ का खेल कर दिया।देश के छह महानगरों में ही टाटा, अशोक लेलैंड हिंदूजा, महिंद्रा10 लाख से ज्यादा छोटे मिनी ट्रक कचरा उठाने के लिए 5लाख से ज्यादा ट्रक डंपर ट्राले आदि खरीदी में ही हजारों करोड का कमीशन खा लिया गया और यह खरीदी देश की 6लाख पंचायतों से लेकर, देश के बड़े 6 महानगरों तक खरीदी की गई अकेले इंदौर में ही 300 से ज्यादा टाटा के मिनी ट्रक जो कि कचरा ढोने के मान से ठीक नहीं थे।और बदले में महापौर से लेकर अधिकांश अधिकारियों को मुफ्त में व्यक्तिगत नामों से कारें भेंट की गई। शौचालय निर्माण के नाम पर हर जिले में शहरीय से लेकर गांवो तक20 से 30 हजार तक निर्माण का आधा पैसा सरपंच से लेकर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगम,परिषदों, पालिकाओं के पार्षदों से लेकर वहां बैठे महापौर निगमायुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने कागजों पर ही हजम कर लिया गया जबकि है योजना सन 2002 अटल बिहारी वाजपेई के समय पर शुरू की गई थी पिछले 16 साल में इस योजना का 90% इसी प्रकार लूटपाट और भ्रष्टाचार में हजम करने में पंचो, सरपंचों से लेकर, शहरी पार्षदों महापौर आदि को बनाकर वित्तीय रूप से सक्षम बनाकर अपनी अपनी मतदाता मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर किया गया सत्ता को स्थाई को बनाया गया। भुखेरा जन पार्टी के कार्यकाल में चारों तरफ भारी भ्रष्टाचार बढ़ा अधिकारियों, नेताओं, को भारी कमाई के अवसर प्राप्त हुए। यही काला धन चुनाव में प्रचार-प्रसार के साथ मतदाताओं को हर स्तर पर तन मन धन से सहयोग कर वोटर खरीदकर आसानी से सत्ता हथिया ली जाती है।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

नोटबंदी जीएसटी से भी ज्यादा घातक होगी, मोदी की नई व्यवस्था

भारतीय बाजार व्यवस्था को बर्बाद करने, नगदी की व्यवस्था खत्म

बाजार तरलता अर्थात नगदी की व्यवस्था खत्म करने, पर भारतीय बाजार व्यवस्था को बर्बाद करने जिससे25 करोड लोग बेरोजगार हो जाए और सारी बाजार व्यवस्था पूजी पतियों के हाथ में पहुंच जाए मोदी शीघ्र ही नई व्यवस्था को अंजाम देने में लगा हुआ है जो नोटबंदी जीएसटी से भी ज्यादा घातक होगी। यदि पांचों राज्यों में भाजपा की सरकार जीतने पर, यह व्यवस्था लागू होगी।

विदेशो से तो अपना स्वयं का व हजारों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पूंजीपतियों का जो धन विदेशी बैंकों में 2014 से पूर्व पड़ा था, उसके बाद 4 सालों में उसका आधा धन भाजपा मंत्रियों नेताओं अधिकारियों का पहुंच चुका है।

यह व्यवस्था देश के काले धन को बाहर लाने के लिए या 2करोड से ज्यादा घरेलू, लघु, व मध्यम उद्योगों व सेवाओं को नगदी के अभाव में नष्ट करने के लिए की जा रही है।

इससे देश भर में 1करोड से ज्यादा छोटे दुकानदार, ठेले वाले, फेरी वाले, फुटपाथ पर माल व सब्जी बेचने वाले सब नष्ट हो जाएंगे उन पर निर्भर 10 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे इन सब का फायदा केवल बड़े पूंजीपतियों को शॉपिंग मॉल्स को वॉलमार्ट बिरला टाटा ईजी डे, फेयर प्राइस, रिलायंस फ्रेश आदि को मिलेगा उसका मोटा कमीशन हजारों करोड प्रतिमाह में भेडियों झुंड पार्टी, कांग्रेसी अंग्रेजों की अवैध औलाद इन पूंजी राक्षसों के माध्यम से हजम करती रहेगी भारत की सड़कों पर 50 करोड़ लोग कटोरा लेकर भीख मांगते डकैती चोरी हत्या आदि के अपराध करते घूमेंगे और जीवन यापन करेंगे।

इसके लिए

मोदी द्वारा 58-61 साल के 125,000 सेवानिवृत्त आयकर अधिकारियों को पुनः बुलाया गया है।

उनके पास 28-30 नवंबर से 3 दिन का प्रशिक्षण है और 1 दिसंबर को काम में शामिल हो गए हैं।

वे क्या करेंगे जो किसी का अनुमान है।

वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित हो जाएगा।

अप्रैल-मार्च।

के बजाय जनवरी-दिसंबर।

घोषणा 30 दिसंबर को की जाएगी।

एक मजबूत संभावना है कि सरकार वित्त वर्ष 2019-20 से आयकर स्क्रैप कर सकती है और बैंकिंग लेनदेन कर (बीटीटी) के साथ प्रतिस्थापित कर सकती है। से

1 अप्रैल 2019 केवल दो करों की संभावना है

1. * * बी टी टी के रूप में प्रत्यक्ष कर बैंकिंग ट्रांसेक्सेन टेक्स,

तथा

2. अप्रत्यक्ष कर के रूप में जी एस टी।

सरकार भारत से काले धन को हटाने की योजना कैसे बनाती है? पूंजीपतियों का पेट भरने

चरण 1: पैन या आधार के बिना 10000 रुपये से अधिक नकदी लेनदेन की अनुमति न देकर नकदी अर्थव्यवस्था को हटा दें।

चरण 2: आयकर में खर्च का दावा करने के लिए चेक या आरटीजीएस में सभी वेतन और व्यावसायिक खर्च किए जाने की आवश्यकता है। सभी नकदी लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चरण 3: एक नकद सीमा आदेश जारी किया जाएगा जो प्रति व्यक्ति कुल 50000 रुपये की अधिकतम नकद भत्ता की अनुमति देगा।

चरण 4: कुछ महीनों के बाद नकद अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है, इसलिए 2000 रुपये के नोट को सीमित नोटिस के साथ दिखाया जाएगा।

बाजार में बहुत सीमित नकद उपलब्ध होने

के साथ, नकदी अर्थव्यवस्था को मौत के लिए उलझा दिया जाएगा।

चरण 5: चूंकि कुछ नकदी अर्थव्यवस्था सोने में स्थानांतरित करने की कोशिश करेगी, सोने के सिक्कों के निर्माण और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

चरण 6: एक सोने और मूल्यवान आभूषण नियंत्रण आदेश जारी किया जाएगा जो प्रति व्यक्ति केवल 500 ग्राम सोने और अन्य आभूषणों का एक निश्चित मूल्य की अनुमति देगा। प्रारूप के अनुसार अधिकारियों को घोषित किए जाने पर मौजूदा आभूषणों के लिए छूट दी जाएगी। एक निश्चित तारीख के बाद, सभी अविकसित सोने और आभूषण राज्य द्वारा लिया जा सकता है।

चरण 7: एक संपत्ति और संपत्ति घोषणा आदेश जारी किया जाएगा जहां सभी संपत्ति (* भूमि, भवन और फ्लैट) और शेयरों को अधिकारियों को किसी विशेष प्रारूप में घोषित किया जाना होगा। एक निश्चित तारीख के बाद, सभी अविकसित संपत्ति या शेयर राज्य द्वारा लिया जा सकता है।

(3 लाख 70 हज़ार करोड़ रुपये)

ये RBI का वो पैसा है जिससे वो देश की इकॉनमी को स्थिर रखती है। और इस पर कुछ ब्याज भी कमाती है।

अब RBI कानून के सेक्शन 7 का इस्तेमाल कर के मोदी जी इस धन को हथियाना चाहते है।

सरकार का कहना है कि देश आर्थिक इमेरजैंसी में है और सरकार को इस धन की जरूरत है जिससे वो इकॉनमी को संभालेगी।

अब सवाल ये है कि अगर देश का विकास हुआ है तो ये इमरजेंसी कहाँ से आई।

और अगर वाकई में इमरजेंसी है तो देश को बताया क्यों नहीं जा रहा इस इमरजेंसी के बारे में? क्योंकि ये इमरजेंसी नोटबंदी, GST और मोदी जी के दोस्तों के 12 लाख करोड़ के NPA की वजह से आई है।

2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत सरकार को इमरजेंसी का बहाना देकर RBI के पैसे हथियाने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो मोदी जी तो सिर्फ पैट्रोल-डीजल पर देश की जनता से 12 लाख करोड़ ज्यादा वसूल चुके है, दूसरी लूट के पैसे अलग, फिर भी मोदी जी को RBI के 3 लाख करोड़ चाहिए?

ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है?

अब अगर RBI का पैसा गया तो उसे भी मोदी जी वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे देश की तिजोरी के सारे पैसों को किया। सारा पैसा धन्ना सेठों की जेबों में जायेगा। पर उससे भी खराब बात ये होगी कि RBI जिस काम के लिए बनी है वो काम नहीं कर पायेगी।

ये कितना खराब होगा इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अम्बानी का आदमी उर्जित पटेल, जिसे खुद मोदी जी ने RBI गवर्नर बनाया था वो इसे रोकने इस्तीफा देनेकी धमकी दे चुका है।

अगर ये हुआ तो मार्किट और रुपये की गिरावट छोड़ो, RBI पर से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा। ये भरोसा बनाने में देश को 70 साल लगे है, ये 1 सेकिंड में खत्म हो जाएगा।

ये रफाल से बहुत बड़ा कांड है पर सवाल सिर्फ 1 है। मोदी सरकार पिछली सारी सरकारों से कई गुना अधिक रुपया जनता की जेबों से काट रही है, चाहे GST या कई सारे टैक्स-सेस के बहाने या पैट्रोल-डीजल पर हो रही लूट के ज़रिए, तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? योजनाओं की तो सिर्फ घोषणाएं होती है, किसी योजना में तो पैसा खर्च नहीं हो रहा। अगर खर्च हो रहा है तो सिर्फ पब्लिसिटी पर। फिर सारा पैसा जा कहाँ रहा है?

ये पैसा 3 गुना दाम पर खरीदे रफाल के ज़रिए अम्बानी की जेब में जा रहा है। ये पैसा बैंकों के ज़रिए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या की जेब में जा रहा है। ये पैसा IL&FS के ज़रिए संदेसरा और राकेश अस्थाना की जेब में जा रहा है। ये पैसा NPA के ज़रिए रुइया, अडानी, टोरेंट, जिंदल की जेबों में जा रहा है। ये सब ऑन पेपर है, सब को दिखता है जो देख-समझ सकता है।

क्या यही है नया भारत? ये है विकास? ये सब ऐसे ही चलते रहना चाहिए? असली विकास की जगह सिर्फ विकास की झूठी पब्लिसिटी ही चाहिए देश को? इस पब्लिसिटी के लिए देश के गरीबों और मध्यम वर्ग से दुगना टैक्स लूटा जा रहा है?

छात्रावास यौन शोषण कांड, सभी जिम्मेदार

भोपाल। सेना से 1990 में सेवानिवृत्त महेश प्रसाद अवस्थी पहले होशंगाबाद में 2001-02 से मूक बधिरों और विकलांगों का स्कूल व छात्रावास चलाता था। जिसमें मूक बधिर लड़के लड़कियां पढ़ते व छात्रावास में रहते थे। महेश अवस्थी तभी से न केवल छात्रओं का वरन छात्रों का भी यौन शोषण करता रहा। जिसमें भाजपा कांग्रेस आदि के नेताओं, मंत्रियों अधिकारियों का भी आना जाना था। यह महत्वपूर्ण तथ्य जानबूझकर समाचार पत्रों और TV न्यूज चैनल ने छुपा लिया। पहले भी कई बार शिकायतें हुई परंतु महेश अवस्थी की भोपाल के मंत्रालयों त्तक पहुंच होने के कारण मामला बीच में ही दबा दिया गया।

सन 2017 में भी एक बच्ची के मां-बाप ने उसकी जब शिकायत की तो जांच SDM मनोज उपाध्याय को सौंपी गई। सारी शिकायतें सही पाई जाने के बाद मैं उस समय होशंगाबाद में आशुतोष सिंह जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भानजा दामाद है। भांजी रितु चौहान जिसे फर्जी तरीके से भर्ती करवा कर अधिकारी बनाया है, का पति पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे और अविनाश लवानिया जो कि नरोत्तम मिश्रा के दामाद हैं। वहां पर कलेक्टर हुआ करते थे। जब भी यह कांड सामने आया था और आशुतोष सिंह व जिलाधीश अविनाश लवानिया का भी वहां आना-जाना हुआ करता था। दोनों ही घोर भ्रष्ट अय्याश होने के कारण मात्र होशंगाबाद के छात्रावास पर ताला डाल दिया गया और वहां की सरकारी सहायता बंद कर दी गई। परंतु किसी की भी थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। सारे मामले को लीपापोती कर दी गई। जबकि दोनों के पास अधिकार था कि वे उस को तत्काल गिरफ्तार करके प्रकरण चलाते और भोपाल के उसके चलने वाले सारे छात्रावासों और स्कूलों को भी सरकारी सहायता बंद कर काली सूची में डालकर ताले लगा देते परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मामा

इसके बाद मामा ससुर मंत्री जी की कृपा से अविनाश लवानिया भोपाल के कलेक्टर हो गए और मामा ससुरे मुख्यमंत्री की कृपा से भारतीय पुलिस सेवा के आशुतोष सिंह को जनसंपर्क में लाकर बिठा दिया गया। ताकि मामा ससुरे कि मीडिया में कोई भी व्यापम कांड, सैकड़ों भ्रष्टाचार कांड की नकारात्मक खबरें ना तो समाचार पत्रों में छपे और ना ही टीवी मीडिया पर चलें और चलाने

वाले को यह पुलिसिया अंदाज में डरा-धमकाकर खबरों को रोक सके और वहां चलने वाले घोर भ्रष्टाचार जिसमें सारे सरकारी पैसे हजारो करोड का उपयोग मामा ससुरे की चुनावी सभाओं में अपनी लूटपाट करते हुए आसानी से करवाया जा सके और उस पर कोई कार्रवाई भी ना हो सके के लिए बैठा दिया गया। फिर जनसंपर्क के प्रधान सचिव एस के मिश्रा जो की ऐतिहासिक भ्रष्ट घोर अय्याश जिनका अनुराधा के साथ रंगरेलियां के किस्से रायपुर से लेकर भोपाल तक खूब चटकारे लेकर सुने व सुनाये जाते थे। जिसकी बाद में अकाल मौत हो गई। जबकि महेश अवस्थी का योनाचार का मूकबधिर छात्रावास एवं स्कूल में यह तांडव भोपाल में भी चलता रहा। जिसे अविनाश लवानिया और आशुतोष सिंह न केवल भली-भांति जानते थे। बल्कि उनका सीधा दखल चुकी मुख्यमंत्री कार्यालय में था। जानबूझकर इस मामले को दबा कर रखा गया। जबकि महेश अवस्थी के भोपाल के छात्रावासों और स्कूलों में, अवयस्क बालकिाओं व बालकों के साथ में खुला यौन शोषण का तांडव जिसमें सभी दलों के नेताओं और अधिकारियों द्वारा काफी लंबे समय से किया जाता रहा। इसीलिए महेश अवस्थी को सभी का खुला सरंक्षण मिलता रहा। अब जब मामला खुल चुका है महेश अवस्थी के साथ उसके चेले विजय मिश्रा चेली गीता मिश्रा और राकेश चौधरी को सारे कांड में दोषी माना गया है। जब की दोषी तो अविनाश लवानिया और आशुतोष सिंह के साथ दोनों के ससुरे भी हैं।

सूचना के अधिकार में कैसे दें जानकारी खनिज अधिकारी

अवैध खनन में खनन माफिया नेता, सीएम, मंत्री, अधिकारी निरीक्षक भी शामिल

अवैध रेत उत्खनन में प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के नामों के साथ, राजेंद्र शुक्ला रीवा, नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना, के नाम तो बरसो से अखबार में आ रहे हैं। पर किसी का कुछ बिगड़ा नहीं। जिनकी अंध भक्ति करते हुए जिलों के जिलाधीश, सहायक उप जिलाधीश व खनिज अधिकारी के साथ निरीक्षक मोटी कमाई करते हुए शांति से सब कुछ देख रहे हैं इसलिए सूचना के अधिकार में जानकारी देने में तरह-तरह के बहाने बनाए जाते हैं।

पूरे मध्यप्रदेश में हर जिले में चारों तरफ अवैध उत्खनन का कार्य बेरोक जारी है। नर्मदा नदी के किनारों पर अमरकंटक से आगे चलकर मंडला जिले से बड़वानी तक करीबन 1077 किलोमीटर के दोनों किनारों पर अवैध उत्खनन रेती, का लगातार चल रहा है। जिसमें अधिकांश समतल क्षेत्रों में इसमें जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा जिलों मैं रेती उलीचने व खनन के साथ जबलपुर संभाग में अवैध रूप से संगमरमर का खनन भी करोड़ों रुपए का किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में मूल्यवान हीरे से लेकर बहुमूल्य धातुओं अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, लोहा, कोयला, चुना तक पाया जाता है। परंतु 50 से 80% तक अवैध रूप से उत्खनन खनन माफियाओं नेताओं, मंत्रियों, का जिला खनिज अधिकारियों, निरीक्षकों के साथ मिलकर खुले बाजार में बेच दिया जाता है। यही हाल, रेती, पीली मिट्टी, गिट्टी, पत्थर, आदि का उत्खनन पूरे प्रदेश के हर जिले हर तहसील में अधिकांश खनन माफियाओं जो स्वयं अपने इस काले कारोबार को बचाने के लिए नेतागिरी करते हैं। पंच सरपंच से लेकर पार्षद विधायक मंत्री सांसद बनकर स्वयं ही सरकार बन चुके हैं। इसलिए ऐसे खनन माफियाओं के सामने सीधी सी बात है खनिज अधिकारी निरीक्षकों से लेकर सहायक व उप जिलाधीश जिलाधीश तक सभी सिर झुका कर उनके अवैध उत्खनन से अपनी निगाहें बचाते हैं।

प्रदेश के 51 जिलों में हो रहा वैध अवैध उत्खनन, इससे कटनी, छिंदवाड़ा, शहडोल, बालाघाट, झाबुआ, जहां कीमती खनिज पाए जाते हैं। वहां पर भारी गहरी लंबी चौड़ी सैकड़ों हेक्टेयर कि सो दो सो फुट से ज्यादा गहरी खाइयां बन चुकी है। अनेकों स्थानों पर पूरे के पूरे पहाड़ गायब हो चुके हैं नदियों को समेट दिया गया है। प्राकृतिक नदियों नालों की बहाव की दिशा मोड दी गई या खत्म कर दी गई है। जबकि किसी भी खदान को उत्खनन करने के बाद उसे पूरा भरा जाना चाहिए और वहां पर पर्याप्त अच्छा वृक्षारोपण होना चाहिए। फिर यह बात कि भारत में वैध अवैध उत्खनन से भारत का न केवल पूरा पर्यावरण बिगड़ रहा है। वरन् खेती का फसल चक्र भी बिगड़ने के साथ प्राकृतिक पशु पक्षियों पेड़ पौधों सैकड़ों प्रजातियां भी नष्ट हो चुकी है। जो मानव जीवन को अनेकों गंभीर किस्म की बीमारियां देने के साथ औसत आयु को भी कम कर रही है। पर इन सबसे घोर लालची भू माफियाओं खनन माफियाओं, खनन विभाग के निरीक्षकों अधिकारियों के साथ राजस्व के घोर भ्रष्ट पटवारी से लेकर तहसीलदार सहायक, उप, जिलाधीश आयुक्तों, प्रधान सचिव, खनन मंत्री, मुख्यमंत्री जो सब दोनों हाथ से धन उलीच रहे हैं। क्या मतलब है?

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

भुखेरा जन पार्टी केंद्र से लेकर, राज्यों, नगरों और गांवों तक अपनी मोटी कमाई के लिए

आखिर त्योहारों के समय ही क्यों की जाती है? तोड़फोड़ की नौटंकी

मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज एक तरफ प्रदेश की महानगरों नगरों और गांवों तक हजारों बसी अवैध कालोनियों को वैध बनाने का वोटों की खातिर आश्वासन देता है। उनके निवासों की सुरक्षा का और दूसरी तरफ इंदौर के साथ प्रदेश के सभी नगरों में पिछले कई वर्षों से कानूनी दांवपेच के चंगुल में फंसा कर वैध अवैध के नाम पर सतत बरसों से बीच बाजारों में तोड़फोड़ की जा रही है। क्या है? क्यों है? यह दोहरा चरित्र? भूखेरा जन पार्टी का। क्या मोदी का यह कहना की कांग्रेसियों ने देश को 65 साल लूटा है। उतना हम 5 साल में लूटेगे। क्या यह उसी सत्य को को पूरा करने का हिस्सा है?

पिछले 18 वर्षों से मैं इंदौर में हूं और देख रहा हूं कि यहां की नगर निगम पर भुखेरा जन पार्टी का कब्जा है। और यह भुखेरा जन पार्टी अपने मोटे लाभ के लिए हर साल केवल त्योहारों के समय ही इस शहर के निवासियों की दुकानें मकान किसी भी बहाने तोडता चला आ रहा है। वही हाल ठीक त्योहारों के समय, अपनी मोटी कमाई के लिए पार्षद जानबूझकर अच्छी खासी लगी हुई पेवर ब्लॉक और सड़कें तोड़ी-फोड़ी जाती हैं। फिर बनाने के नाम पर उखाड़ा जाकर घरों के सामने मिट्टी का ढेर लगा दिया जाता है। और जनता के त्योहारों को बर्बाद किया जाता है।

यदि कोई अवैध निर्माण किया गया था तो उस समय किया जा रहा था उस समय क्या पूरा का पूरा नगर निगम का दरोगा से लेकर इंजीनियरिंग विभाग की पूरी टीम अपनी महीना वसूली करके चुपचाप सोते रहते थे जब निर्माण हो जाता है और वह मार्केट, बाजार और निवासी क्षेत्र चल निकलता है वहां पर विवाह होने लगती है और वहां की जमीनों की कीमतें चौगुनी से 10 गुनी हो जाती है। तब बड़े भू माफियाओं नेताओं, कॉलोनाइजरो, बिल्डरों की मोटा धन कमाने की लार टपकने लगती है। तब फिर कानूनी सारे दांव पेंच खेले जाने लगते हैं और छोटे न्यायालय से निकल कर बात सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचती है और वहां मोटा धन बड़े वकील खड़े कर प्रकरण को जीतने का दावा कर तोड़फोड़ मचा दी जाती है। बाकी सारे केसों में जहां मोटा धन अधिकारियों पार्षदों और महापौर को मिल जाता है। वहां जानबूझकर हर स्तर पर नगर निगम विकास प्राधिकरण शासन कमजोर प्रस्तुति कर स्वंय प्रकरणों को हारने का नाटक करता है। अकेले इंदौर विकास प्राधिकरण में 5000 से ज्यादा मामले पट्टा शर्तों के उल्लंघन के लंबित पड़े हुए हैं। जिस में सबसे बढ़ा मामला सयाजी होटल की पट्टा शर्तों के उल्लंघन का है 30 साल की थी सन 2006 से अभी तक न्यायालयो की आड़ में उसे बचाया जा रहा है। सयाजी होटल न केवल लीज का उल्लंघन किया, बरन अनाधिकृत अत्यधिक निर्माण भी कर रखा है परंतु उसका आज तक एक ईंट भी नहीं हटाई जा सकी। जबकि तुलसियाना बिल्डिंग, मनी मार्केट, मैं न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के बावजूद भी उसको ठीक दीपावली दशहरे के समय पर तोड़ दिया गया और वहां के दुकानदारों रहवासियों की जीवन की जमा पूंजी को कुछ ही घंटों में तहस-नहस कर मिट्टी में मिला कर चौराहों पर कटोरा थमा का छोड़ दिया गया।

ठीक त्योहारों पर जवाहर मार्ग पुल तोड़ा गया

जबकि ब्रैकेटिंग कर 5- 10साल उपयोग किया जा सकता था।तोडने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक इन त्योहारों के समय पर शहर में अनेकों स्थानों पर स्मार्ट सिटी और चौड़ीकरण के नाम पर तोड़फोड़ जारी है। पर इन बेरहम नगिम के भेड़ियों को अपनी कमाई के आगे किसी के दुख दर्द त्योहार व्यापार व्यवसाय निवास स्थल उजाड़ने तोड़ने में कुछ भी नहीं दिखाई देता। निगम के बेलदार असलम से लेकर उपयंत्री अमित राठौर जो 25 से 50 करोड़ के आसामी निकले हैं तो अन्य उपयंत्री, सहायक यंत्री, सभी विभाग के बाबूओ, अधिकारियों उपायुक्तो, आयुक्तों, आयुक्तों, क्षेत्र के पार्षदों से लेकर महापौरो तक सब ने कितने अरबों रुपए का धन कमाया। इसकी खोजबीन और जांच हर किसी की बारीकी से की जानी चाहिए।

इसके पहले भी पाटनीपुरा चौराहे से मालवा मिल चौराहे तक, पाटनीपुरा चौराहे से आस्था टॉकीज तक, पुरी बियाबानी, राजमोहल्ले से बड़ा गणपति तक, पूरी लोहार पट्टी, कनाडिया रोड इसी प्रकार पिछले वर्षों में ठीक त्योहारों के समय पर तोड़कर क्षेत्रीय रहवासियों और व्यापारियों को त्योहारों पर कमाई और खुशी की अपेक्षा आंसूओं के कटोरे थमा कर रोते बिलखते छोड़ दिया जाता है।

हर साल जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इसकी तोड फोड गिरोह ज्यादा सक्रिय रहती है। ताकि इस तोड़फोड़ से उनकी मोटी कमाई कि जाकर वो अपना त्योहार बहुत मौज मस्ती खुशी से मनाएं और अन्य शहरवासी रोते बिलखते अपने आशियाने व्यवसाय समेटते हुए नये बसेरों की तलाश में सड़कों पर और या अपने अन्य रिश्तेदारों के पास उनकी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते है।

इंदौर के धनाढ्य निवासी उच्च अभिजात्य वर्ग जिसकी ऊंची पहुंच राजनीति और प्रशासन में है। मीडिया के भांडों के साथ मिलकर यहां के दैनिक समाचार पत्रों में बातें बड़ी ज्ञान और सहानुभूति पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, हरियाली वृक्षों के प्रति, गरीब बीमारों के प्रति बड़ी सहानुभूति दान धर्म की बातें करता है। हर दिन ऐसे कार्यक्रम अपनी महानता सिद्ध हो आयोजित कर बड़ी- बड़ी फोटो अखबार में चिपकवाता है। चिकित्सालय में मुफ्त भोजन बीमारों को बांटने की नौटंकी करता है। यह वही अभीजात्य वर्ग है। जिनके इशारे पर यह सारी नौटंकी करवाई जाती है। लोगों के आशियाने दुकानों व्यापार व्यवसाय को ठीक त्योहारों के समय उजाड़ बनाकर मध्यमवर्गीय लोगों को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है आखिर इंदौर के सभी रहवासी ऐसे नगर निगम के प्रशासन के इन घोर अत्याचारों के विरुद्ध एकत्रित होकर आवाज उठाकर रोका जा सके। ताकि कम से कम त्योहारों के समय हमारे ही भाई बंधु रिश्ते नातेदार व अन्य सभी को ऐसी विपरीत परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े।

यही हाल एक तरफ हर वर्ष जुलाई के महीने में 6--8 करोड पेड़ लगाने की नौटंकी की जाती है। दूसरी तरफ गांव वालों को बोला जाता है कि तुम तो कब्जे कर लो। कृषि भूमि व मकान बनाने की पट्टे मामा देगा और इस तरह एक तरफ जंगल उजाड़े जाते हैं। फिर वन कर्मचारियों बीट गार्ड, फर्स्ट अवेंजर फॉरेस्टर रेंजर आदि की जांच बिठाकर, उन्हें दोषी पाकर निलंबन किया जाता है और नौकरियों से हटाया जाता है। तो फिर यही कहानी नगर निगम में बैठे, दरोगा, उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री, अधिकारियों उप निगम आयुक्तों, आयुक्तों, क्षेत्र के पार्षदों से लेकर महापौरो पर क्यों नहीं की जाती पर जब निर्माण होता है तब तो सबको मोटी बसूली से मतलब होता है। फिर जब तक वसूली मिलती रहती है। तब तक निर्माण खड़ा रहता है जब कोई मोटा आसामी ज्यादा धन देने वाला मिल जाता है तो वह वैद्य निर्माण भी अवैध हो जाता है। अभी भी पूरे शहर में सभी नालों के किनारे बड़ी बड़ी पोस कालोनियों से लेकर छोटी बस्तियों तक कम से कम इस शहर में 50,000 से ज्यादा निर्माण खड़े हुए हैं उनका कब और क्या होगा?

जो किसी भी बहाने बाजार में सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर स्मार्ट सिटी के नाम पर भारी तोड़फोड़ करके लोगों के आसियाने, व्यापार, व्यवसाय उजाड़ने में सिद्ध हस्त रही है। बदले में धर्म के नाम पर अपने भाई भतीजों को, रिश्तेदारो, मित्रों को, 50से70% तक के कमीशन पर स्तरहीन निर्माण के ठेके दिए जाते हैं। इंदौर की पूरे शहर की जनता इतिहास को देख सकती हैं।

प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री, प्रधान सचिव, आयुक्त, नियंत्रक सबको मासिक करोड़ों में कमाई इसलिए सब चुप

भ्रष्टाचार से 100 से ज्यादा निरीक्षक 10 साल से अजगरों की तरह

इस विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी व औषधि निरीक्षक एक स्थान पर 10 -10 बरसों से कुंडली मारे लूट और वसूली करते बैठे हुए हैं। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर इन हरामखोर सूकरों की फौज जवाब और जानकारी देती ही नहीं। अपील के बाद यदि आदेश दे भी दिया। तो भी यह घोर निकम्मे, जालसाज, मक्कार आवेदक को चार चार महीने चक्कर लगवा देते हैं। जैसा कि उज्जैन के विभाग में आवेदक के साथ किया जा रहा है।

इंदौर में सुभाष खेड़कर, श्रीमती वैशाली सिंह, मनीष स्वामी, देवास में नरसिंह सोलंकी श्रीमती अलमेलु टीवी, धार मे संजीव कुमार मिश्रा, महेंद्र कुमार वर्मा, सन 2008 से, खरगोन में धीरज श्रीवास्तव और श्रीमती मयूरी डोंगरी सन 2010 से मंदसौर में कमलेश जमरा सन 2008 से भोपाल में भोजराज सिंह धाकड़ सुश्री प्रभा घुरे, सुश्री टिनेश्वरी धुर्वे सन 2008 से, अरुणेश पटेल, धर्मेंद्र भैया लुलिया नुनइया, सन 2010 से से कुंडली मारे बैठे हुए हैं पूरे मध्यप्रदेश का है। यह हाल औषधि निरीक्षक अशोक गोयल 10 सालों से इंदौर में ही, रु25लाख, देकर डटा है। भोपाल में बैठा हुआ वरिष्ठ औषधि निरीक्षक शोभित कोष्टा पूरे मध्यप्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं औषधि निरीक्षकों से मोटा धन लेकर स्थानांतरण पदस्थापना आदि के स्थानांतरण के मौसम में उन सबके प्रस्ताव मंगवाकर जो जितना धन देता है। उसके हिसाब से उसकी वसूली कर पदस्थापना करवा देता है। जिसमें विशेष कर्तव्य अधिकारी अरविंद पाठक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह का निजी सचिव है। जो कि संजय मिश्रा 10 साल से धार में खाद्य निरीक्षक व सुरक्षा अधिकारी कार्यरत है। रिश्ते में साढू भाई लगता है। उस के माध्यम से पूरे स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरे मध्यप्रदेश की खाद्य सुरक्षा अधिकारियों व औषधि निरीक्षको की मंत्री रुस्तम सिंह द्वारा धन के आधार पर की जाती है। इसी संजय मिश्रा के द्वारा सचिन लोंगरिया की झूठी शिकायत कर उसका ट्रांसफर धार से मंदसौर करवा दिया गया। क्योंकि उसकी वसूली में सचिन लोंगरिया के कारण बाधा उत्पन्न हो रही थी। औषधि निरीक्षक धर्मेश बिगोनिया विगत 6 वर्षों से इंदौर में सीनियर इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है। रु50लाख देकर आराम से इंदौर में जमा हुआ है। मंत्री रुस्तम सिंह के इस निजी सचिव का शिकायतों के आधार पर स्थानांतरण छतरपुर करवा दिया गया था। निजी सचिव अरविंद पाठक का अपर कलेक्टर के रूप में छतरपुर का स्थानांतरण रुपए 25लाख देकर 2 माह पूर्व सांठगांठ करके अपना स्थानांतरण रद्द करवा पुनः निजी सचिव के पास करवा लिया। औषधि निरीक्षक धर्मेश बिगोनिया जो हर साल इंदौर से करीबन दवा बाजार से हर तिमाही में 25लाख रुपए की वसूली करता है। इसी प्रकार मोटी वसूली जो लाखों रुपए प्रति वर्ष सारे ड्रग फैक्ट्रियों और विक्रेताओं से की जाती है। वैसे भी विभाग में औषधि निरीक्षकों की भारी कमी है हर शहर में जहां कम से कम 2 औषधि निरीक्षक होने चाहिए मध्यप्रदेश में लगभग ४५ औषधि निरीक्षक ही है जिसमें 5-5 इंदौर और भोपाल में ही है २५ औषधि निरीक्षकों के पास पूरे मध्यप्रदेश कि 49 जिलों का प्रभार है। जो निरीक्षण कम वसूली में ज्यादा संग्लन रहते हैं। लगभग 30 से ज्यादा औषधि निरीक्षकों को जो कि अधिकांश निजी औषधि महाविद्यालयो से स्नातक की डिग्री लेकर आए हैं जहां पर न तो पर्याप्त फार्मेसी की प्रयोगशालाये पढ़ाने के लिए पर्याप्त स्टाफ तक नहीं था। मोटा धन देकर उन्होंने नियुक्तियां तो पा लीं, परंतु अभी तक सैंपल लेना और उसकी रिपोर्ट तैयार करने का ज्ञान तक ही नहीं है। वह हरामखोर जालसाज खाक औषधियों की जांच करेंगे नमूने लेंगे स्तरहीन मिस ब्रांडेड नमूने पाए जाने पर क्या खाक कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिन सबको 3 से10 साल के बाद में भी फार्म 35 पर नमूने लेने और उसे प्रयोगशाला पर भेजने का का सही तरीका ही ना मालूम हो। औषधियों के साथ इस विभाग में पेथोलैब, ब्लड बैंक व सभी निजी व सरकारी चिकित्सालयों में जाकर वहां की औषधियों, चिकित्सा से संबंधित अन्य सामग्री के स्तर की जांच का भी जिम्मा होता है। पर जिन्हें अवैध वसूली से ही फुर्सत ना हो। उन भ्रष्टों से नियमित शासकीय अच्छे काम की काम की उम्मीद करना तो वैसे भी निरर्थक ही है।

स्वामी ने हीं इंदौर के समस्त नमकीन निर्माताओं से मावा व्यापारियों से उसकी मासिक वसूली चालू कर रखी है। साथ ही इसके पास 50 से ज्यादा सभी बड़े शॉपिंग मॉलस, 5000से ज्यादा खाद्य् सामग्री उत्पादको, पैकर्स आदि से पूरे इंदौर नगर में प्रतिमाह रुपए 50लाख से ज्यादा की वसूली की जाती है। इसी दम पर है वह 10 साल से बैठा हुआ है और अपने दो एवजियो को अपने अवैध वसूली से वेतन देकर जो मुचिअद की लाइसेंस आई डी का उपयोग करते हैं जो की पूर्णता अवैध एवं गैर कानूनी है।

खाद्य एवं औषधि निरीक्षक जोकी हर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अंतर्गत कार्य करते हैं । हर जिले का सीएमओ इन सभी खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों से मोटा मासकि धन लेकर इन सभी औषधि एवं खाद्य निरीक्षकों को 10-20लाख से लेकर करोड़ों रुपए की मासिक वसूली करने की पूरी छूट देता है। बदले में सभी औषध एवं खाद्य सामग्री विक्रेता जनता के साथ मिलावटी नकली और स्तर हीन औषधियां व खाद्य सामग्री जनता को बेचकर उन्हें भारी गंभीर बीमारियां जिस में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक मधुमेह, उच्च नम्नि रक्तचाप, लिवर किडनी पेट की गंभीर रोग आदि की बीमारियां बांटते रहते हैं।

प्रदेश भर में जब दुधारू पशुओं की संख्या 50 लाख भी नहीं है । तो सवा सात करोड़ आबादी को औसतन 4करोड़ किलो लीटर दूध कहां से बरस रहा है। सांची और अमूल भी न केबल शुद्ध नकली और पाउडर से बना दूध रु50 लीटर तक बेच रहे हैं। इन हरामखोर और जालसाजों द्वारा महंगा दूध बेचने के कारण आम नकली दूध विक्रेता भी रु12-15 की कीमत का दूध जनता को 40 से रु50 बेंच रही है। इसके बावजूद इन हरामखोर खाद्य औषध विभाग के निरीक्षकों की फौज महीना वसूल कर के जनता के दूधमुहै बच्चों को नकली दूध पिलाकर पाल पोस के बीमारियों का घर बना के बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कमाई का साधन बना चुके हैं। पर भेड़िया झुंड पार्टी की सरकार उसके मंत्रियों, साथ में बैठे अधिकारियों डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग को इस से कोई मतलब नहीं रोज अखबारों में इसके संबंध में खबरें छपती हैं। पर इन धूर्त, मक्कार, हरामखोर, जालसाज निरीक्षकों को केवल अपनी मोटी मासिक कमाई से मतलब होता है । दूसरी ओर महिला खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों का हाल तो और भी बुरा है। ये सब सामान्यतः 12के बाद आती है। और कोशिश होती है 4:00 बजे के पहले अपने साथी पुरुष कर्मियों को कोई भी बहाना बना कर चली जाए जैसा कि हर शासकीय विभाग मैं महिलाओं का कार्य करने का चलन है। यहां पर भी अधिकांश औषधि निरीक्षक महिलाओं ने अपने हिस्से के नमूने लेने की बात तो दूर उन्हें ढंग से फॉर्म 35 भरना भी नहीं आता। निरीक्षण के नाम पर तो अंगूठा भी ढंग से नहीं लगाना आता। परंतु अवैध मासिक वसूली जालसाजी मे इनका कोई सानी नहीं।

खाद्य सुरक्षा व औषधि विभाग में जो वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे उन्हें क्योंकि वह धन नहीं दे पाए मंत्री को इसलिए उन्हें छोटे जलिो में पदस्थ कर दिया गया इसके विपरीत जो घोर भ्रष्ट और वसूलीवाज सेटिंग करने में मास्टर थे। उन्हें बड़े जिलों में सालों से पदस्थ करके रखा गया है क्योंकि वह सब नियमित रूप से स्वास्थ्य मंत्री को अपनी वसूली का हिस्सा पहुंचाते हैं।

इंदौर के नमूना सहायक सुधाकर वनसिंहे के 1985 इंदौर में पद पर कार्यरत है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष खेडकर पिछले 10 वर्षों से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में इंदौर में ही पदस्थ है और यह दोनों मिलकर वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक मनीष स्वामी के इशारे पर पूरे इंदौर शहर से वसूली करते हैं। वर्तमान में सुभाष खेडकर के द्वारा 10 लाख की एक स्वि फ्ट कार खरीदी गई है।सुधाकर बनसिगे की पुत्री का विवाह हाल ही में फरवरी 2018 में हुआ जिसको अमेरिका का वीजा करवा के दिया गया। जिसकी लागत लगभग रु40000 होती है। यह एक नमूना सहायक के पास में रु 4लाख और रु 25लाख रुपए की शादी का पैसा कहां से आया। इसकी सूक्ष्म जांच की जानी चाहिए। उसने पिछले 10 वर्षों में जो आयकर विवरणी प्रस्तुत की गई है। उसमें क्या यह जो पैसा इसके पास था। वह उसके ऊपर आयकर चुकाया गया इसकी जांच की जानी चाहिए सुभाष खेड़कर के द्वारा।

मनीष स्वामी द्वारा स्कीम नंबर 136 में जो बंगला खरीदा जिसकी कीमत 50लाख रुपए है और एक बलेनो कार खरीदी गई खरीदा गया उसका धन कहां से आया। हाल ही में वैशाली सिंह ने भी एक मारुति 800 और एक फ्लेट खरीदा है। हिमाली सोन पाटकी ने भी अभी हाल ही में एक बजाज जी में 25लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा था। क्या इसकी अनुमति अपने वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त की गई।

उज्जैन में शैलेश गुप्ता 5सालो से ज्यादा समय से, वर्षा व्यास 10 सालों से ज्यादा समय से, इसी प्रकार पूरे मध्यप्रदेश में 50 प्रतिशत खाद्य निरीक्षक बरसों से ही मोटी वसूली कर मोटा धन हर वर्ष मंत्री को देकर एक ही स्थान पर डटे हुए हैं।

यह हाल मध्य प्रदेश की सभी 51 जिलों का है जहां पर खाद्य व औषधि निरीक्षक खुले में मोटी वसूली कर अमानक स्तर के खाद्य और औषधियों के बिकने की खुली छूट दे कर रखे हुए हैं और जो पैसा नहीं देता है उनके जानबूझकर नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेज कर अमानक और मिलावटी करार देकर उन पर मोटा रु 50000 से लाखों में आर्थिक दंड लगाया जाता है। इस से डरकर हर खाद्य एवं औषधि निर्माता पैकर और विक्रेता इन हरामखोर भ्रष्ट निरीक्षकों को महीना देते रहते हैं। बदले में जनता को अमानक स्तर के खाद्य एवं औषधियों का सेवन उनके स्वास्थ्य को बर्बाद कर, जिसके परिणाम स्वरुप कैंसर, हृदयाघात, किडनी लीवर वह अन्य सैकड़ों बीमारियो के कारण देसी विदेशी दवा कंपनियों व चिकित्सालय का करोड़ों का फायदा करवाया जाता है।

वर्तमान में अधिकांश खाद्य एवं औषधि निरीक्षक जिनकी नौकरियां एक ही स्थान पर 5 से 10 वर्ष से ज्यादा हो चुकी हैं वे सभी करोड़पति हैं सभी के पास बेनामी संपत्तियां मकान का नई महंगी कारें आदि है। और कुछ जोड़े तो 25-25 करोड़ से ज्यादा की आसामी हो चुके हैं इन सब के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियंत्रक से लेकर मंत्री तक को लोकायुक्त लपेटे में ले कर प्रदेश में चल रहे मिलावटी खाद्य वस्तुओं व स्तरहीन औषधियों के रेकेट की जांच करनी चाहिए।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

13 साल के शासन में हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन की कमाई केवल बिजली से

पेज एक से जारी

विभिन्न माध्यमों इसमें रेत, गिट्टी मुरम खनन से लेकर भवनों की स्वीकृतियां देना, सरकारी, नजूल, चरनोइ, वन भूमि की जमीनों की अफरा-तफरी, अवैध कब्जे मकान, दुकान, कालोनियों आदि के निर्माण में मोटा धन लेकर अपनी महत्वपूर्ण भुमकिा अदा की।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सभी विभागों में मुख्यतः लोक निर्माण विभाग, कोषालय, पंजीयक, जल संसाधन, पंचायत, सामान्य प्रशासन, वाणिज्य कर, महिला बाल विकास, भू अभिलेख आदि के सॉफ्टवेयरो के बनाने आप सभी विभागों में कंप्यूटर प्रणाली कब विकसित करने में हीं हार्डवेयरो की खरीद में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया। रु25-50 लाख के सॉफ्टवेयरो को रु500-600 करोड तक में टाटा कंसलटेंसी विप्रो व अन्य कंपनियों से बनवाये जाकर 100 से ज्यादा सॉफ्टवेयर विभिन्न विभागों के लिए बनवाई जा कर हजारों करोड़ की लूट की गई। जिसमें मंत्री मुख्यमंत्री का मोटा हिस्सा था। यही हाल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में जिस में गेहूं दाल चावल शक्कर आदि की आपूर्ति में घटिया गुणवत्ता का माल खरीदकर गरीब जनता को आपूर्ति करने के नाम पर 50% से ज्यादा माल खुले बाजारों में मैदा आटा मिल मालिकों को बेंच दिया गया। जबकि गरीब जनता को अंगूठा, आधार कार्ड, की आड़ में उचित कीमतों पर राशन नहीं मिल सका। इसके साथ ही गैस पैट्रोल डीजल पंप आदि के मालिकों से हर महीने की अरबों रुपए की वसूली पूरे प्रदेश में की जाती रही जिले के खाद्य अधिकारियों व नीरक्षिकों द्वारा, इसका पैसा भी मंत्री और भाभी के पास पहुंचता रहा।

भाजपा की बुरहानपुर से विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस जो कि पूर्व में इंदौर के जापानी गद्दा कांड की नायिका रही है। महिला बाल विकास विभाग की मंत्री रहते हुए उसने भी अपने अंतर्गत चलने वाली 61036 आंगनबाड़ियों में पोषण आहार जो 1 से 5 साल के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को बाटा जाना चाहिए था उस का 20 परसेंट भी 1 से 5 साल के बच्चों वह गर्भवती महिलाओं को कभी नहीं मिला और वह सारा पैसा मंत्री मुख्यमंत्री आदि ने डकार लिया जो कि हजारों करोड़ में था पोषण आहार की आपूर्ति में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया। यही कारण है, कि श्योपुर, खंडवा जिलों के विकास खंडों मैं 80% बच्चे और महिलाएं कुपोषण से ग्रस्त पाई गई इसमें सैकड़ों की मौत भी हो गई परंतु मंत्री स्त्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भ्रष्टाचार इसी के अन्य विभागों जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण मैं भी खुलकर हुआ सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर यहां बैठे जिला अधिकारी जो घोर भ्रष्ट और हरामखोर है जानकारी देने के नाम पर आवेदकों को भारी परेशान करते हैं क्योंकि कदम कदम पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

ऊर्जा के नाम पर विद्युत कंपनियों में चल रहे लूटपाट का तांडव वैसे तो बिकाऊ मीडिया चाहे वो टीवी के समाचार चैनल्स या दैनिक समाचार पत्र थोड़ा थोड़ा कभी कभी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सरकार के खिलाफ छापते ही रहे हैं। पूरे प्रदेश में चारों तरफ इन कंपनियों में भी चुन चुन के घोर महा भ्रष्ट जाल साज भारतीय प्रताड़ना सेवा के उन अधिकारियों को बैठाया गया है जनता को लूटने विद्युत मंडल की बनी हुई कंपनियों को बर्बाद करने और हजारों करोड हर साल हजम कर जाने मैं तो सिद्ध हस्त होने के साथ झूठे आंकड़ों कीमते बढ़वाने के लिए सारी लेखा बही मैं झूठे तलपट और चिठ्ठे बनाकर प्रस्तुति में भी मास्टर है। विद्युत कंपनियों में सबसे ज्यादा लाखों करोड़ की विद्युत की खरीद बिक्री करने वाली पावर ट्रेडिंग कंपनी भारी लूटपाट का तांडव कर रही है। जिसे प्रसार माध्यम और जनता भी नहीं समझ पा रही है।

घोर अपराधी प्रवृत्ति का खनिज माफिया ही वर्तमान में खनन और वाणिज्य का मंत्री रीवा का राजेंद्र शुक्ला जिसके आपराधिकता, भ्रष्टाचार अवैध खनन से हजारों करोड़ की कमाई और लूट आदि के किस्से।

पिछले 5 वर्षों से देश और प्रदेश के अखबारों में लगातार छप रहे हैं। फिर जब स्वयं ही बड़ा रेत माफिया हो तो कुछ कहने व लिखने का औचित्य सिद्ध नहीं होता। जबकि प्रदेश में हीरो से लेकर मैग्नीज, तांबा, अभ्रक, लोहा, चूना, संगमरमर, कोयला तक की बड़ी बड़ी खदान हैं जिसमें लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया जाकर कमाई की जाती है। दूसरी ओर वाणिज्य, उद्योग, रोजगार की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। वाणिज्य उद्योग मैं बैठे घोर भ्रष्ट प्रबंध संचालकों से लेकर वहां के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधको, प्रबंधकों, इंजीनियरों, लेखापालो जो लंबे समय से औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम 8 से ज्यादा संभागों में बरसों से कुंडली मारकर डटे हुए हैं। प्रदेश में पिछले 15 सालों में 30% से ज्यादा बड़े उद्योग उनके भ्रष्टाचार और लूट के कारण बंद हो गए। दूसरी तरफ सैकड़ों करोड़ इन्वेस्टर्स मीट कि कार्यक्रम आयोजित करने में ही हजम कर लिए गए। यह सच है इस आपराधिक घोर भ्रष्ट मंत्री राजेंद्र शुक्ल का।

रामपाल सिंह को 3 साल पहले ही लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया था। इन 3 सालों में पूरे लोक निर्माण विभाग की हालत अधिक गंभीर हो गई चारों तरफ घोर भ्रष्ट सहायक संभागीय अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनाकर अधिकांश को मोटी रॉयल्टी पर कार्यपालन यंत्री बनाकर बैठा दिया गया है स्वाभाविक है, कि जब उन्हें पद पर बैठने के लिए मोटी रॉयल्टी का भुगतान अपने प्रमुख अभियंता मंत्री प्रधान सचिव को करना पड़ेगा तो बिना भ्रष्टाचार के धन कहां से आएगा इसलिए चारों तरफ भ्रष्टाचार की बहार आई हुई है सड़कों और भवनों के रखरखाव के नाम पर खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार की सड़कें और भवनो की हालत चारों तरफ दयनीय बनी हुई है। जबकि पर्याप्त पैसा चारों तरफ खर्च किया गया । जो लगभग रूपीस 20000 करोड़ से ज्यादा था। वैसे तो अभी चुनाव महोत्सव के माहौल में चारों तरफ मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर रेंप बनाना, वहां बिजली पानी आदि की व्यवस्था करना के नाम पर हर जिलाधीश को सैकडौं करोड़ का चुनाव आयोग से आवंटन प्राप्त हुआ है जिस में से मात्र 40 परसेंट पर सही खर्च होता है बाकी सब हजम कर लिया जाता है कार्यपालन यंत्री ठेकेदार और संबंधित सहायक व उप यंत्री के द्वारा । यहां तक की आधा अधूरा काम पहले हो जाता है और उसकी निविदाएं बाद में जारी होती है।

अंदाज लगाया जा सकता है। क्या चल रहा है पूरे लोक निर्माण विभाग में? वही हाल इस विभाग की परियोजना की क्रियान्वयन इकाई, सेतु, राष्ट्रीय राजमार्ग व मध्य प्रदेश सड़क डकैती विकास निगम के कार्यों का भी है डकैती विकास निगम में तो हालत यह है कि वहां के ठेकेदार चुंकि सभी को, जिसमें संभागीय प्रबंधक, प्रबंध संचालक से लेकर प्रधान सचिव मंत्री और मुख्यमंत्री को महीना बांटते हैं इसलिए वहां हर साल 7% की बढ़ोतरी हर साल कर दी जाती है। जो कि प्राथमिक स्तर पर किए का करार मैं 3 साल में एक बार होनी चाहिए थी कें स्थान पर हर वर्ष की जाती है और इस प्रकार जनता को लूटा जाता है। परंतु पूरे प्रदेश की उबड खाबड सड़कों पर हर 30 -40 कि मी के बाद हर वाहन चालक को अंटसंट टोल टैक्स देना पड़ता है। जो कि 15 वर्ष की भाजपा की सरकार में नियमों के विपरीत भारी पेट्रोल-डीजल पर टैक्स देने के बाद में भी जनता को चुकाना पड़ रहा है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह इस विभाग की लूटपाट के बारे में 90% जनता को कुछ भी नहीं मालूम। यही वह विभाग है। जहां से नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों, आदि के विकास के लिए धन उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में चलने वाली प्रदेश कें 6 शहरों जो कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहां तोड़फोड़ और लूट का तांडव चल रहा है। जिसमें सीधा 25 से 50% कमीशन बांटने पर ही आवश्यक व अनावश्यक काम किए जाते हैं। पैसा हजम करने के लिए पार्षदों से लेकर महापौर निगमायुक्त तक अपनी मोटी कमाई के लिए बनी बनाई सड़कों को, पेवर ब्लॉक, नालियां, फुटपाथ, बगीचे आदि को जानबूझकर तोड़ना फोडना और उनका पुनः निर्माण करवाने में आधे से ज्यादा पैसा हजम कर जाना बहुत सामान्य सी बात है। अभी सबसे बड़ा घोटाला सफाई के नाम पर किया जा रहा है जहां पर 30% कर्मचारियों एक काम लिया जा कर 70% कर्मचारियों को केवल कागजों पर ही काम लिया जा रहा है। साथ ही पूरे प्रदेश में सफाई के लिए हजारों करोड़ की गाड़ियां, ट्रालयिां, डंपर, ट्रकों, झाड़ लगाने वाली मशीनों आदि की खरीदी में सैकड़ों करोड़ का कमीशन हजम किया गया पूरे प्रदेश भर में माया सिंह का भी जिससे 10-15% का हिस्सा था।

यही हाल सब ही मंत्रालयों और उनके अंतर्गत काम करने वाले सभी विभागों का है। जसि की छोटी मोटी भ्रष्टाचार की कहानियां आए दिन समाचार पत्रों में समाचार पत्रों को अपना अस्ति त्व जनता के बीच बनाए रखने के लिए छापनी पड़ती है। अन्यथा समाचार पत्रों को मिलने वाले हर दिन 5-7 पेज के मोटे विज्ञापनों के कारण सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं कुछ अपना चाहते हैं यह सच्चाई हर विभाग के साथ पुरी सरकार के साथ है जनता सोचे इस अगले चुनाव में उसे क्या करना है।

स्विट्जरलैंड की सरकार ने भारत के साथ सन 2006-07 में किए हुए काले धन के समझौते को इसीलिए रद्द कर दिया, क्योंकि जितना धन पिछले 65 सालों में भारत से कांग्रेस के कार्यकाल में भारत से स्विट्जरलैंड में जमा हुआ था उसका आधा धन 4 सालों में ही स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा हो गया है।

नए अछूत

हमको देखो हम सवर्ण हैं
भारत माँ के पूत हैं,
लेकिन दुःख है अब भारत में,
हम सब 'नए अछूत' हैं;

सारे नियम सभी कानूनों ने,
हमको ही मारा है;
भारत का निर्माता देखो,
अपने घर में हारा है;
नहीं हमारे लिए नौकरी,
नहीं सीट विद्यालय में;
ना अपनी कोई सुनवाई,
संसद में, न्यायालय में;
हम भविष्य थे भारत माँ के,
आज बने हम भूत हैं;
बेहद दुःख है अब भारत में;
हम सब 'नए अछूत' हैं;

'दलित' महज़ आरोप लगा दे,
हमें जेल में जाना है;
हम-निर्दोष, नहीं हैं दोषी,
ये सबूत भी लाना है;
हम जिनको सत्ता में लाये,
छुरा उन्हींने भोंका है,
काले कानूनों की भट्ठी,
में हम सब को झोंका है;
किसको चुनें, किन्हें हम मत दें?
सारे ही यमदूत हैं;
बेहद दुःख है अब भारत में;
हम सब 'नए अछूत' हैं;

प्राण त्यागते हैं सीमा पर,
लड़ कर मरते हम ही हैं;
अपनी मेधा से भारत की,
सेवा करते हम ही हैं;
हर सवर्ण इस भारत माँ का,
एक अनमोल नगीना है;
अपने तो बच्चे बच्चे का,
छप्पन इंची सीना है;
भस्म हमारी महाकाल से,
लिपटी हुई भभूत है;
लेकिन दुःख है अब भारत में,
हम सब 'नए अछूत' हैं..

देकर खून पसीना अपना,
इस गुलशन को सींचा है;
डूबा देश रसातल में जब,
हमने बाहर खींचा है;
हमने ही भारत भूमि में,
धर्म-ध्वजा लहराई है;
सोच हमारी नभ को चूमे
बातों में गहराई है;
हम हैं त्यागी,हम बैरागी,
हम ही तो अवधूत हैं;
बेहद दुःख है अब भारत में,
हम सब 'नए अछूत' हैं...
योगी भी हो गया ढोंगी ।

मोदी नचा रहा ।
मुस्लिम वोटों के लिए, योगी।
योगी भी हो गया ढोंगी ।
भूल गया हिंदुत्व।
हो गया सत्ता भोगी।
अब दहाड़ खत्म हो गई ।
योगी की काया भी हो गई वोटों की रोगी।
सत्ता की मिमियाहट आ गई।
अपने ही संगी साथी
अब त्योहार नहीं मना सकते।
सत्ता का रोग लगते ही।
हिंदुओं को गले नहीं लगा सकते।
पाखंडी सन्यासी का चोला फेंक।
और फिर हिंदुओं का तमाशा देख।

भ्रष्टाचार और विदेशों से अनाप-शनाप खरीदी भी कारण है

डॉलर की कीमत बढ़ने में सबसे बड़ा कारण घोर भ्रष्टाचार

इसके पीछे का सच बहुत कड़वा है स्विट्जरलैंड ने हाल ही में भारत सरकार के साथ कांगेस के समय में किया गया अनुबंध तोड़ दिया है। जिसमें एक दूसरे देश को काले धन के संबंध में जानकारी देने के लिए समझौता किया गया था। स्विट्जरलैंड की सरकार ने बोला है कि जितना धन भारत से पिछले 60 सालों में आया था। उस का 50% काला धन पिछले 4 सालों में भारत की भाजपा सरकार के होते हुए पूंजीपतियों मंत्रियों नेताओं और अधिकारियों का आ गया है।

यह सिद्ध करता है कि वहाँ लगातार भ्रष्टाचार बढता रहा है और उन्हें अपने देश की चिंता कुछ भी नहीं है। अब मोदी और उसके भेड़ियों झुंड पार्टी के सभी नेता वित्त मंत्री अरुण जेटली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज व अन्य सभी के साथ जो की कांग्रेस के सरकार के समय में डालर की कीमत रू65 -67 होने पर चौराहों पर चिल्लाया करते थे ।

आज उनके शासनकाल में उसी की रुपए की कीमत $74 से ज्यादा हो चुकी है । अब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। जो कालाधन लगातार वहां से आ रहा है वह डालर मे परिवर्तित होकर स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा किया जा रहा है। इसलिए डॉलर की कीमत भारत में लगातार गिर रही है सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं है और सरकार ऐसी स्थिति में दिवालिया होने की कगार पर भी पहुंच सकती है।

मोहन करमचंद गांधी का महिमामंडन बकवास

मोहन करमचंद गांधी का कांग्रेसियों ने जिस तरह से महिमामंडन कर देश पर शासन किया है ।

बिल्कुल बकवास था ।

मोहन करमचंद गांधी जिसने देश के टुकड़े करवाए। घोर अय्याश, घोर स्वार्थी, और मक्कार किस्म का व्यक्ति था। उसने आजादी के लिए काम करने की अपेक्षा देश के आजादी में शहीद होने वालों को मरवाने में भी भरपूर सहयोग दिया।

वह अंग्रेजों का एजेंट था। आजादी गांधी के कारण नहीं देश की आजादी देश पर बलिदान होने वाले शहीदों जिन्होंने आजादी प्राप्त करने के लिए 1810-20 से लेकर 1947 तक लगातार लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिया और इस हरामखोर जाल साज ने फिर भी देश को पूर्ण आजादी की अपेक्षा पट्टे की आजादी पर हस्ताक्षर कर इस देश को 99 साल की पट्टे की आजादी दिलवाई ।

इसलिए वह कहीं से भी आदरणीय माननीय और पूजनीय नहीं। इसलिए देश की उसकी ना तो बिल्कुल आजादी के नायक के रूप में पूजा करें ।

वैसे भी कांग्रेस की सरकार नहीं जो उसके महिमामंडन को स्वीकार करना हमारी बाध्यता हो।

देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से लेकर 1945 तक ब्रिटेन पूर्ण रुप से दिवालिया हो चुका था।

इसलिए 65 देशों में उसकी औकात नहीं थी कि वह अपनी सेनाओं को वित्तीय सहायता देकर पाल सके ।

दूसरी तरफ अंग्रेजों ने जो भारतीय सेना के नायकों को आश्वासन दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के उपरांत देश को आजाद कर दिया जाएगा जब उन्होंने 1946 में इस बात से मना कर दिया तब मुंबई नेवी के भारतीय सैनिकों ने 300 से ज्यादा अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और ढाई सौ से ज्यादा जल सेना नौकाओं पर कब्जा कर लिया।

तब अंग्रेज बुरी तरीके से भयभीत और वित्तीय रूप से परेशान हो जाने के कारण उन्होंने देश को आजाद करने का निर्णय ले लिया था। परंतु उसके पाले हुए गांधी, नेहरू, जिन्ना जिन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की डिग्रियां प्राप्त की थी ।

उन्हें कानूनों के चक्कर में बांधकर आजादी के नाम पर पट्टा लिख कर दे दिया। इससे देश 14 अगस्त 2046 को पट्टा खत्म हो चुका होगा। इसके बाद है देश पुनः अंग्रेजों का गुलाम होगा इसकी पुष्टि गूगल पर जाकर भारतीय आजादी का दस्तावेज और सत्ता का हस्तांतरण 14 अगस्त 1947 को पढ़ सकते हैं जो कि गूगल भी पूरा नहीं बताता।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

केरल में पूरी तरह से हिंदुओं को साफ करने का षड्यंत्र अंतरराष्ट्रीय ईसाई मिशनरियों का

हिंदू महिलाओं का नहीं सबरीमाला मंदिर में महिला प्रवेश कराने का दुष्चक्र

सबरीमाला मंदिर में भगवान अय्यप्पा का एकमात्र साक्षात मंदिर है जिसमें बिना जाति और धर्म के कोई भी दीक्षा लेकर और उनके नियम धर्म के साथ विधि पूरी करने के बाद स्वामी बन सकता है। यही स्वामी बनने की प्रक्रिया के कारण धर्मांतरण से ईसाई बने सैंकड़ों हिंदू बन गए। यह बात ईसाई मिशनरियों को काफी नागवार गुजरी है। इसलिए वह ईसाई और मुस्लिम महिलाएं जिनके नाम हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। उन्होंने ही सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दायर कर, और अंतरराष्ट्रीय ईसाई मिशनरियों की तरफ से प्राप्त करोड़ों का धन को खर्च कर यह प्रवेश के लिए आदेशति करवाया है।

आखिर क्यों है सबरीमाला मंदिर ईसाइयों मुस्लिमों के निशाने पर

केरल में सबरीमला के मशहूर स्वामी अयप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के नाम पर चल रहे विवाद के बीच लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है कि ईसाई और इस्लाम धर्मों को मानने वाले तथाकथित एक्टिविस्ट भी कम से कम एक बार यहां घुसने को बेताब हैं। इस बात को समझने के लिए हमें केरल के इतिहास और यहां इस्लामी और राज्य में बीते 4-5 दशक से चल रही ईसाई धर्मांतरण की कोशिशों को भी समझना होगा। मंदिर में प्रवेश पाने के पीछे नीयत धार्मिक नहीं, बल्कि यहां के लोगों की सदियों पुरानी धार्मिक आस्था को तोड़ना है, ताकि इस पूरे इलाके में बसे लाखों हिंदुओं को ईसाई और इस्लाम जैसे अब्राहमिक धर्मों में लाया जा सके। केरल में चल रहे धर्मांतरण अभियानों में सबरीमला मंदिर बहुत बड़ी रुकावट बनकर खड़ा है। पिछले कुछ समय से इसकी पवित्रता और इसे लेकर स्थानीय लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का काम चल रहा था। लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। लेकिन आखिरकार महिलाओं के मुद्दे पर ईसाई मिशनरियों ने न सिर्फ सबरीमला के अयप्पा मंदिर बल्कि पूरे केरल में हिंदू धर्म के खात्मे के लिए सबसे बड़ी चाल चल दी है।

इतिहास को समझिए

1980 से पहले तक सबरीमला के स्वामी अयप्पा मंदिर के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। केरल और कुछ आसपास के इलाकों में बसने वाले लोग यहां के भक्त थे। 70 और 80 के दशक का यही वो समय था जब केरल में ईसाई मिशनरियों ने सबसे मजबूती के साथ पैर जमाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने सबसे पहला निशाना गरीबों और अनुसूचित जाति के लोगों को बनाया। इस दौरान बड़े पैमाने पर यहां लोगों को ईसाई बनाया गया। इसके बावजूद लोगों की मंदिर में आस्था बनी रही। इसका बड़ा कारण यह था कि मंदिर में पूजा की एक तय विधि थी। जिसके तहत दीक्षा आधारित व्रत रखना जरूरी था। सबरीमला उन मंदिरों में से है जहां पूजा पर किसी जाति का विशेषाधिकार नहीं। किसी भी जाति का हिंदू पूरे विधि-विधान के साथ व्रत का पालन करके मंदिर में प्रवेश पा सकता था। सबरीमला में स्वामी अयप्पा को जागृत देवता माना जाता है। यहां पूजा में जाति विहीन व्यवस्था का नतीजा है कि इलाके के दलितों और आदिवासियों के बीच मंदिर को लेकर अटूट आस्था है। मान्यता है कि मंदिर में पूरे विधि-विधान से पूजा करने वालों को मकर संक्रांति के दिन एक विशेष चंद्रमा के दर्शन होते हैं। जो लोग व्रत को ठीक ढंग से नहीं पूरा करते उन्हें यह दर्शन नहीं होते। जिसे एक बार इस चंद्रमा के दर्शन हो गए माना जाता है कि उसके पिछले सभी पाप धुल जाते हैं।

आया सामाजिक बदलाव

सबरीमला मंदिर की पूजा विधि देश के बाकी मंदिरों से काफी अलग और कठिन है। यहां दो मुट्ठी चावल के साथ दीक्षा दी जाती है। इस दौरान रुद्राक्ष जैसी एक माला पहननी होती है। साधक को रोज मंत्रों का जाप करना होता है। इस दौरान वो काले कपड़े पहनता है। जमीन पर सोता है। जिस किसी को यह दीक्षा दी जाती है उसे स्वामी कहा जाता है। यानी अगर कोई रिक्शावाला दीक्षा ले तो उसे रिक्शेवाला बुलाना पाप होगा। इसके बजाय वो स्वामी कहलाएगा। इस परंपरा ने एक तरह से सामाजिक क्रांति का रूप ले लिया। मेहनतकश मजदूरी करने वाले और कमजोर तबकों के लाखों-करोड़ों लोगों ने मंदिर में दीक्षा ली और वो स्वामी कहलाए। ऐसे लोगों का समाज में बहुत ऊंचा स्थान माना जाता है। यानी यह मंदिर एक तरह से जाति-पाति को तोड़कर भगवान के हर साधक को वो उच्च स्थान देने का काम कर रहा था जो कोई दूसरी संवैधानिक व्यवस्था कभी नहीं कर सकती।

मिशनरियों के लिए मुश्किल

सबरीमला मंदिर में समाज के कमजोर तबकों की एंट्री और वहां से हो रहे सामाजिक बदलाव ने ईसाई मिशनरियों के कान खड़े कर दिए। उन्होंने पाया कि जिन लोगों को उन्होंने धर्मांतरित करके ईसाई बना लिया वो भी स्वामी अयप्पा में आस्था रखते हैं और कई ने ईसाई धर्म को त्यागकर वापस सबरीमला मंदिर में 'स्वामी' के तौर पर दीक्षा ले ली। यही कारण है कि ये मंदिर ईसाई मिशनरियों की आंखों में लंबे समय से खटक रहा था। अमिताभ बच्चन, येशुदास जैसे कई बड़े लोगों ने भी स्वामी अयप्पा की दीक्षा ली। इन सभी ने भी मंदिर में रहकर दो मुट्ठी चावल के साथ दीक्षा ली। इस दौरान उन्होंने चप्पल पहनना मना होता था। और उन्हें भी उन्हीं रास्तों से गुजरना होता था जहां उनके साथ कोई रिक्शेवाला, कोई जूते-चप्पल बनाने वाला स्वामी चल रहा होता था। नतीजा यह हुआ कि ईसाई संगठनों ने सबरीमला मंदिर के आसपास चर्च में भी मकर संक्रांति के दिन फर्जी तौर पर 'चंद्र दर्शन' कार्यक्रम आयोजित कराए जाने लगे। ईसाई धर्म के इस फर्जीवाड़े के बावजूद सबरीमला मंदिर की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। यह याचिका हिंदू नाम वाले कुछ ईसाइयों और एक मुसलमान की तरफ से डलवाई गई।

1980 में मंदिर के बगीचे में ईसाई मिशनरियों ने रातों रात एक क्रॉस गाड़ दिया था !

उन्होंने इलाके में परचे बांट कर दावा किया कि यह 2000 साल पुराना सेंट थॉमस का क्रॉस है। इसलिए यहां पर एक चर्च बनाया जाना चाहिए। उस वक्त आरएसएस के नेता जे शिशुपालन ने इस क्रॉस को हटाने के लिए आंदोलन छेड़ा था और वो इसमें सफल भी हुए। इस आंदोलन के बदले में राज्य सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया।

हिंदुओं पर सबसे बड़ा हमला

केरल के हिंदुओं के लिए यह इतना बड़ा मसला इसलिए है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ में नीयत क्या है। राज्य में हिंदू धर्म को बचाने का उनके लिए यह आखिरी मौका है। केरल में गैर-हिंदू आबादी तेजी के साथ बढ़ते हुए 35 फीसदी से भी अधिक हो चुकी है। अगर सबरीमला की पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया गया तो ईसाई मिशनरियां प्रचार करेंगी कि भगवान अयप्पा में कोई शक्ति नहीं है और वो अब अशुद्ध हो चुके है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और कांग्रेसी नेता देखें

कब होगा घोर भ्रष्ट लंबे समय से बैठे अधिकारियों का स्थानांतरण

जो अगले चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनकर अपने संबंधों से चुनावों को प्रभावित करेंगे

चुनाव आयोग वैसे तो घोषणाएं करता है ईमानदारी से चुनाव करवाने की परंतु इसके विपरीत आईएएस स्तर के अधिकारी वर्षों तक एक ही स्थान पर शुद्ध कुंडली मारे बैठे रहते हैं। जैसे की वर्तमान में आकाश त्रिपाठी जोकि पूर्व मे इंदौर का सन 2012 से कलेक्टर था। सन 2015 इंदौर में ही पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का प्रबंध संचालक बन कर बैठा हुआ है। वही हाल उस समय के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में बैठा आशीष सिंह वर्तमान में इंदौर निगम आयुक्त बनकर बैठा है आखैरि दोनों चुनाव में भाग लेंगे ही ।उप जिलाधीश संदीप सोनी, संतोष टैगोर, आदि भी बरसों से इंदौर में कुंडली मारे बैठे हुए हैं जो कि सभी चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। सभी के पुराने संबंध कांग्रेसियों और भाजपा के सभी नेताओं से हैं। स्वाभाविक है सभी चुनावो को प्रभावित करेंगे ही। वही हाल मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल में घोर भ्रष्ट 50करोड से ज्यादा की संपत्ति के मालिक कार्यपालन यंत्री मनोज शिवाले और मनोज श्रीवास्तव पिछले 30 सालों से इंदौर में ही 1985 से डटे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग में 10 से ज्यादा बैठे हुए अधिकांश सहायक व उपयंत्री जो पिछले 10 साल से ज्यादा समय से इंदौर में ही बैठे हुए हैं। जिसमें पंकज तिवारी जो उपयंत्री है परंतु सहायक यंत्री के प्रभार में बैठकर लोक निर्माण विभाग के संभाग एक में पिछले 8 वर्षों से भारी जालसाजी करते हुए अपने खास ठेकेदारों से काम करवा कर करोड़पति बस का चंदन लगा रहा है। वही हाल सहायक यंत्री अभय राज दुबे जो 10 वर्षों से इंदौर में ही बैठा हुआ है उसका भी है।

वही हाल मध्य प्रदेश जल संसाधन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, नर्मदा घाटी , गृह एवं ग्राम निवेश, औद्योगिक केंद्र विकास निगम, मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, कृषि, उद्यानकी, महिला बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, खाद्य एवं औषधि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खनिज विभाग, मंडी, मध्य प्रदेश वाणिज्य कर में 20 से ज्यादा अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भू अभिलेख, शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग , स्वास्थ्य, वन विभाग, आदि में बरसों से कुंडली मारे सैकडौ अधिकारी बैठे हुए इनके संबंध कांग्रेस भाजपा के सभी नेताओं विधायकों पार्षदों आदि से बरसों से जुड़े हुए हैं चुनावों को प्रभावित करेंगे ही यह हाल इंदौर का ही नहीं उज्जैन देवास धार भोपाल ग्वालियर से लेकर पूरे मध्यप्रदेश का है परंतु चुनाव आयुक्त सब जानने के बावजूद चुप बैठा हुआ है क्या ऐसे ही इमानदारी से चुनाव होंगे

यह सारे अधिकारी अपने बड़े आकाओ, नेताओं, मंत्रियों को भ्रष्टाचार की लूट में से कुछ इस साल उठाकर भारी चहेते बने बरसों से एक ही स्थान पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं जो निम्नानुसार है।

इसी प्रकार सहायक परियोजना संचालक खरात जो परियोजना क्रियान्वयन इकाई में भी 5 वर्ष से इंदौर में ही बैठा हुआ है। सहायक यंत्री आलोक जैन 10 सालों से मुख्य अभियंता कार्यालय इंदौर में है। पूरे मध्यप्रदेश में 50 से ज्यादा सहायक यंत्री एक ही स्थान पर 5 वर्षों से ज्यादा एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। जो अगले चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनकर चुनाव को प्रभावित करेंगे।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय मैं नगर निगम संभाग2 इंदौर में पिछले 5 साल से ज्यादा समय कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव बैठा हुआ है पिछले 8 साल से ज्यादा समय से कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी चेतन रघुवंशी, उज्जैन में कार्यपालन यंत्री उदयि उज्जैन ग्रामीण, संतोष श्रीवास्तव खरगोन, अधीक्षण यंत्री रत्नावत इंदौर उज्जैन संभाग, धार कार्यपालन यंत्री राजीव खुराना 5 साल से ज्यादा समय से डटे हुए हैं । पूरे मध्यप्रदेश में 15 से ज्यादा कार्यपालन यंत्री 5 साल से ज्यादा समय से, 40 से ज्यादा सहायक इंजीनियर 5 साल से ज्यादा समय एक ही स्थान पर एक ही जिले में बैठे हुए हैं। रीवा में बैठा फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाला विद्युत यांत्रिकी कार्यपालन यंत्री बोरखेड़े, सन 2012 से।

जल संसाधन में, 20 साल से ज्यादा समय से ही खरगोन मैं बैठा अधीक्षण यंत्री भगोरा 1992 से पहले सहायक यंत्री, 2002 तक, बाद में कार्यपालन यंत्री सन 2012 तक और अब अधीक्षण यंत्री 6 साल से खरगोन में ही पदस्थबैठा हुआ है। भारी भ्रष्ट और शासन को अरबों रुपए का चूना लगा चुका है। डॉक्टर सरल जो पिछले 20 सालों से देवास में ही पदस्थ हैं । वर्तमान में सीएमओ देवास है। और वर्तमान में वहां के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है । कि एनआरएचएम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना व अन्य केंद्र शासन की 15 से ज्यादा योजनाओं में और राज्य शासन की 12 से ज्यादा योजनाओं में 120 से डेढ़ सौ करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होती है हर वर्ष।

हर जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी केंद्र शासन की 15 से ज्यादा योजनाओं और राज्य शासन की 20 से ज्यादा योजनाओ का जो हर वर्ष 200 से 300 करोड़ के बीच में आता है उसका 15 से 20 प्रतिशत डकार ने के साथ, जिले के अंतर्गत शहरो की पैथोलैब, ब्लड बैंक निजी नर्सिंग होम दवा दुकानों खाद्य आदि की दुकानों से भी मोटी वसूली की जाती है इसलिए हर मु चि अ स्वास्थ्य मंत्री को मोटा धन देकर ही बैठा है इसलिए यह हरामखोर जानकारी सूचना के अधिकार में देना पसंद नहीं करते। आप और इसी दम पर वर्षों तक अधिकांश डॉक्टर खाद एवं औषधि निरीक्षक एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। नर्मदा घाटी में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा मीणा, पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से ही पुनासा ओर नर्मदा नगर में बैठकर सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार कर चुका है।

गुलाम की औलाद

ना तू हिंदू रहेगा.
ना मुसलमान रहेगा .
गुलाम की औलाद है .
गुलाम रहेगा .
तेरे पास न अपनी अक्ल है.
न समझ है, न बुद्धि है.
दिखने का तू इंसान है.
देखने का ही इंसान रहेगा.
श्वानों से बदतर है।
न अपना, परिवार का, समाज का,
देश का गुजरा व
आने कल की सोच व समझ है ।
न देशप्रेम है.
न मान है. न आत्मसम्मान है.
हजारों साल से गुलाम है।
गुलामी में ही खुश रहेगा।
तू देखने का इंसान रहेगा.
तू कभी मन के राग गाएगा।
कभी धूर्तो लाबरा मोदी शिव के
झांसे में आएगा।
ये सब लूटेंगे तुझ ही को।
तुझ पर लुटाने का,
अनुदान बांटने का,
सस्ता गेहूं, बिजली बांटने का,
भावांतर, साइकिल, लेपटाप,
मोबाइल मुफ्त बांटने का,
ये सब धूर्त ढोंगी पाखंडी
लुटाने का ढोंग करेंगे ।
तुझ से बैंको में लालच देकर
खाते खुलवा, गैस अनुदान
तेरी मेहनत का भी
लाखों करोड़ न्युन शेष मे हजम
किया, करेंगे।
ये भी तेरी तरह जन्मे हैं।
देश को बेंच, गुलाम बना
तो निश्चित ही जनता को और
आने वाली पीढ़ीयों को
अपनी मौज मस्ती मे
जनता को भिखारी बना कर ही
अचानक ही अकाल मौत मरेंगें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, आम्बेडकर नगर इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 94256-37958, इंदौर। मोबा. 94251-25569, 9479535569